चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

07 अक्टूबर–14 अक्टूबर 2013

भारत में पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का तमगा हासिल है. लेकिन कुछ संस्थानों ने इसे अपने हितों को साधने के लिए माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया और चौथे स्तंभ की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई. ऐसे वाक़ए भी हैं, जब पत्रकारिता के महानायक बनते सख़्श कई बार महाअपराधी नायक की श्रेणी में बदल जाते हैं और उनका पूरा व्यक्तित्व भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े बेशर्म इन्सान के रूप में तब्दील हो जाता है. यह घटनाएं *जब तोप मुक़ाबिल हो तो अख़बार निकालो* जैसे जुमले को ग़लत साबित करती हैं और भारतीय पत्रकारिता के चेहरे पर स्याह निशान छोड़ जाती हैं...

यह पत्रकारिता नहीं देशद्रोह है

संतोष भारतीय

ये कहानी भारतीय पत्रकारिता के उस काले चेहरे की कहानी है, जिस चेहरे को स्वर्गीय रामनाथ गोयनका शायद स्वर्ग में बैठकर कभी पढ़ना नहीं चाहेंगे या कभी जानना नहीं चाहेंगे. देश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझसे कहा कि अगर आज श्री रामनाथ गोयनका ज़िंदा होते, तो या तो अपने संपादक को बर्ख़ास्त कर देते और अगर नहीं कर पाते तो बंबई के एक्सप्रेस टावर के पेंट हाउस से नीचे छलांग लगाकर अपनी जान दे देते. स्वर्गीय श्री रामनाथ गोयनका ने जिस आदर्श को छुआ था, वो आदर्श प्रो–पीपुल जर्नलिज़्म का अद्भुत उदाहरण था. रामनाथ गोयनका ने अपने अख़बार के ज़रिये भारतीय पत्रकारिता की ऐसी ऊंचाइयां छुई थीं, जिनका लोग हमेशा उदाहरण देते थे. उन्होंने कभी हथियारों के दलालों, पूंजीपतियों, सत्ताधीशों के पक्ष की पत्रकारिता नहीं होने दी. इसीलिए उनके समय के संपादकों के नाम भारतीय पत्रकारिता के इतिहास के जगमगाते हुए पन्ने हैं.

लेकिन आज क्या हो रहा है. विवेक गोयनका रामनाथ गोयनका के उत्तराधिकारी हैं. विवेक गोयनका अपने अंग्रेज़ी अख़बार में पत्रकारिता के आदर्शों की धज्जियां उड़ते हुए देखकर अगर चुप हैं, तो इसका मतलब है कि विवेक गोयनका में रामनाथ गोयनका का अंशमात्र भी, सम्मान के लिए लड़ने की ताकत का अंश नहीं बचा है. ये पत्रकारिता जर्नलिज़्म ऑफ़ करेज नहीं है, जर्नलिज़्म ऑफ़ करप्शन है, जर्नलिज़्म ऑफ़ दलाली है, जर्नलिज़्म ऑफ़ ऐंटीनेशनलिज़्म है.

ये सख़्त शब्द हमें इसलिए कहने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक समय पत्रकारिता के महानायक के पद पर बैठा हुआ शख़्स अगर अपराध–नायक बनने की तरफ़ बढ़ने लगे और सत्ता में बैठे अपने दोस्तों के ज़रिये पैसे कमाने लगे और अख़बार का इस्तेमाल देशद्रोही ताक़तों को मदद पहुंचाने के लिए करने लगे, तो लिखना ज़रूरी हो जाता है. ये कहानी भारतीय पत्रकारिता के दूसरे अख़बारों के संकोच की कहानी भी है, कम हिम्मत की कहानी भी है और हमारे आज के राजनीतिक दौर में किस तरह देशप्रेम, देशभक्ति एक तरफ़ रख दी जाती है और किस तरह देशद्रोह को आदर्श मान लिया जाता है, उसकी कहानी भी है.

ये कहानी शुरू होती है, जब जनरल वी के सिंह भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष बने. जब जनरल वी के सिंह भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष बने थे, उस समय भारतीय सेना में ख़रीदे जाने वाले हर हथियार के पीछे हथियारों के सौदागरों की भूमिका थी. हथियारों से संबंधित लॉबी साउथ ब्लॉक में टहलती रहती थी. देश के कुछ बड़े नाम देश की सेना को सप्लाई होने वाले हर हथियार के ऊपर असर डालते थे. उनके पास रक्षा मंत्रालय से और भारत की सेना से जानकारियां पहुंच जाती थीं कि रक्षा बजट में हथियारों की ख़रीद का कितना प्रतिशत हिस्सा है और उसके हिसाब से वो योजना बनाने लगते थे. वो जानते थे कि युद्ध नहीं होने वाला है, इसलिए भारत की सेना को उन्होंने घटिया हथियारों की आपूर्ति की. भारतीय सेना हथियारों के दलालों के जाल में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाहे वो टाट्रा ट्रक हों, चाहे वो राइफलें हों, चाहे वो तोपें हों या चाहे गोला–बारूद हो, हर जगह सब–स्टैंडर्ड सामान भारत की सेना में आ रहा था. जनरल वी के सिंह ने इस स्थिति के ख़िलाफ़ कमर कसी और उन्होंने ऐसे नियम बनाने शुरू किए, जिन नियमों की वजह से हथियारों के दलालों को अपना काम करना मुश्किल लगने लगा. जनरल वी के सिंह द्वारा उठाए गए क़दमों ने उन लोगों को असहज कर दिया, जो लोग भारत की सेना को बेचे जाने वाले हथियारों से फ़ायदा उठाते थे.

ये रिपोर्ट, जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये रिपोर्ट न तो जनरल वी के सिंह ने हमें बताई और न ये रिपोर्ट सेना के देशभक्त अफसरों द्वारा लीक की गई. ये रिपोर्ट हमारी छानबीन का नतीजा है, जो हम भारत के पाठकों के सामने इस आशा से रख रहे हैं कि अगर भारत की जनता इस बात को जान जाएगी, तो कम से कम हम अपने उस कर्तव्य का पालन कर पाएंगे, जो एक पत्रकार को करना चाहिए. जनरल वी के सिंह से पहले जितने जनरल हुए, उन्होंने सेना के जवानों में या भारत की पूरी सेना में हौसला भरने का काम पूरे तौर पर नहीं किया. एक बार तो सेना में ये स्थिति आ गई थी कि मनोवैज्ञानिक रूप से सिपाही और अफसर आपस में ही लड़ने लगे थे. आठ महीने से ज़्यादा चीन बॉर्डर के ऊपर भारत की सेना बिना किसी लक्ष्य के बैठा दी गई थी. हमारी जानकारी के हिसाब से जब जनरल वी के सिंह भारत के सेनाधयक्ष बने, तो उनके सामने हथियारों के दलालों को रक्षा मंत्रालय में घुसने से रोकना एक काम था, वहीं दूसरा काम भारत की सीमाओं को भारत के पड़ोसियों से सुरक्षित रखना था. भारत में तीन तरफ़ की सीमाओं से घुसने के रास्ते बने हुए थे. आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ़ से, नेपाल की तरफ़ से और बांग्लादेश की तरफ़ से हिंदुस्तान में घुसते थे. कभी कुछ पकड़े जाते थे, कुछ मारे जाते थे, लेकिन ज़्यादातर घुस आते थे. जनरल वी के सिंह के सामने शायद ये बड़ा प्रश्न था कि हमारी सेना के ऊपर हमले न हों और हमारी सीमाएं चाक–चौबंद, सिपाहियों की निगरानी में हों. मुंबई हमले के बाद ऐसे किसी खतरे से निपटने के लिए रणनीति की जरूरत महसूस हुई और जनरल वी के सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की सलाह और रक्षा मंत्री के आदेश पर भारतीय सेना में एक जांबाज़ यूनिट बनाई, जिसका नाम टेक्निकल सर्विसेज डिवीज़न रखा. टीएसडी इस डिवीज़न का शॉर्ट नाम है, जिस तरह रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का शॉर्ट नाम रॉ है. रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमारे देश की ऐसी ख़ुफ़िया एजेंसी है, जो विदशों में काम करती है और विदेशी जानकारी भारत सरकार को देती है. विदेशों में भारत के हितों को लेकर जासूसी करना जिस तरह भारत का अधिकार है, उसी तरह से दूसरे देशों का अपने देश के लिए जासूसी करना उनका अधिकार है. उनके जासूस हमारे देश समेत कई देशों में बिखरे पड़े हैं और हमारे जासूस भी पड़ोसी देशों सहित कई देशों में बिखरे पड़े हैं. जासूस पकड़े भी जाते हैं, जासूस ख़बरें भी भेजते हैं, उन ख़बरों में जो देश की सुरक्षा से जुडी ख़बरें होती हैं, उन ख़बरों के ऊपर अमल होता है और बाक़ी ख़बरें रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं. जनरल वीके सिंह ने टीएसडी को इसी तर्ज पर बनाया. सेना की मजबूरी होती है कि वो तभी आगे बढ़ पाती है जब उसे आदेश मिलता है. लेकिन टीएसडी इस तर्ज पर बनाई गई कि हमारी सीमाएं भी सुरक्षित रहें और हमारी सेना भी सुरक्षित रहें. टीएसडी का टास्क, पाकिस्तान का बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर और इन बॉर्डर पर हमारे जवान, न पड़ोसी देशों के सेना के सीधे निशाने पर आएं और न इन देशों से होकर हमारे देश में घुसने वाले

(शेष पृष्ठ 2 पर)

जनरल वीके सिंह द्वारा किया गया ट्वीट

शेखर गुप्ता की कंपनी का डाटा: वे और उनकी पत्नी नीलम जॉली ने 2002 में ग्रीनपाइन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी शुरू की. ग्रीनपाइन पति–पत्नी द्वारा शुरू की गई कंपनी है. उनकी कंपनी कॉमनवेल्थ खेलों में भी भागीदारी कर रही थी.

सालों तक इसका कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ. 2003 से 2009 तक सारे रिकॉर्ड रिटर्न ऑन कैपिटल के साथ 2010 में दर्ज किए गए और चालू वर्ष मई 2010 में दर्ज किया गया.

शेखर गुप्ता ने ईईएस (इंटरप्राइज एम्प्लॉय सिनर्जी) जमा करके अगस्त, 2010 में कंपनी बंद कर दी. इसके बाद सभी अकांउट में हेरफेर कर दिया गया. 2002 में उन्होंने एक लोन लिया. यह मात्र 12 लाख रुपये का था, जबकि इस दौरान उन्होंने दो एकड़ के तीन फार्म खरीदे. अगस्त, 2010 में उन्होंने कंपनी बंद कर दी. बैलेंस सीट दिखाती है कि 2004 में उन्होंने 45 लाख का अनसेक्योर लोन लिया, लेकिन बाद में फार्म हाउस के मामले में बैलेंस सीट्स को साफ कर दिया गया.

तमाम खोजी रिपोर्ट छापने वाले संपादक ने आठ साल बाद 18 जनवरी, 2010 को एक बैलेंस सीट फाइल की.

दिल्ली में मालचा रोड पर 55 करोड़ का मकान (यह ज्यादा का भी हो सकता है) हो सकता है उन्हें यूपीए सरकार के लिए काम करने के लिए मिला हो. इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग कांग्रेस के निर्लज्ज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन पर झूठे आरोप लगाने के लिए शेखर गुप्ता इंडियन एक्सप्रेस को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं.

जीत आख़िर में सच्चाई की ही होगी 03

सीबीआई के शिकंजे में अमित शाह और नरेंद्र मोदी 04

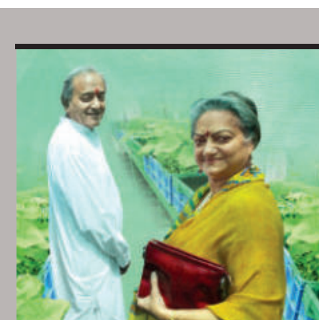
किसानों में जगाती उम्मीद 07

साईं की महिमा 12

यह पत्रकारिता नहीं देशद्रोह है

पृष्ठ एक का शेष

आतंकवादियों के निशाने पर आएं, ये इस डिवीज़न का टास्क था. इस डिवीज़न को यह आदेश नहीं था कि वो दूसरे देश में घुसकर कोई ऐक्शन ले. इस डिवीज़न की ज़िम्मेदारी थी कि वो हमारी सीमावर्ती हिस्से के आसपास अगर कोई गतिविधियां हो रहीं हैं तो उन गतिविधियों को रोकने में अपने जान की बाज़ी लगा दें, ताकि सेना तब तक चौबंद होकर, अगर उसे आदेश मिलता है तो अपने टास्क की पूर्ति करे.

टीएसडी की गतिविधियों से भारत में घुसपैठ कम हुई. जब टीएसडी की गतिविधियों की वजह से पाकिस्तान और चीन परेशान होने लगे, तो उन्होंने भारत में अपने एजेंटों से टीएसडी के बारे में जानकारी हासिल की. जनरल वीके सिंह ने टीएसडी को इस अंदाज में बनाया था कि टीएसडी के बारे में कोई जानकारी पाकिस्तान और चीन को नहीं मिल पा रही थी. टीएसडी है ये तो पता चल रहा था, लेकिन टीएसडी के कार्य करने की शैली, टीएसडी में कौन अफसर और जवान हैं, उनके टारगेट्स क्या-क्या क्या हैं. उनको ऑर्डर कौन देता है. उनके पास हथियार क्या-क्या हैं. इसको लेकर के पाकिस्तान और चीन में बहुत बडा भ्रम था. चूंकि उन्हें कोई जानकरी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उनके स्थानीय एजेंट उन दोनों सरकारों को डरा रहे थे. उन्होंने टीएसडी को एक हौवा बनाकर अपनी सरकारों को इसलिए बताया क्योंकि उनके पास सचमुच कोई ख़बर थी ही नहीं. पर उन्हें कोई न कोई ख़बर तो भेजनी ही थी.

टीएसडी पाकिस्तान और चीन के लिए एक डरावना हौवा बन गया और दोनों सरकारों को और दोनों सेनाओं को जब कुछ पता नहीं चला, तो इस बीच हथियारों के दलालों ने जनरल विजय कुमार सिंह की तस्वीर बर्बाद करने की सारी कोशिशें शुरू कर दीं. इन कोशिशों में जनरल वीके सिंह की उम्र का विवाद देश में उछाला गया. जनरल वीके सिंह की उम्र के विवाद की भी यह विडंबना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जनरल वीके सिंह के हाईस्कूल के सर्टीफिकेट में लिखी हुई उम्र प्रामाणिक नहीं मानता, लेकिन रेप केस में सबसे ज़्यादा रोल निभाने वाले एक अपराधी के बालिग या नाबालिग होने के विषय में हाईस्कूल के जन्म प्रमाणपत्र को सही मानता है. शायद भारत के सुप्रीम कोर्ट को ही ऐसा अंतर्विरोध शोभा देता है. जनता में इस फ़ैसले की थू-थू भी हुई, पर हथियारों के सौदागरों ने, जिनमें सेना के कुछ बड़े अफसर भी शामिल थे, कुछ राजनीतिक नेताओं का साथ लेकर एक अख़बार के ज़रिये इस मुद्दे पर जनरल वीके सिंह के ख़िलाफ़ अभियान चला दिया.

इस बीच जनरल वीके सिंह रिटायर हो गए, लेकिन जनरल वीके सिंह ने जो क़दम उठाए थे, उन क़दमों से सेना के भीतर हथियारों के दलालों का काम, जहां एक तरफ़ मुश्किल हुआ, वहीं अभी भी टीएसडी को लेकर पाकिस्तान और चीन के मन में भयानक डर बैठा हुआ था. वे किसी भी तरह से टीएसडी की जानकारी चाहते थे और टीएसडी को डिफंक्ट करना चाहते थे. रामनाथ गोयनका के इस अख़बार ने इस काम में हथियारों के दलालों की और पाकिस्तान तथा चीन की ज़बरदस्त मदद की. इस अखबार ने इस तरह की ख़बर अपने पहले पन्ने पर, पहली हेडिंग के साथ छापी कि जनरल वीके सिंह इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म कर सेना का शासन स्थापित करना चाहते थे. और जिसके लिए उन्होंने सेना की दो टुकड़ियों को दिल्ली की तरफ़ कूच करने का आदेश दे दिया था.

जनरल वीके सिंह इस ख़बर के छपने के समय सेना अध्यक्ष थे. और ये वार बहुत ख़तरनाक वार था. इस वार की असली कहानी यह है कि रामनाथ गोयनका जी के अख़बार के संपादक ढाई घंटे से ज़्यादा जनरल विजय कुमार सिंह के सरकारी आवास आर्मी हाउस में रहे, उनके साथ उन्होंने दोपहर का खाना खाया. एक-एक सवाल उन्होंने पूछा और सवाल पूछने के लिए उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार किया. उन्होंने कहा, कि उनका भारतीय सेना से काफ़ी पुराना रिश्ता है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो ये कहा कि उनके भाई भी सेना में हैं. अपने रिश्तेदारों के नाम गिनाए. किस कोर, किस डिवीज़न में हैं, इसके नाम गिनाए. कुछ कहानियां बताईं कि किस तरीक़े से उनके साथ सेना की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं. और इसके बाद उन्होंने इन ट्रूप्स के दिल्ली कूच करने की हकीक़त पूछी. जनरल वीके सिंह ने उन्हें एक-एक चीज़ बताई कि किस तरह की यह रूटीन एक्सरसाइज़ है और दिल्ली के आसपास कुछ टुकड़ियां इसलिए रहती हैं, ताकि अगर दिल्ली में कहीं कुछ हो जाए, जैसे बंबई में 26-11 को हुआ था, तो सेना की टुकडियां इतनी दूर पर रहें कि वो दो घंटे के भीतर दिल्ली पहुंच सकें. और टाइम-टू-टाइम ये एक्सरसाइज होती रहती है कि अगर दिल्ली में कुछ होता है तो राजधानी को बचाने के लिए सेना कितनी तेज़ी से स्ट्राइक कर सकती है. और ये हर मौसम में होता है. चाहे गर्मी हो, बरसात हो, धुंध हो. उस बार की एक्सरसाइज धुंध में हुई थी. लेकिन दूसरे दिन, एक दिन छोड़कर उसके अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस के महान संपादक शेखर गुप्ता ने अपने एक रिपोर्टर के नाम से स्टोरी छापी कि भारत की सेना जनरल वीके सिंह के आदेश पर सत्ता पर कब्ज़ा करना चाहती है. रामनाथ गोयनका के वारिस विवेक गोयनका के अख़बार में तख़्तापलट की कोशिश के बारे में जब रिपोर्ट छपी तो उसका सबसे काला अध्याय ये था कि इसके संपादक ने ये नहीं बताया कि वो कुछ घंटे पहले भारत के सेनाध्यक्ष के साथ दोपहर का खाना खाकर आया है और उसने ये सारे सवाल भारत के सेनाध्यक्ष से पूछे और सेनाध्यक्ष ने न केवल उनका खंडन किया, बल्कि विस्तार से बताया कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं. अगर संपादक, जिसे ये सारी जानकारी संबंधित व्यक्ति से मिली थी, तो उस रिपोर्ट में ये लिख सकता था कि हमारा ये मानना है कि तख़्तापलट की कोशिश हुई, लेकिन भारत के सेनाध्यक्ष ने इससे सिरे से इन्कार किया और आर्मी की कंपनियों के मूवमेंट के भी कारण बताए. ये न लिखना इस अख़बार की पत्रकारिता के सिद्धांतों को तिलांजलि देना है और ये जर्नलिज़्म ऑफ कावर्डनेस, जर्नलिज़्म ऑफ झूठ, जर्नलिज़्म ऑफ करप्शन, जर्नलिज़्म ऑफ एंटीनेशनलिज़्म कहलाता है या कहा जा सकता है.

इस रिपोर्ट को सरकार ने हास्यास्पद क़रार दिया. विपक्ष ने हास्यास्पद क़रार दिया. सेना के रिटायर्ड जनरलों ने हास्यास्पद क़रार दिया. लेकिन ये अख़बार इतना बेशर्म हो गया कि उसने इस रिपोर्ट पर माफ़ी तक नहीं मांगी. एक सबूत अख़बार के पास नहीं और अख़बार ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को समाप्त करने की सेना की साज़िश की ख़बर भारत में फ़ैला दी. हर तरफ़ इस रिपोर्ट को लेकर थू-थू हुई. लेकिन ये अख़बार अपनी इस रिपोर्ट पर क़ायम रहा. मज़े की चीज़ ये है कि इस अख़बार ने भारत के राजनीतिक तंत्र के उन लोगों के नाम नहीं छापे, जिन्होंने उसकी इतनी बड़ी रिपोर्ट छपने के बाद क्यों सेना के उन अफसरों के ऊपर और जनरल वीके सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने अख़बार के अनुसार दिल्ली की सत्ता पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी? क्या इस तख़्तापलट की योजना में ख़ुद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री शामिल थे? अपने ही ख़िलाफ़ वो कुछ करना चाहते थे? या वो इतने ग़ैर-ज़िम्मेदार प्रधानमंत्री और गृहमंत्री थे, जिन्होंने इतनी बड़ी रिपोर्ट के छपने के बाद कुछ नहीं किया?

दरअसल, आज़ाद हिंदुस्तान की ये सबसे घटिया और सनसनीख़ेज रिपोर्ट थी. सनसनीख़ेज इस मामले में, क्योंकि ये पूरी तौर पर हथियारों के दलालों और इस अख़बार के विदेशी संपर्कों के इशारे पर लिखी हुई भारत की सेना को बेइज़्ज़त करने वाली रिपोर्ट थी.

»» **यह रिपोर्ट भारतीय सेना के जवानों को मारने के षडयंत्र का हिस्सा है. इसलिए श्री रामनाथ गोयनका के वारिस विवेक गोयनका के अख़बार की इस रिपोर्ट का हम जमकर विरोध करते हैं और इसे भारतीय पत्रकारिता की सबसे काली रिपोर्ट के रूप में देखते हैं. पत्रकारिता का महानायक बनता हुए एक सख़्श कैसे महाअपराधी नायक की श्रेणी में बदल जाता है और कैसे उसका पूरा व्यक्तित्व भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े बेशर्म इन्सान के रूप में तब्दील हो जाता है, इस अख़बार को पढ़कर देखा जा सकता है.** »»

इसके बाद, इस अख़बार ने टीएसडी का सवाल उठाया. मूर्खता भरी रिपोर्ट विवेक गोयनका का अख़बार ही छाप सकता है, जिसने लिखा कि जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार को उखाड़ने के लिए एक करोड़ 19 लाख की रिश्वत जम्मू-कश्मीर के एक मंत्री को दी गई. भारत के एक मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने साहसिक काम किया और उन्होंने कहा, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, न कोई राज्य सरकार को उखाड़ने की कोशिश हुई है और यह रिपोर्ट ठीक वैसी ही हास्यास्पद और बेसलेस है, जैसी भारत की सत्ता पर सेना के कब्ज़ा करने की रिपोर्ट थी और ये दोनों रिपोर्ट एक ही अख़बार ने छापी. आख़िर ये रिपोर्ट रामनाथ गोयनका के वारिस विवेक गोयनका के अख़बार में ही क्यों छप रही हैं? इसलिए छप रही हैं, क्योंकि इस अख़बार के संपादक और इस अख़बार के पत्रकारों के रिश्ते हथियारों के दलालों से हैं. इनके रिश्ते चीन और पाकिस्तान की उन ताक़तों से हैं, जो टीएसडी से भयभीत थे. इन्होंने दबाव डालकर टीएसडी को बंद करने का फ़ैसला करवाया. टीएसडी के बंद होने के फ़ैसले ने ही इन्हें संतुष्ट नहीं किया. ये टीएसडी में कौन-कौन अफसर और जवान शामिल थे, उनके नाम जानना चाहते थे और ये अख़बार देशद्रोही गतिविधियों का ऐसा हिस्सा बन गया कि वह हमारे जवान और अफसरों की जान का दुश्मन बन गया. वो इन सारी चीज़ों के ख़ुलासे की मांग करने लगा, ताकि अफसरों की और टीएसडी में शामिल सभी लोगों की कार्यप्रणाली भी सामने आए, उनके नाम भी सामने आएं ताकि आसानी के साथ पाकिस्तान और चीन के जासूस उनकी हत्या कर दें. विवेक गोयनका के इस अख़बार ने देशद्रोही पत्रकारिता की ये सर्वोच्च मिसाल कायम की. भारत सरकार के मंत्रियों में भी, हथियारों के दलालों से और उन दलालों के ज़रिये चीन और पाकिस्तान से रिश्ता रखने वाले कुछ मंत्रियों का एक ग्रुप है, जो ग्रुप टीएसडी को लेकर और जनरल वीके सिंह द्वारा बनाए गए नियमों को समाप्त करवाना चाहता है. ये अख़बार, अख़बार के संपादक इस गिरोह के कोर कमेटी का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं.

कुछ आंकड़े गौर करने लायक हैं. जनरल वी के सिंह के कार्यकाल के दौरान ही मुंबई का 26/11 का मशहूर कांड हुआ, जिसमें ताज होटल में आतंकियों ने एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया था. इस समय की एक घटना और बताते हैं. कोलकाता से कुछ सिमकार्ड खरीद गए. कोलकाता के मिलिट्री इंटेलीजेंस को पता चला कि कुछ लोगों ने सिमकार्ड ख़रीदे हैं और हिंदुस्तान में कहीं पर कोई वारदात होने वाली है, जिनमें इन सिमकार्डों का इस्तेमाल होने वाला है. वो जानकारी सर्वोच्च स्तर पर भारत के तत्कालीन इंटेलीजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को दी गई. इन दोनों ने इस जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि इन सिमकार्डों के नंबर तक सेना ने मुहैया करा दिए थे. जब 26/11 घटित हो गया और फोन के ऊपर बातचीत इंटरसेप्ट हुई तो ये वही नंबर थे, जो सेना ने डायरेक्टर ऑफ इंटेलीजेंस ब्यूरो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को मुहैया कराए थे. और जो उस समय सबसे बड़ी चूक हुई, जिसके ऊपर भारतीय सेना को आज तक अफ़सोस है कि भारत के पास इतने जैमर हैं, लेकिन उन 24 घंटों के दौरान जब ताज होटल में आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहे थे, कम्युनिकेशन जाम नहीं किया गया. अगर कम्युनिकेशन जाम हो जाता तो पाकिस्तान से आतंकवादियों को निर्देश नहीं मिल पाते, क्योंकि वे सेटेलाइट फोन नहीं थे. सेटेलाइट फोन भी जाम किए जा सकते हैं, लेकिन उसे जाम करने में थोड़ा वक़्त लगता है. लेकिन अपने हिंदुस्तान के टॉवर से जाने वाले इंडियन सिमकार्ड से होने वाली बातचीत फौरन जाम की जा सकती है. यह जाम क्यों नहीं किया गया, अभी तक ये रहस्य बना हुआ है. अगर जाम कर दिया गया होता तो मुठभेड़ इतनी देर तक चलती ही नहीं.

जनरल वी के सिंह जब तक भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष रहे, देश में आईएसआई की गतिविधियां नियंत्रित रहीं, क्योंकि आईएसआई को भारत की सेना के टीएसडी डिवीज़न से डर था. जनरल वी के सिंह के समय हमारी सीमाओं पर शांति रही. चाहे पाकिस्तान के सैनिक हों या चीन के, उन्होंने कोई हरकत करने की कोशिश नहीं की. क्योंकि उन्हें जनरल वी के सिंह से भी डर था और जनरल वी के सिंह द्वारा बनाए गए दस्तों से भी डर था. इसीलिए जैसे ही वी के सिंह हटे, हमारी सीमा पर युद्धविराम तोड़ने की कोशिश हुई. आतंकवादी भेजे जाने लगे और हमारे जवानों की सिरकटी लाशें देश में आने लगीं. चीन की सीमा पर चीन टहलता हुआ लद्दाख और अरुणाचल में घूमने लगा. हमारी सेना की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई. कार्रवाई हो भी नहीं सकती, जब तक राजनीतिक फैसला न लिया जाए. लेकिन चीन को कोई डर ही नहीं था, उन्हें यह भी पता कि अब भारतीय सेना स्ट्राइक नहीं करेगी, क्योंकि टीएसडी डिवीज़न जो सेना के ऑफिसियल स्ट्राइक करने से पहले अपनी सेना की तरफ़ बढ़ने वाले क़दमों को रोकने के लिए ढाल का काम करती थी, वह अब है ही नहीं. जो काम चीन और पाकिस्तान ख़ुद नहीं करवा सके, उन्होंने भारत के पत्रकारिता के आदर्श रहे रामनाथ गोयनका के वारिस विवेक गोयनका के इस अख़बार के द्वारा करवा दिया. कहा तो यह भी जा रहा है कि इस अख़बार के संपादक सहित अन्य लोगों का उठना बैठना उस समय के गृहमंत्री के साथ काफ़ी ज्यादा था और इन सारी चीज़ों के पीछे तत्कालीन गृहमंत्री के इशारे, हथियारों के दलालों के सीधे हस्तक्षेप और पाकिस्तान और चीन के हितों में काम करने वाले हिंदुस्तान के लोगों का हाथ था.

झूठ किस तरीक़े से फ़ैलाया जा सकता है. टीएसडी के ऊपर आरोप लगा दिया कि वह हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री तक की बातें भी सुन रही है. उसने इंटरसेप्ट रिकॉर्ड करने वाले इंस्ट्रूमेंट ख़रीदे हैं. उसने जम्मू-कश्मीर की सरकार को गिराने के लिए पैसा दिया है. पहले भारत सरकार को गिराने के लिए सेना की टुकड़ियों का मूवमेंट और अब गप्प कि जम्मू-कश्मीर की सरकार को गिराने के लिए एक करोड़ 19 लाख. न संपादक को कोई शर्म और न रिपोर्टर को शर्म कि जिसे पढ़ते ही पाठक अख़बार के ऊपर थूक दे और देखने से ही जो रिपोर्ट सुपरफिशियल लगे, ये भारतीय पत्रकारिता को शर्मसार करने वाली घटना है. और टीएसडी पर छपी इस अख़बार की रिपोर्ट के समर्थन में तत्काल भारत सरकार के कुछ मंत्री खड़े हो गए. उन्हें यह शर्म नहीं आई कि वे अपनी ही सेना के उस डिवीज़न का विरोध कर रहे हैं, जो डिवीज़न देश की रक्षा के लिए काम करती है. उन्हें यह भी शर्म नहीं आई कि वे अपने जांबाज़ अफसरों का अपमान कर रहे हैं जो देश में कहीं भी कुछ करने की शपथ लिए, जान देने का जज़्बा लिए सेना में शामिल होते हैं. हथियारों के दलालों, चीन और पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसियों और भारत के किसी ज़माने में पत्रकारिता में सिरमौर रहे अख़बार के गठजोड़ की यह नापाक कहानी है, जिस कहानी ने भारत की पत्रकारिता को शर्मसार कर दिया है. लगभग सारे पत्रकार इस रिपोर्ट को ग़लत मानते हैं, लेकिन वो अपने में यह हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि इस अख़बार की गलत रिपोर्टिंग की शैली का वे मुखर विरोध करें. लगभग हर बड़े पत्रकार ने मुझसे यह कहा कि यह हमें शर्मसार कर देने वाली स्थिति लगती है, लेकिन वे इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आख़िर वे भी एक पत्रकार हैं. यह भारतीय पत्रकारिता की कायरता का दूसरा चेहरा है.

अफ़सोस की बात तो यह है कि यह रिपोर्ट सेना के भ्रष्टाचार को लेकर नहीं है. इस अख़बार ने यह रिपोर्ट सेना के अंदरूनी घटनाओं को लेकर नहीं छापी है, यह व्यक्तित्वों के टकराव की कहानी नहीं है. यह रिपोर्ट भारतीय सेना के जांबाज़ अफ़सरों और सिपाहियों की भारत के रक्षाहितों के लिए की जाने वाली कार्वाइयों का खुलासा है. यह रिपोर्ट भारतीय सेना के अफसरों व जवानों को मारने के षडयंत्र का हिस्सा है. इसलिए श्री रामनाथ गोयनका के वारिस विवेक गोयनका के अख़बार की इस रिपोर्ट का हम जमकर विरोध करते हैं और इसे भारतीय पत्रकारिता की सबसे काली रिपोर्ट के रूप में देखते हैं. पत्रकारिता का महानायक बनता हुए एक सख़्श कैसे महाअपराधी नायक की श्रेणी में बदल जाता है और कैसे उसका पूरा व्यक्तित्व भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े बेशर्म इन्सान के रूप में तब्दील हो जाता है, इसे देखना हो तो रामनाथ गोयनका के वारिस विवेक गोयनका के नेतृत्व में चलने वाले अंग्रेज़ी अख़बार को पढ़कर देखा जा सकता है. यह अख़बार भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ रिपोर्ट नहीं करता, बल्कि भ्रष्टाचारियों के समर्थन में रिपोर्ट करता है, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ने वाले को यह अख़बार कन्फ्यूज्ड आदमी बताता है और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को नायक बनाता है, इस अख़बार में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ रिपोर्ट तलाशनी हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो लोग भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं या आवाज़ उठा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ यह अख़बार पहलवानी करता दिखाई दे रहा है. यह भारत की पत्रकारिता का सबसे गंदा चेहरा है. ■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 31
दिल्ली, 07 अक्टूबर-14 अक्टूबर 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना-800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

अगर टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन जैसी किसी टॉप सीक्रेट यूनिट की कार्यप्रणाली के बारे में कोई जानकारी कहीं से गोपनीय ढंग से निकलकर सामने आती भी है, तो उसकी जानकारी को सार्वजनिक करना देश के साथ गद्दारी करने जैसा है.

अख़बार की रिपोर्ट पर पूर्व सेना प्रमुख का पलटवार

जीत आख़िर में सच्चाई की ही होगी

हाल ही में एक अख़बार ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह पर आरोप लगाए कि उन्होंने सीक्रेट सर्विसेज यूनिट का इस्तेमाल गुप्त ऑपरेशन और गैरकानूनी गतिविधियों में व सीक्रेट सर्विस फंड का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर की सरकार को गिराने में किया. अख़बार के इस दावे की सच्चाई पर सवालिया निशान लगाते हुए वी के सिंह ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे एक गहरी साज़िश क़रार दिया है...

जनरल वी के सिंह

बीते 20 सितंबर को अंग्रेज़ी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर एक स्टोरी छपी, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि मेरे द्वारा गठित सीक्रेट सर्विस यूनिट का इस्तेमाल गुप्त ऑपरेशन और गैरक़ानूनी गतिविधियों में किया है. साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि मैंने सीक्रेट सर्विस फंड का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर की सरकार को गिराने में किया. अख़बार का दावा है कि जनरल वीके सिंह द्वारा गठित मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट- टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन के क्रियाकलापों की जांच के लिए एक टॉप सीक्रेट आर्मी बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी बैठाई गई है और यह रिपोर्ट वहीं से लीक हुई.

मैं शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं कि यह सारे आरोप झूठे-बेबुनियाद और किसी की शह पर लगाए गए हैं. मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन की स्थापना मैंने नहीं की, बल्कि पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किए गए मुंबई हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की सलाह के मद्देनजर सेना ने इसकी स्थापना की थी. टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन रक्षा मंत्री के निर्देश पर बनाई गई और इसकी स्थापना डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलीजेंस में उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर ही हुई. हालांकि हम इसके काम के स्वरूप पर गौर करें तो यह खुफिया इकाई के तौर पर ही दिखती है, लेकिन वास्तव में इसका अस्तित्व एक खुफिया इकाई के रूप में बिल्कुल नहीं है. मेरी सेवानिवृत्ति के बाद ही यह इकाई भंग हो गई थी, हालांकि ऐसा क्यों किया गया, इसे बेहतर ढंग से वही बता सकते हैं, जिन्होंने इसे भंग करने का निर्णय लिया.

जहां तक आम जनता का सवाल है तो अपनी कार्यप्रणाली और प्रकृति के अनुरूप टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन द्वारा किए गए ऑपरेशन हमेशा बेहद गोपनीय होते थे. ऐसी स्थिति में टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन जैसी कोई संस्था है, इसको सार्वजनिक करना ही नहीं चाहिए था. दूसरे अगर ऐसी किसी टॉप सीक्रेट यूनिट की कार्यप्रणाली के बारे में कोई जानकारी कहीं से गोपनीय ढंग से निकलकर आती भी है, तो उसकी जानकारी को सार्वजनिक करना देश के साथ गद्दारी करना है. भले ही वह जानकारी सही हो या गलत. केवल इतनी सी जानकारी का सार्वजनिक हो जाना कि भारतीय सेना में टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन जैसी कोई इकाई है, देश के दुश्मनों के लिए मददगार हो सकती है. और चूंकि ऐसा करना देशद्रोह है, इसलिए जानकारी देने वाले और जानकारी हासिल करने में मदद करने वालों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. इन सब के बावजूद मीडिया में तकरीबन पिछले एक-ढेड़ वर्ष से टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन को लेकर झूठी खबरें प्रकाशित हो रही हैं. लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि भारत सरकार इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है और जानने की कोशिश भी नहीं कर रही है कि यह भारतीय सेना से जुड़ी जानकारियां देने वाले कौन लोग हैं. न ही सरकार ने इस पर कोई वक्तव्य जारी किया और न ही इस दुर्भावनापूर्ण और खतरनाक मुहिम पर कोई रोक लगाने की कोशिश की.

एक कहावत है कि अगर कोई झूठ बार-बार सच के तौर पर प्रचारित किया जाए तो वह झूठ भी सच लगने लगता है. इस कहावत को चरितार्थ करते हुए टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन के बारे में गलत और दुर्भावनापूर्ण प्रचार किया गया और जानबूझ कर

> **पिछले एक-ढेड़ वर्ष से टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन को लेकर झूठी खबरें प्रकाशित हो रही हैं. लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि भारत सरकार इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है और जानने की कोशिश भी नहीं कर रही है कि यह भारतीय सेना से जुड़ी जानकारियां देने वाले कौन लोग हैं. न ही सरकार ने इस पर कोई वक्तव्य जारी किया और न ही इस दुर्भावनापूर्ण और ख़तरनाक मुहिम पर कोई रोक लगाने की कोशिश की.**

फैलाए गए इस प्रोपेगेंडा ने अब एक खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है. कैसे, इसका जिक्र मैं इसी लेख में आगे करूंगा.

प्रधानमंत्री कार्यालय से बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी इन खुफिया जानकारियों को लीक करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही मंत्रालय द्वारा नहीं की गई. मामले को नजरअंदाज करते हुए चिंगारी को भड़कने के लिए छोड़ दिया गया. 2102 की शुरुआत से ही इन तथाकथित खुफिया जानकारियों के नाम पर झूठी अफवाहें फैलाई गईं और मेरी राष्ट्रीयता, ईमानदारी और देशभक्ति पर सवाल उठाए गए. इन आरोपों की शुरुआत इस बात से हुई कि रक्षा मंत्री के कार्यालय में छिपे हुए माइक्रोफोन लगाए गए. फिर यह आरोप लगा कि सैन्य दस्तों को खुफिया तरीके से संचालित किया गया, ताकि अप्रत्याशित हमला किया जा सके. फिर मुझ पर प्रधानमंत्री को भेजी गई अपनी ही चिट्ठी लीक करने का आरोप लगा, जिसमें सेना के पास के पास हथियारों की और आयुध भंडारों की बेहद कमी होने की बात की गई थी, जिससे हमारी लड़ाकू-शक्ति प्रभावित हो सकती थी. और आखिर में यह आरोप लगाया गया कि मैंने जम्मू और कश्मीर की सरकार को गिराने के लिए टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन का इस्तेमाल किया.

इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को आधार बनाकर 24 सितंबर को द हिंदू अखबार के चंड़ीगढ़ संवाददाता ने एक खबर छापी, जिसका शीर्षक था कि वी के सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हैं और यह मानते हैं कि जो प्रो-इंडिया एनजीओ हैं, उन्हें पैसे दिए जाते हैं. इस रिपोर्ट का पहला वाक्य ही गलत है, जिसमें यह कहा गया है कि इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के बाद किसी अखबार को दिया गया यह उनका पहला साक्षात्कार है. यह पूरी तरह से गलत है. वास्तविक्ता तो यह है कि मैं अपने एक दोस्त के घर पर था, उनके आग्रह पर कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया. अखबार ने अनुमानों के आधार पर बहुत सारी झूठ और बरगलाने वाली बातें इस स्टोरी में जोड़ दीं. इनमें सबसे गौरतलब तो यह है कि मैंने कहा था टीडीएस की दो जो प्रमुख उपलब्धियां रही हैं, उनमें एक 2011 के पंचायती चुनाव और दूसरी 2010 में कश्मीर में संगबाजों द्वारा किया गए उपद्रव पर तुरंत नियंत्रण पाना. इस रिपोर्ट को लिखने वाले ने बड़ी ही चालाकी से कट-पेस्ट नीति को अपनाते हुए जो मैंने उससे कहा था और जो मैंने टीवी पर इंटरव्यू में कहा था, उसमें से कुछ बातें लेकर कहीं का कहीं अपने मन से जोड़ दिया. इस संवाददाता का यह भी दावा था (संवाददाता सेना में एक री-इम्प्लॉयड अधिकारी की पत्नी हैं) कि 15 कॉर्प्स के अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन द्वारा इस कॉर्प्स को ऑफ द एयर इंटरसेप्टर मुहैया कराए थे, जोकि बाद में दोषपूर्ण पाए गए. यह दोनों ही बातें झूठी और बेबुनियाद हैं, जिन्हें कि बड़ी चालाकी से रिपोर्ट में डाला गया.

रिपोर्ट के प्रकाशित होने के तुरंत बाद ही राजनीतिक और गैर-राजनीतिक ताकतें अपने निहित स्वार्थों के चलते जानबूझ कर रिपोर्ट को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही हैं और बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं ताकि जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद फैलाया जाए और सेना में असंगति लाई जाए. द हिंदू ने खुद ही 25 सितंबर को प्रकाशित स्टोरी के माध्यम से उन्माद फैलाने की कोशिश की, जिसका शीर्षक था कि जम्मू-कश्मीर में सरपंच कहते हैं कि हमारी जान ख़तरे में है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, मैंने जो लापरवाही भरा बयान दिया, उसी का नतीजा है कि आज जम्मू-कश्मीर में 30,000 पंचों और सरपंचों को अलगाववादियों से जान का ख़तरा है. ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने 2011 में राज्य में पंचायत चुनावों को बदनाम किया है. यह आरोप पूरी तरह से सच्चाई से कोसों दूर है. अख़बार द्वारा इन कथनों को बीच-बीच में ऐसे डाला गया है जैसे मैंने ही यह बयान दिए हों. यह मनगढ़ंत कोरी गप्प के अलावा और कुछ नहीं है.

अख़बार के संपादक ने अख़बार के पहले पन्ने पर 26 सितंबर को एक रिपोर्ट लिखी जिसका शीर्षक है अधिकारियों का मानना है कि जनरल सिंह के दावों ने देश को नुकसाना पहुंचाया है. वास्तव में संपादक महोदय चिंगारी को हवा दे रहे हैं. सरकार के कुछ बड़े अधिकारियों का हवाला देते हुए यह रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर पर दिए गए मेरे हालिया वक्तव्यों के कारण मुझ पर देश को भारी छति पहुंचाने का आरोप लगाती है. साथ ही यह भी कहा गया है कि सरकार मेरे उन दावों की जांच कर रही है जिसमें कहा गया है कि मिलिट्री के अफसर नेताओं को गैर-कानूनी ढंग से पैसे देते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार यह भी कह रही है कि वह तथ्यों की जांच के बाद इस बात का फैसला करेगी कि उसे क्या कदम उठाने चाहिए.

यह रिपोर्ट सिद्धार्थ वरदराजन ने लिखी है, जो द हिंदू के संपादक हैं. प्रधानमंत्री यूएन में संबोधन देने और अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए अमेरिका की यात्रा पर हैं और संपादक महोदय भी प्रधानमंत्री के साथ गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं. यह रिपोर्ट वाशिंगटन डीसी जाते समय रास्ते में हवाई जहाज से ही लिखी गई. इस प्रतिनिधिमंडल में प्रधानमंत्री के पूर्व मुख्य सचिव जो कि इस समय उनके सलाहकार हैं, पूर्व विदेश सचिव और वर्तमान सुरक्षा सलाहकार, पूर्व रक्षा सचिव व भारत के वर्तमान महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार, इंडियन एक्सप्रेस के संपादक व द हिंदू के संपादक शामिल हैं.

पूर्व रक्षा सचिव जो कि अब सीएजी है, उन्होंने सेना के माध्यम से बोर्ड ऑफ इक्वायरी रिपोर्ट मार्च, 2013 में हासिल की. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं. रक्षा मंत्रालय के एक पूर्व संयुक्त सचिव जो कि पूर्व रक्षा सचिव के बेहद करीबी रहे हैं, उन्होंने यह रिपोर्ट लीक की और इसे इंडियन एक्सप्रेस के संपादक ने छापा और द हिंदू के संपादक ने यह लिखते हुए इसे और और उन्माद भरा बना दिया कि मेरी वजह से जम्मू-कश्मीर के 30,000 हजार सरपंचों और पंचों की जान खतरे में है.

संभवत: यह वही टीम है, जिन्होंने रक्षा के प्रति भारत की अधूरी तैयारी के संदर्भ में प्रधानमंत्री को भेजे मेरे अतिगोपनीय पत्र को लीक किया था. टाट्रा ट्रक घोटाला, हथियारों की खरीद के कई घोटालों और उससे बढ़कर सियाचीन ग्लेसियर संदेहास्पद ट्रैक 2 के माध्यम से बेचने की कोशिश, जिसका नेतृत्व एयर चीफ मार्शल त्यागी ने किया और द हिंदू के संपादक इसमें प्रमुख भूमिका में थे.

बहुत सारी घटनाएं और सच हैं और यह ताकतवर समूह हमेशा उन पर पर्दा नहीं डाल पाएगा. इन्हें राष्ट्रहित से कोई सरोकार नहीं है. घोटाले-दर-घोटाले ने सत्ताधारी पार्टी को नैतिक रूप से भ्रष्ट साबित कर दिया है. मैं इन लोगों को राष्ट्रीय आदर्श की याद दिलाना चाहता हूं कि सत्यमेव जयते. केवल सत्य की ही विजय होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

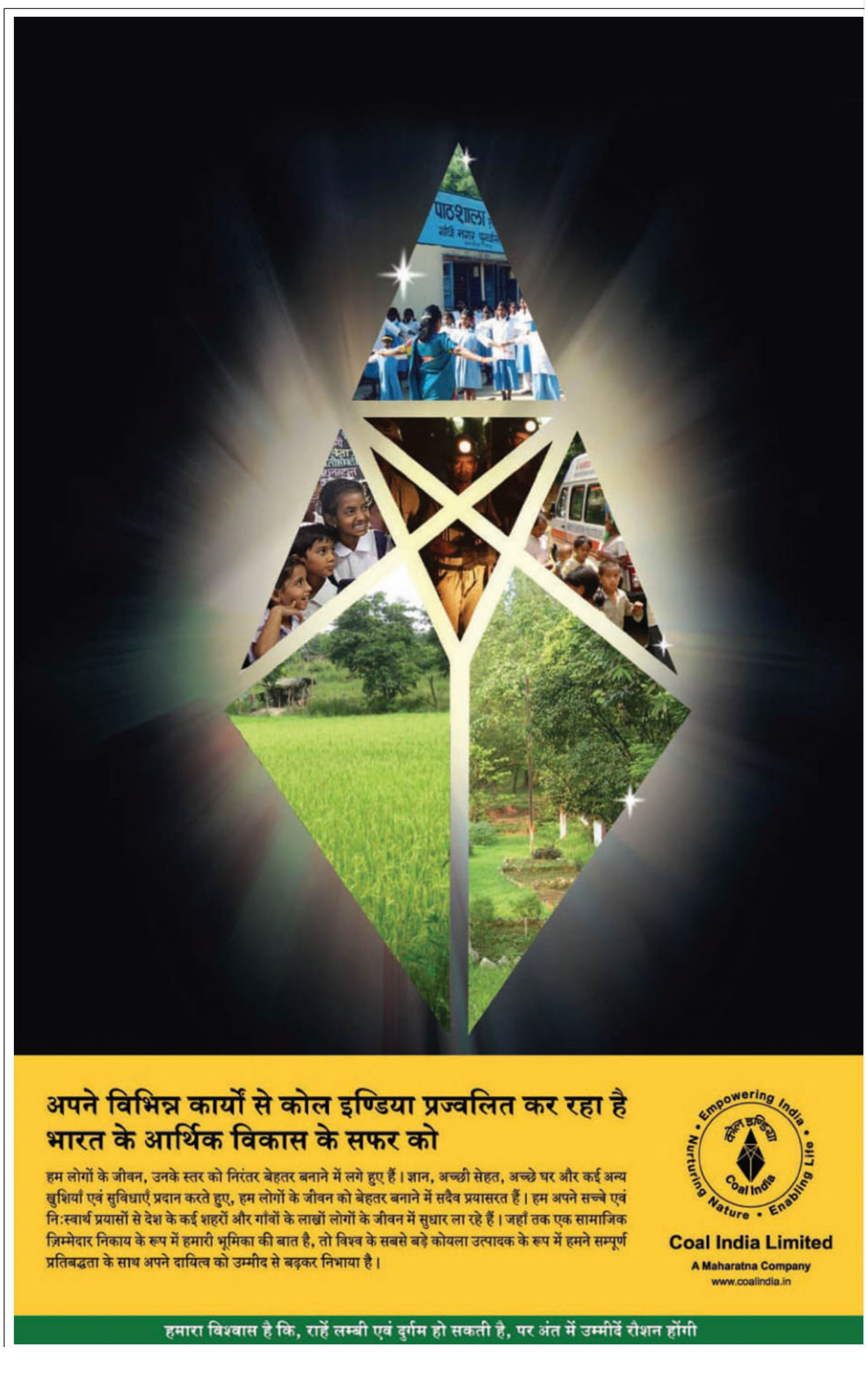

अमित शाह अपने ही बनाए कानूनी भंवर में फंस चुके हैं. अमित शाह की गिरफ्तारी सोहराबुद्दीन और कौसर बी के मामले में हुई थी. तुलसी प्रजापति का केस उसके बाद सामने आया, लेकिन तब तक अमित शाह को कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी.

सीबीआई के शिकंजे में अमित शाह और नरेंद्र मोदी

सियासी समर अब पूरी तरह छिड़ चुका है. सभी अहम दल अपने-अपने हिसाब से शह-मात की बाजियां खेलने लगे हैं. कांग्रेस ने भी 2014 के लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें उसने समाजवादी पार्टी को भी अपना सहभागी बनाया है. निशाने पर हैं गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी. एक तरफ सांप्रदायिक सौहार्द-बिगड़ने का अंदेशा ज़ाहिर कर समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में मोदी के चुनावी दौरों पर रोक लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सीबीआई के ज़रिये नरेंद्र मोदी के खासमखास अमित शाह को काबू करने की कोशिश में है.

रूबी अरुण

सीबीआई इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि सोहराबुद्दीन, कौसर बी और तुलसी प्रजापति की मौत के आरोपी अमित शाह की जमानत याचिका ख़ारिज करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगा दी जाय. इसका नतीजा यह होगा कि अमित शाह एक बार फिर सलाख़ों के पीछे चले जाएंगे. अमित शाह, नरेंद्र मोदी की तरफ से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह कमान संभाले हुए हैं. उनके जेल जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी के हाथ से फिसलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि फिर मोदी के पास अमित शाह जैसा कोई दूसरा भरोसेमंद व्यक्ति नहीं रहेगा जो वहां नरेंद्र मोदी के विजय के अभियान को चला सके. कांग्रेस अब सीधे-सीधे नरेंद्र मोदी पर वार न करके उनके भरोसे के लोगों पर प्रहार करने की योजना बना रही है, ताकि मोदी कमज़ोर हो जाएं और उनका भारत पर राज करने का सपना पूरा न हो सके.

दरअसल, अमित शाह अपने ही बनाए कानूनी भंवर में फंस गए हैं. अमित शाह की गिरफ्तारी सोहराबुद्दीन और कौसर बी के मामले में हुई थी. तुलसी प्रजापति का केस उसके बाद सामने आया, लेकिन तब तक अमित शाह को कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी. जब अमित शाह को इस बात का एहसास हुआ कि तुलसी प्रजापति के मामले में उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है, तब उन्होंने आनन-फानन में सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी यह कहते हुए दाखिल कर दी कि जब यह तीनों केस आपस में जुड़े हुए हैं तो इसमें अलग से एफआईआर दर्ज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह की बात मान ली. पर इसमें एक ज़बरदस्त कानूनी पेंच आ गया. इन तीनों केसों के क्लब होते ही इसमें अधिकतम सज़ा के तौर पर मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान समाहित हो गया. सीबीआई जब अमित शाह की जमानत को ख़ारिज करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल करेगी तो वह कोर्ट में इसी क़ानूनी प्रावधान का हवाला देगी. ऐसे में इस बात की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट अमित शाह की जमानत रद्द कर दे. और अगर ऐसा हुआ तो ऐन चुनावों के पहले मोदी के लिए यकीनन बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है.

वैसे भी सीबीआई ने तुलसी प्रजापति फ़र्ज़ी मुठभेड़ कांड को एक परफेक्ट मर्डर करार दिया हुआ है. दांता कोर्ट में सीबीआई ने अपनी जो चार्जशीट पेश की थी, उसमें यह खुलासा किया था कि गुजरात के तत्कालीन गृहराज्य मंत्री अमित शाह ने अपनी ताक़त का बेजा इस्तेमाल करते हुए राज्य के पुलिस अधिकारियों पर यह दबाव डाला कि तुलसी प्रजापति की हत्या कर दी जाए.

यहां आपके लिए यह जानना ज़रूरी होगा कि तुलसी प्रजापति कौन था और उसे फ़र्ज़ी मुठभेड़ में क्यों मारा गया. तुलसी प्रजापति, सोहराबुद्दीन का दाहिना हाथ था. सोहराबुद्दीन पर यह आरोप था कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की नीयत से गुजरात आया था. सोहराबुद्दीन, डी कंपनी का गुर्गा था. टाडा में दोषी और राजस्थान की मार्बल लॉबी से रंगदारी वसूलने का आरोपी. राजस्थान में एक गैंगस्टर हुआ करता था हामिद लाला. जिसकी हत्या तुलसी प्रजापति और सोहराबुद्दीन ने मिलकर की थी. जहां तुलसी और सोहराबुद्दीन राजस्थान के मार्बल व्यापारियों से फिरौती वसूलने का काम करते थे, वही हामिद लाला व्यापारियों को सुरक्षा देने का काम करता था. तुलसी पर अहमदाबाद के एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का भी आरोप था. तुलसी को पहले ही यह आशंका थी कि गुजरात पुलिस उसे फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मार सकती है. इसलिए जब पुलिस ने उसे राजस्थान से गिरफ़्तार किया था तो उसने तभी मानवाधिकार आयोग और अदालत को यह आवेदन दिया था कि पुलिस उसकी हत्या कर सकती है. जब गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन को फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मारा और उसके बाद, सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी की हत्या कर दी, तब प्रजापति तुलसी इन सभी घटनाओं के दरम्यान मौके पर पुलिस के साथ हाज़िर था. तुलसी, पुलिस की कारगुजारियों का इकलौता गवाह था. सोहराबुद्दीन और तुलसी की मुलाक़ात जेल में हुई थी और उसके बाद से ही दोनों मिल कर एक साथ जुर्म को अंजाम देते थे. तुलसी सोहराबुद्दीन के फिरौती नेटवर्क को भी संभालता था.

इस बात की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट अमित शाह की जमानत रद्द कर दे. और अगर ऐसा हुआ तो ऐन चुनावों के पहले मोदी के लिए यक़ीनन बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है. सीबीआई ने तुलसी प्रजापति फ़र्ज़ी मुठभेड़ कांड को एक परफेक्ट मर्डर करार दिया हुआ है. सीबीआई ने चार्जशीट में यह खुलासा किया था कि गुजरात के तत्कालीन गृहराज्य मंत्री अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों पर यह दबाव डाला कि तुलसी प्रजापति की हत्या कर दी जाए.

बहरहाल, सीबीआई के मुताबिक सोहराबुद्दीन और कौसर बी को जब सांगली से गुजरात पुलिस ने अगवा किया, उस समय तीसरा शख़्स तुलसी ही था जो पूरी वारदात के दरम्यान मौजूद था. मतलब, तुलसी एकमात्र चश्मदीद गवाह था, इसलिए उसका जिंदा रहना कई लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर देता. इसलिए तुलसी को भी मार दिया गया.

सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के चहेते और गुजरात पुलिस के अधिकारी डीजी बंजारा के कहने पर ही तुलसी सोहराब और कौसर को अपने साथ लेकर आ रहा था. और इसी दरम्यान साज़िशन गुजरात पुलिस ने तीनों को रास्ते से ही उठा लिया. सीबीआई की चार्जशीट के पेज नंबर 6 पर अमित शाह और पुलिस अधिकारियों के बीच 26 नवम्बर, 2005 से लेकर 30 नवम्बर, 2005 तक की कॉल डीटेल्स को रखा है. जिसके अनुसार आईपीएस राजकुमार, डीजी बंजारा और पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह के बीच की लम्बी बातचीत का ब्यौरा है. यह वही वक़्त था जब तुलसी को उदयपुर से अहमदाबाद कोर्ट में पेशी के लिए बार-बार ले आया जा रहा था. चार्जशीट के पेज नंबर 18 पर दर्ज है कि 11 और 22 दिसंबर, 2006 को अमित शाह ने अपने दफ्तर में एक ख़ास बैठक बुलाई थी. इस गोपनीय बैठक में डीजीपी पांडे, एडिशनल डीजीपी जी सी रायगर, आईजी गीता जौहरी शामिल थीं. इस दौरान अमित शाह ने पुलिस अधिकारी सोलंकी की जांच रिपोर्ट पर नाराज़गी जताई और गीता जौहरी को जांच के तमाम पेपर नष्ट करने के आदेश दिए. एडिशनल डीजीपी जी सी रायगर ने अमित शाह की इस साज़िश में शामिल होने से मना कर दिया, तब अमित शाह ने नाराज़ होकर उनका ट्रांसफर कर दिया. सीबीआई ने अपनी चार्जशीट के पेज नंबर 10 और 11 में दावा किया है कि तुलसी को मारने की तैयारी लंबे समय से चल रही थी.

जेल में बंद नरेंद्र मोदी के बेहद खास रह चुके गुजरात के पुलिस अधिकारी डीजी बंजारा के जिस पत्र पर मोदी के ख़िलाफ़ राजनीतिक बावेला मचा था, उस पत्र में भी बंजारा ने इन सभी बातों का स्पष्ट जिक्र किया है. बंजारा ने लिखा कि हम सरकार के वफ़ादार सिपाही रहे और उसी के बताए काम करने पर गिरफ़्तार होने के बाद किसी ने हमारी सुध नहीं ली. 6 साल से जेल में बंद वंजारा ने लिखा है, वक्त गुज़रने के साथ-साथ मुझे अहसास हुआ इस सरकार की हमें बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि यह तो गुप-चुप तरीके से हमें अंदर रखने की कोशिशें कर रही है, ताकि सीबीआई से अपनी चमड़ी बचा सके और राजनीतिक फ़ायदे उठा सके.

अगर हम सीबीआई द्वारा दाख़िल की गई चार्जशीट पर भी नज़र डालें, तो उसके मुताबिक 22 नवंबर, 2005 को कौसर बी, उसका पति सोहराबुद्दीन और सोहराबुद्दीन का दोस्त तुलसी आंध्र प्रदेश की एसआरटीसी की बस में बैठे थे. जब उनकी बस सांगली के पास पहुंची, तब अचानक बस के आगे पुलिस की एक गाड़ी आ गई. सोहराबुद्दीन, कौसर बी और तुलसी कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बस के अंदर गुजरात एटीएस और राजस्थान पुलिस की टीम घुस चुकी थी. पुलिस ने आनन-फानन में कौसर, उसके पति सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति को अपने शिकंजे में ले लिया और ज़बरन उन्हें एक टोयटा क्वालिस कार में बिठा लिया. उन्हें गांधीनगर के बाहरी इलाके जमीयतपुरा के एक फार्म हाउस की दिशा में ले आया गया. 26 नवंबर, 2005 को पुलिस वाले सोहराबुद्दीन को, उसकी पत्नी कौसर बी से अलग कर ले गए और उसी दिन सोहराबुद्दीन के क़त्ल की खबर कौसर बी के पास पहुची.

सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है, उसमें गुजरात पुलिस के कुछ अधिकारियों के बयान भी दर्ज हैं. इन बयानों में साफ़ तौर पर यह कहा गया है कि सोहराबुद्दीन को मारने के बाद, कौसर बी को लेकर एटीएस के डीआईजी डीजी बंजारा निश्ंचित थे, लेकिन अचानक उनके पास एक फोन कॉल आई, जो अमित शाह की थी. गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने डीजी बंजारा को सख़्त निर्देश देते हुए कहा कि कौसर बी का ज़िंदा रहना ख़तरनाक है, इसलिए उसे मार दिया जाए. तब 28 नवंबर की आधी रात को कौसर बी को ज़हर का इंजेक्शन देकर मार दिया गया. सीबीआई के पास उस दवा दुकान के दुकानदार का भी बयान है, जहां से ज़हर का इंजेक्शन ख़रीदा गया. कौसर बी को मार कर उसकी लाश को ठिकाने लगाने की ज़िम्मेदारी डिप्टी एसपी एनके अमीन को दी गई थी. सीबीआई के दस्तावेज़ों के मुताबिक़ जब कौसर बी मर गई, तब उसकी लाश अर्हाम फार्म हाउस से उठाकर इल्लोर गांव ले जाया गया. जहां डी जी बंजारा पहले से ही मौजूद थे. वहां एक टाटा 407 भी था, जिसमें चार सौ किलो लकड़ी लदी थी, जो मोटेरा रोड के भगवती फार्म हॉउस से मंगाई गई थी. यहीं, इसी गांव में कौसर बी की लाश जला दी गई. उसकी हड्डियों को नर्मदा में बहा दिया गया, जबकि चिता की राख को इल्लोर गांव के खेतों में बिखेर दिया गया.

हालांकि, सीबीआई ने सितम्बर, 2012 में भी अमित शाह की जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई थी, पर कोर्ट ने जमानत बरकरार रखी. पर इस बार सीबीआई एक बार फिर तमाम सबूतों और गवाहों को समेट कर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है. सीबीआई को लगता है कि अमित शाह के ख़िलाफ़ तीन केसों के क्लब हो जाने और सज़ा का प्रावधान बदल जाने की वज़ह से कोर्ट उनकी दलील मानेगा और अमित शाह की जमानत ख़ारिज कर देगा. ज़ाहिर है अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी के लिए उत्तर प्रदेश और केंद्र की राह दुरूह हो सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

> आख़िर वे कौन से आर्थिक कारक हैं, जिसकी वजह से सदियों से साथ रह रहे जाट और मुसलामानों के बीच वैमनस्यता की गहरी खाई खिंच गई? दरअसल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट हमेशा से ही प्रभावशाली रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र की अधिकतर ज़मीन उनके हिस्से में हैं, जिन पर बड़े पैमाने पर खेती होती है. चौधरी चरण सिंह के दौर से ही इस इलाक़े में जाट और मुस्लिमों का विश्वसनीय गठबंधन बना रहा है. यह गठबंधन दोनों ही वर्गों के लिए फायदेमंद रहा.

मुज़फ़्फ़रनगर दंगों का चुनावी असर

मयंक मिश्रा

कभी ख़त्म न होने वाली धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता का आपसी टकराव एक बार फिर उत्तर प्रदेश में लौट आया है. इसकी परिणति पिछले दिनों हमें इस राज्य के मुज़फ़्फ़रनगर और उससे सटे अन्य ज़िलों में हुए दंगों में दिखाई दी. धर्मनिरपेक्ष ताक़तों का आरोप है कि प्रदेश के पैदा हुए इन हालातों के लिए भगवा बिग्रेड और उनके द्वारा लोगों में बांटी गई भड़काऊ भाषणों की सीडी ज़िम्मेदार है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उत्तर प्रदेश में समाजावदी पार्टी की सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं. इससे अलग कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन दंगों के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजावादी पार्टी दोनों ही ज़िम्मेदार हैं. दरअसल, उनका मानना है कि धर्म के आधार पर धुव्रीकरण करना दोनों ही पार्टियों के लिए आगामी लोकसभा चुनावों में फ़ायदेमंद होगा, लेकिन सवाल यह है कि राजनीति के इस खेल में जाट और मुस्लिम, राजनीतिक दलों का साथ क्यों देंगे. वे भी उस आपसी सद्भाव की बलि चढ़ाकर, जिसे दशकों से उन्होंने संजोया है.

हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों ने अपने फ़ायदे के लिए लोगों के बीच तनाव फैलाया हो, जिसने दंगे का रूप ले लिया, लेकिन वहां इसके मूल कारण अगर मौजूद ही न रहे होते, तो क्या राजनीतिक दल इसे बढ़ावा दे पाते. शायद नहीं. उत्तर प्रदेश की राजनीति की खास समझ रखने वाली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका सुधा पाई के मुताबिक, ऐसे हादसे केवल आईडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं होते, बल्कि उसके पीछे आर्थिक कारकों की भी बड़ी भूमिका होती है.

आख़िर वे कौन से आर्थिक कारक हैं, जिसकी वजह से सदियों से साथ रह रहे जाट और मुसलामानों के बीच वैमनस्यता की गहरी खाई खिंच गई? दरअसल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट हमेशा से ही प्रभावशाली रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र की अधिकतर ज़मीन उनके हिस्से में हैं, जिस पर बड़े पैमाने पर खेती होती है. चौधरी चरण सिंह के दौर से ही इस इलाके में जाट और मुस्लिमों का विश्वसनीय गठबंधन बना रहा है. यह गठबंधन दोनों ही वर्गों के लिए फायदेमंद रहा. हां, यह ज़रूर कहा जा सकता है कि दोनों के लिए यह लाभ अलग-अलग दृष्टिकोण से था.

विशेषज्ञों का मानना है कि 1987 में जब चरण सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद धीरे-धीरे इस गठबंधन में तनाव आने शुरू हो गए. कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रोफेसर व सेंटर फॉर डेवलपिंग स्ट्डीज द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों का हिस्सा रह चुके डॉ ए. के. वर्मा बताते हैं कि चरण सिंह वह व्यक्ति थे, जिन्होंने इन दोनों समुदाय के लोगों को एक डोर में बांधे रखा था, लेकिन उनके निधन के बाद इन दोनों समुदायों के बीच के रिश्तों की खाई गहरी होती गई. चरण सिंह के बाद मुलायम सिंह और अजीत सिंह ने इन दोनों समुदायों पर अपना-अपना दावा ठोंकना शुरू किया, जिससे दोनों समुदाय बंटने लगे. डॉ वर्मा बताते हैं कि मुसलमान इस क्षेत्र में संख्या बल में तो हमेशा से ज़्यादा रहे, लेकिन उनके आत्मविश्वास में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी होने लगी, क्योंकि समय के साथ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी. धनबल और आत्मबल के इस मेल ने उन्हें राजनीतिक स्तर पर भी मजबूत करना शुरू किया. जनगणना 2001 के आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 ज़िलों में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी के 33 फीसद से अधिक है. 2012 के विधानसभा चुनावों में इस क्षेत्र की सभी सीटों में से 26 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी विजयी हुए.

हमें यह भी समझना होगा कि आख़िर वे कौन से कारण हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में मुसलमानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया. 2006 में जारी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो कुछ हद तक इसे समझा जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही उन कृषि कार्यों में मुसलमानों की संख्या अन्य समुदायों से कम हो, लेकिन मैन्यूफैक्चरिंग और ट्रेड के मामले उनकी संख्या (विशेषकर पुरुषों की) दूसरे सामाजिक-धार्मिक समूहों से काफी ज्यादा है. साथ ही निर्माण क्षेत्र में भी इस समुदाय के लोगों की भागीदारी अन्य समुदाय से ज़्यादा है.

> हो सकता है मज़फ़्फ़रनगर दंगे की साज़िश राजनीतिक पार्टियों ने अपने फ़ायदे के लिए रची हो, लेकिन वहां इसके मूल कारण अगर मौजूद ही न रहे होते, तो क्या राजनीतिक दल इसे बढ़ावा दे पाते. शायद नहीं. सच पूछा जाए तो ऐसे हादसे केवल आईडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं होते, बल्कि उसके पीछे आर्थिक कारकों की भी बड़ी भूमिका होती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, विनिर्माण के अलावा थोक व फुटकर व्यापार, भू-यातायात, मोटरगाड़ियों की मरम्मत, तंबाकू उत्पाद, टेक्सटाइल व वस्त्र उद्योगों के साथ-साथ धातुओं के सामान के उत्पादन जैसे व्यापार में मुसलमानों की हिस्सेदारी बहुत है. रिपोर्ट के मुताबिक, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में यह हिस्सेदारी दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान में 25 प्रतिशत से भी अधिक है.

हालांकि रिपोर्ट यह नहीं बताती कि इन क्षेत्रों में विकास दर क्या है. हां, रिपोर्ट में इस बात का ज़िक्र ज़रूर है कि 1994 से 2001 के बीच तंबाकू उत्पाद सेक्टर में रोजगार की दर 7.7 प्रतिशत थी. वस्त्र उद्योग में 14.4 प्रतिशत, ऑटो रिपेयर सेक्टर में 9.4 प्रतिशत व इलेक्ट्रिकल मशीनरी सेक्टर में रोजगार की दर 18.6 रही है. स्पष्ट है कि पिछले दस वर्षों में कंन्सट्रक्शन और ऑटो सेक्टर में पिछले 10 वर्षों में जो तेजी आई, उसका लाभ मुसलमानों को मिला.

मेरठ में कांग्रेस से जुड़े एक विश्लेषक अपना नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कुशल कारीगरों की मांग बढ़ी है और इसका फायदा मुसलमानों को मिला है. साथ ही इस क्षेत्र में फल व्यापार पर पूरी तरह से मुसलमानों का कब्जा है. उनके मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश फलों के बागीचे या तो मुसलमानों के अपने हैं या फिर वे उनके द्वारा संचालित हैं. इन क्षेत्रों से नजदीक के बड़े शहरों, जैसे दिल्ली से भारी मात्रा में फलों का आयात होता है.

इसके विपरीत जाट समुदाय के लोगों की माली हालत कमज़ोर होती जा रही है. क्षेत्र की अधिकांश चीनी मिलों पर जाटों का कब्ज़ा है, लेकिन चीनी मिलों की हालत दिन-ब-दिन खस्ता होती जा रही है. कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राज्य का चीनी का कटोरा कहा जाता था. अकेले मुज़फ़्फ़रनगर में ही 11 चीनी मिलें हैं. भारतीय चीनी मिल के मुख्य निदेशक अविनाश वर्मा बताते हैं कि सरकार ने जो गन्ना नीति बनाई, उसने इस राज्य में इससे जुड़े उद्योग को काफी नुकसान पहुंचाया. एक अनुमान के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 14 में प्रदेश की चीनी मिलों को तकरीबन 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है. साथ ही मिलों पर तकरीबन 3000 करोड़ की देनदारी भी बाक़ी है, जो मिलें किसानों को चुकाएंगी.

इस बकाए के अलावा किसानों के सामने दूसरा एक और संकट है कि पिछले 10 साल से गन्ने की उत्पादकता लगातार घट रही है. अविनाश वर्मा के मुताबिक, 10 साल पहले एक हेक्टेयर में 55 टन गन्ने का उत्पाद होता था और आज भी एक हेक्टेरयर में उतना ही उत्पादन हो रहा है. गन्ना उत्पादन का जो राष्ट्रीय औसत है, वह राज्य में राष्ट्रीय औसत से 10-12 टन प्रति हेक्टेयर कम है. हालांकि गन्ने की कीमतों में इजाफा हुआ है. 2005 में एक क्विंटल गन्ने का मूल्य 115 था, जो बढ़क़र 2010 में 165 रुपये प्रति क्विंटल हो गया. बावजूद इसके, किसानों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनियां मूल्यों में होने वाली इस बढ़ोत्तरी को चुकाने की स्थिति में नहीं हैं. मिलें पहले नवंबर में किसानों का भुगतान कर देती थीं, लेकिन अब इसमें छह से सात महीने की देरी होने लगी है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में किसान आर्थिक तौर पर बेहद दबाव में हैं.

यह दबाव के ही संकेत हैं (हो सकता है कि सही हो या केवल प्रतीत होता है) कि जाट पिछले कुछ समय से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों की श्रेणी में शामिल किया जाए, ताकि सरकारी नौकरियों में आरक्षण पा सकें. सुधा पाई बताती हैं कि 20 साल पहले यह सोचना भी अकल्पनीय था कि जाट भी ओबीसी के दर्जे की मांग कर सकते हैं. जाट आर्थिक तौर पर कमज़ोर होते गए और मुसलमान आर्थिक तौर पर मजबूत. जाटों के लिए यह बेहद असहनीय सी स्थिति हो रही थी कि मुसलमान उनके बराबरी पर आ गए हैं और कुछ क्षेत्रों, मसलन राजनीति में उनसे भी आगे निकलते जा रहे हैं. आगरा युनिवर्सिटी से जुड़े मेरठ निवासी शशिकांत पांडे इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि इन स्थितियों ने दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा करना शुरू किया और जब यह तनाव बढ़ गया तो इस तरह के टकराव सामने आने लगें. वे कहते हैं कि इसे हम केवल दो समुदायों के बीच का झगड़ा नहीं मान सकते, इन समुदायों के बीच की प्रतिस्पर्धा भी इसका एक कारण है.

प्रसिद्ध समाजशास्त्री दीपांकर गुप्ता इन दंगों के प्रति अलग नज़रिया रखते हैं. इन सांप्रदायिक दंगों की मुख्य वजह गांवों की बदलती अर्थव्यवस्था है, जिसके चलते अंदर ही अंदर तनाव की स्थिति बन रही थी. वे मानते हैं कि शहरों में जो अल्पमत और बहुमत की सोच है, वह गांवों में प्रवेश कर रही है, जिससे गांवों में जो पारंपरिक भाईचारे की भावना है, वह कमजोर पड़ रही है.

एक सवाल यह भी है कि जाट और मुस्लिमों के बीच पैदा हुई दरार, जो कि इन दंगों के दौरान दिखाई दी, उसका असर आने वाले चुनावों पर क्या पड़ेगा? पाई मानती हैं कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी को इसका सबसे बड़ा फायदा होगा. वो कहती हैं कि असुरक्षा की भावना में कोई नहीं जीना चाहता. साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि जरूरी नहीं है कि धार्मिक स्तर पर ध्रुवीकरण का फायदा भाजपा और सपा को हो ही, क्योंकि देश 1991 के दौर से काफी आगे निकल चुका है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब मुजफ्फरनगर के दंगा प्रभावित इलाकों का दौर करने गए, तो जिस तरह की प्रतिक्रियाओं से उन्हें दो-चार होना पड़ा, उससे जाहिर होता है कि वास्तव में देश 1991 को पीछे छोड़ आया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

ऊपरी तौर पर जिस तरह से केरल एक समृद्ध और साक्षर राज्य की छवि रखता है, राजनीतिक तौर पर वह उतना ही खोखला होता जा रहा है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन (यूडीएफ) और मार्क्सवादी गठबंधन (एलडीएफ) के बीच राजनीतिक उठापटक में राज्य के असली मुद्दे खो गए हैं और बस दिखावे का बोलबाला रह गया है. दशकों से वामपंथ के समर्थन में रहे ईसाई और मध्यमवर्गीय लोग अब वामपंथी पार्टियों से अलग हो रहे हैं.

भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला है केरल

भारत विविधताओं का देश है. यह विविधताएं सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक तीनों स्तर पर हैं. राजनीतिक स्तर पर देखें तो उत्तर भारत में बैठकर दक्षिण भारत की राजनीति का अंदाजा लगाना मुश्किल है. ऐसी ही स्थितियां देश के हर राज्यों में हैं. चुनावी माहौल में चौथी दुनिया की यह कोशिश है कि अपने हिंदी पट्टी के पाठकों को गैर हिंदी भाषी राज्यों के राजनीतिक माहौल से अवगत कराए. इसी कड़ी के पहले अंक में आइए समझते हैं दक्षिण भारतीय राज्य केरल का राजनीतिक परिदृश्य...

नीरज सिंह

केरल को भारत की राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है. भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर गौर करें तो इस राज्य ने कई ऐसे राजनीतिक बदलावों से देश को पहली बार रूबरू करवाया. चुनाव के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी का सत्ता में आना हो, विभिन्न पार्टियों के मोर्चों का गठन हो या फिर देश में पहली बार इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो. लेकिन इन कई स्थापनाओं के बावजूद केरल का चुनावी गणित उन्हीं राजनीतिक दांव-पेच के बीच चलता है जिनसे देश के अन्य राज्य दो-चार होते ही रहते हैं. हालांकि केरल देश का सबसे साक्षर राज्य है, इसलिए आम तौर यह समझा जाता है कि यहां की राजनीतिक व्यवस्था उत्तर भारतीय राज्यों की तरह जाति और धर्म के आधार से परे होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. इसलिए केरल की राजनीति को समझने के पहले यहां की सामाजिक व्यवस्था को समझना होगा. तकरीबन 90 प्रतिशत साक्षरता और 50 के दशक में ही जाग चुकी राजनीतिक चेतना के बावजूद भी केरल में जाति और समुदाय के आधार पर ही वोट पड़ता है. इसे वैसे ही समझिए जैसे उत्तर भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश-बिहार व मध्य प्रांत के मध्यप्रदेश व राजस्थान में होता है.

जातीय आधार पर केरल में अल्पसंख्यकों के दो बड़े समूह हैं. हालांकि, इन दोनों ही समुदायों को मिला दिया जाए तो ये वहां की आबादी का बहुसंख्यक के करीब पहुंच जाते हैं. ईसाइयों की आबादी 19 फीसदी है, जबकि मुसलमान 23 फीसदी हैं. ईसाइयों में भी बंटवारा है और वहां बड़ी जाति और प्रभावी सीरियल समुदाय में लोकतांत्रिक मोर्चा को भारी समर्थन मिलता है, लगभग तीन चौथाई. शेष ईसाइयों का वोट लगभग बराबर-बराबर दो हिस्सों में बंटता है और दोनों मोर्चों को मिलता था. मुसलमानों में भी जातिगत वर्गीकरण है, लेकिन शेष भारत की ही तरह वोट के मामले में वे आमतौर पर एकजुट रहते हैं. वे कम्युनिस्टों को वोट नहीं देते. उनमें दो तिहाई से लेकर तीन चौथाई वोट लोकतांत्रिक मोर्चा को जाते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल है. और यह समीकरण केरल की राजनीति में शुरुआती दौर से ही है, यही वजह है केरल के पहले मुख्यमंत्री ईएमएस नंबूदरीपाद ने स्वयं यह बात स्वीकारी थी कि केरल में वाम मोर्चा को दोनों अल्पसंख्यक समुदायों का समर्थन नहीं मिलता. यही वजह है कि अगर वामपंथी राजनीति को आधार बनाकर देखें तो केरल की राजनीति और पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा फर्क दिखता है.

वामपंथी पार्टियां वास्तव में समूचे देश में उन्हीं दलितों और पिछड़ी जातियों के समर्थन के भरोसे हैं, जो जातियां किसी न किसी रूप में अपने अस्तित्व व स्वाभिमान की रक्षा के लिए आंदोलनरत रही हैं. केरल में वाम मोर्चा को मुख्यत: उन दलित और पिछड़ी जातियों का समर्थन मिलता है, जिन्होंने समाज सुधार और आत्मसम्मान आंदोलनों के चलते अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया है. ऐसा सबसे बड़ा समूह है इझवा लोगों का, जो पारंपरिक रूप से ताड़ी निकालने का काम करते रहे थे, लेकिन अब वे आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही आधार पर सशक्त भूमिका में आगे आए हैं. जैसा कि पूरे देश में हो रहा है कि सामुदायिक आधार पर जिस पार्टी को दलितों का बड़ा समर्थन मिल रहा है, अगड़े वर्ग मानसिक तौर तो उस पार्टी के खिलाफ ही रहते हैं, भले ही दिखावे और राजनीतिक लाभ के लिए साथ आ जाएं. जैसे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग भले ही मायावतीनीत बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़कर जीतकर आएं और मंत्री बने, लेकिन जब मायावती उनसे अपने कमरे में चप्पल निकाल कर आने को कहती हैं तो इसे अगड़े नेता मुद्दा बनाते हैं. केरल में ऊंची जाति के लोग इसी भावना से ग्रस्त होते दिखने लगे हैं. वाममोर्चा चूंकि दलितों के समर्थन में हैं, इसलिए जाति व्यवस्था में अगले पायदान पर खड़े नायर जोकि राज्य की कुल आबादी का 15 फीसदी हैं, वे वाममोर्चा के खिलाफ ही वोट देते हैं. यही वजह है कि हाल के चुनावों में भाजपा को इसी समुदाय का समर्थन सबसे ज्यादा मिला है. त्रिवेंद्रम और कसारगोड जहां नायरों व दूसरी अगड़ी जातियों का प्रतिशत ज्यादा है, वहां पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है.

सामाजिक व्यवस्था के बाद केरल की राजनीति को समझने के लिए वहां की पार्टीगत राजनीति और उनकी विचारधारा को समझकर ही प्रांत की राजनीति पर कोई राय बनाई जा सकती है. केरल राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य है और शायद इसी वजह से लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता भी झेलता रहा है. 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, तब आसपास के मलयालम बोलने वाले इलाक़ों को जोड़कर केरल का निर्माण किया गया. देश राजनीतिक रूप से सशक्त हो रहा था और केरल में यह मजूबती ईएमएस नंबूदरीपाद, एके गोपालन और टीएम वर्गीस जैसे नेताओं के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी. नवगठित केरल राज्य विधानसभा का पहला चुनाव मार्च, 1957 में हुआ. ईएमएस नंबूदरीपाद पहले मुख्यमंत्री बने. यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी गई पहली वामपंथी सरकार थी. चूंकि दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा था, इसलिए जाहिराना तौर पर वहां वामपंथी नेतृत्व का आगमन हुआ. लेकिन चूंकि देश के अन्य हिस्से में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, इसलिए दूसरे ही चुनाव में, जोकि मध्यावधि चुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करके पी टी पिल्लई के नेतृत्व में सरकार बनाई. लंबे दौर तक केरल राजनीतिक अस्थिरता का सामना करता रहा. राज्य बनने की शुरुआत से लेकर 1970 तक पांच बार चुनाव हो चुके थे और अब तक किसी भी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था. 1970 अच्युत मेनन के नेतृत्व में केरल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार सरकार पांच साल चली.

80 के दशक तक वामपंथियों को यह अहसास

होने लगा था कि केरल में अगर वामपंथी विचारधारा को जीवित रखना है तो गठबंधन की राजनीति को प्रमुखता देनी होगी. इसी सोच के साथ वामपंथी दलों ने सात राजनीतिक दलों को मिलाकर पहली बार गठबंधन बनाया, जिसे लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ़) कहा गया. हालांकि, यह गठबंधन भी केवल एक साल ही चल पाया और कांग्रेस भी गठबंधन की राह पर चलते हुए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ़) नाम से चुनाव लड़ी और बहुमत हासिल किया. तबसे लेकर आज तक यही दोनों घटक केरल की राजनीति निर्धारित करते आए हैं.

हालांकि, जैसे-जैसे सामाजिक परिस्थितियां बदलीं, धीरे-धीरे राजनीतिक स्तर पर भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं. चुनाव परिणामों पर गौर करें तो मजहबी दल मसलन मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस अब अपनी ही जमात के लोगों को खो रहे हैं. जबकि एक वक्त था कि भाषायी स्तर पर बेहद सजग केरल के मुसलमानों ने उस व्यक्ति को भी सांसद चुन लिया, जिसने साफ तौर पर कहा था कि उसकी मातृभाषा मलयालम नहीं अरबी है. उधर केरल कांग्रेस भी ईसाइयों की ओर अपना झुकाव ज्यादा दिखा रही है.

इसकी प्रतिक्रिया का भाव अब हिंदू मतदाताओं में भी उभर रहा है. यही वजह है कि यूनाइटेड डेमोटिक फ्रंट की सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय के बढ़ते दबदबे के कारण हिंदुओं के पिछड़े वर्गों में हताशा का माहौल बनने लगा, जबकि उनकी आबादी राज्य की कुल आबादी का 40 फीसदी है, लेकिन वे अपने आपको राजनीति और सत्ता में हाशिए पर जाता देख रहे हैं. इसके कारण हिंदू पिछड़े वर्गों की सबसे बड़ी जाति इझावा के संगठन एसएनडीपी (श्री नारायण धर्म परिपालना) योगम ने एक राजनैतिक पार्टी का गठन कर डाला है और उसका नाम रखा केरल पीपुल्स फ्रंट.

अधिसंख्य मुस्लिम मतदाता जोकि पहले एकमत से मुस्लिम लीग को ही वोट डालते थे, उन्होंने विकल्प खुले रखने शुरू कर दिए हैं. ईसाई समाज अब भी अपनी पारंपरिक सोच को बदलते हुए अब केरल कांग्रेस के बजाए भाजपा समर्थित राजग उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रहे हैं. दरअसल, अब केरल में कांग्रेस और माकपा- दोनों ही पार्टियों के पास शक्तिशाली नेतृत्व की कमी है जिसकी परिणति इस तरह के मतभेद की ओर ले जा रही है.

ऊपरी तौर पर जिस तरह से केरल एक समृद्ध और साक्षर राज्य की छवि रखता है, राजनीतिक तौर पर वह उतना ही खोखला होता जा रहा है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन (यूडीएफ) और मार्क्सवादी गठबंधन (एलडीएफ) के बीच राजनीतिक उठापटक में राज्य के असली मुद्दे खो गए हैं और बस दिखावे का बोलबाला रह गया है. राज्य में समृद्ध लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर की अनदेखी की वजह से इस संभ्रांत वर्ग के पास आगे बढ़ने के अवसर या तो बहुत कम हो गए हैं या बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं. यही वजह है कि दशकों से वामपंथ के समर्थन में रहे ईसाई और मध्यमवर्गीय लोग अब वामपंथी पार्टियों से अलग हो रहे हैं. कितना अजीब है लगता है कि जो राज्य 99 फीसद शिक्षित है, वहां शहरी बेरोज़गारी 15 फीसदी है, जो कि भारत के सामान्य औसत से तीन गुना अधिक है. वामपंथी सरकार हमेशा ही विदेशी या देश के अन्य राज्यों से निवेश का विरोध करती रही है. कामागर यूनियनें, जिन्हें वामपंथ ने मज़दूरों के अधिकारों को लेकर उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए बढ़ावा दिया, अब वामपंथ और बाक़ी विचारधाराओं के बीच हो रहे राजनीतिक युद्ध का औज़ार बनकर रह गई हैं. इसलिए यहां बंदी और हड़ताल का बोलबाला है.

वास्तव में ऐसी ही व्यवस्था अलग-अलग रूपों में हर राज्यों में है, जिसमें राजनीतिक दांव-पेच के बीच बस आम आदमी ही पिस रहा है, केरल में भी ऐसा हो रहा है. इसको लेकर ताज्जुब इसलिए होता है, क्योंकि जो वामपंथी विचारधारा बुर्जुआ का विरोध करती है, वही दल सर्वहारा बनकर केरल के आर्थिक तंत्र को खोखला कर रहे हैं, जिसका कलंक राजनीति के माथे पर लग रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार में उपेक्षित हैं क़ानून के रखवाले

नीतीश सरकार जिस बेहतर क़ानून व्यवस्था को अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित करती है, उसमें विशेष सहायक पुलिस यानी सैप जवानों का बेहद अहम योगदान है, लेकिन आज स्थिति यह है कि इन जवानों को उपेक्षित कर दिया गया है. जवानों में वेतनमान और अन्य सुविधाओं को लेकर असंतोष है. कार्यस्थल पर उनके साथ होने वाला भेदभाव भी उन्हें आहत करता है. रैली और सम्मेलन कर जवानों द्वारा अपनी मांगें रखने के बाद भी नीतीश सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है.

शशि सागर

जब पहली बार नीतीश की सरकार बनी तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सूबे के लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाना और आम लोगों के मन से अपराधियों के ख़ौफ़ को निकालना. यह हुआ भी. सरकार, सुशासन की सरकार कहलाई. बेहतर विधि-व्यवस्था पर इतराते हुए खुद मुख्यमंत्री भी कहा करते थे कि आकर देखिए हमारे पटना में रात के बारह बजे भी लड़कियां डाक बंगला चौराहे पर आइसक्रीम खाते हुए मिल जाएंगी. तो जिस सुशासन पर सत्तादल के नेता-कार्यकर्ता कॉलर खड़ी करते हैं, उसे बनाने में अहम भूमिका रही है सैप (स्पेशल ऑग्जिलीएरी पुलिस) जवानों की. सैप जवान यह स्वीकारते हैं कि हमारी ही वजह से बिहार में आज सुशासन का माहौल है. सैप जवानों की हनक यह रही है कि उन्हें देखते ही असामाजिक तत्वों के हाथ-पांव फूलने लगते थे. अपराधी सैप जवानों को देखते ही भागने लगते हैं, लेकिन आज यही सैप जवान उपेक्षा में जीने को विवश हैं.

बिहार में पुलिस बल की कमी तो थी ही, अभी भी है. ऐसे में बेहतर लॉ एंड ऑडर के लिए नीतीश सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को सैप के रूप में बहाल किया. सरकार को कम पैसे और सीमित संसाधन खर्च करके बेहतर और प्रशिक्षित जवान मिल गए. सैप की पहली बहाली 2006 में की गई. अब तक 6 से 7 हजार सैप जवानों को बहाल किया जा चुका है. तब इनकी सैलरी 10 हजार तय की गई थी. विडंबना देखिए कि छठा वेतनमान लागू होने के बाद भी इनके वेतन और सुविधाओं में बढ़ोत्तरी नहीं हुई. सैप जवानों की भर्ती का मुख्य उद्देश्य था कि उनकी सेवा नक्सल प्रभावित इलाकों में ली जाएगी या फिर उन्हें आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जाएगा. लगभग एक साल तक ऐसा हुआ भी. उन्हें रिजर्व पुलिस के रूप में रखा गया, लेकिन अब जिला पुलिस के तर्ज पर उनका इस्तेमाल किया जाने लगा है. जितने भी सैप जवानों से मुलाकात होती है, वे इस बात से आहत दिखते हैं कि अब उन्हें अधिकारियों के घर की रखवाली में लगाया जाता है. स्थिति यह है कि अधिकारियों के बच्चों को स्कूल पहुंचाना, उनके बगीचे में पानी डालना और शाम के समय उनके घर की सब्जी लाने जैसा काम भी अब बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी उनसे लेने लगे हैं.

यह आजीविका की मजबूरी ही है कि अनुशासित और सम्मानित जिंदगी जी चुके ये सेना के जवान आज उपेक्षित हैं. फुलवारीशरीफ जेल परिसर में कुछ सैप जवानों से मुलाकात होती है. अन्य बातों को अगर छोड़ भी दें तो न्यूनतम सुविधा भी इन जवानों को नसीब नहीं है. एक बड़े से हॉल में बीस-पच्चीस चौकी लगा दी गई है, और हर जवान को एक-एक चौकी आवंटित कर दी गई है. जिन्हें चौकी नहीं मिली है वे जमीन पर ही अपना बिस्तर लगाकर रात काटते हैं. ये जवान इसी एक चौकी के दायरे में अपना खाना भी खुद बनाते हैं और अपने लिए बिजली और पंखे की व्यवस्था भी खुद ही करते हैं. छत्रपाल सिंह राठौर 2006 से ही सैप में हैं. कहते हैं कि हमारी बदौलत ही ये सुशासन बाबू कहलाते हैं और देखिए कि राजधानी के सैप जवानों की क्या स्थिति है. जो जवान दुर्गम क्षेत्र में होंगे, उनकी यह व्यवस्था कितना ख्याल रखती होगी, आप अंदाजा लागा सकते हैं. सैप के जवानों के साथ ही सेना के ही सेवानिवृत्त जेसीओ, कुक, ड्राइवर आदि की बहाली हुई. बिहार पहला राज्य बना जिसने सेवानिवृत सैनिकों को बहाल किया था, इसके बाद कई राज्यों ने इसका अनुकरण भी किया. शुरुआत में व्यवस्था यह बनाई गई थी कि इन सैप जवानों की अलग सेल होगी और ये जवान जेसीओ को रिपोर्ट करेंगे. उनके कुक और ड्राइवर भी अलग ही होंगे. फिलहाल झारखंड और उड़ीसा में यही व्यवस्था है, लेकिन यह बात बिहार में कागज पर ही रह गई. स्थिति यह है कि जेसीओ से लेकर कुक और ड्राइवर तक बिहार पुलिस के बड़े अधिकारियों की सेवा में लगा दिए गए हैं.

पिछले दिनों बिहार के सैप जवान विभिन्न मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर चले गए थे. उन्होंने राजधानी पटना में एक रैली भी की और कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो हम अपने-अपने हथियार सौंप कर घर वापस चले जाएंगे. सूत्र बताते हैं कि इसके बाद बिहार पुलिस के बड़े अधिकारियों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सैप जवानों की जगह पर बिहार पुलिस को ही तैनात किया जाए, लेकिन दाल गली नहीं. बिहार पुलिस के जवानों ने कहा कि सिर्फ विधि-व्यवस्था के लिए हैं, सैप जवानों का काम हमसे नहीं

होगा. हम सक्षम नहीं हैं. तब आनन-फानन में आकर सैप जवानों की कुछ मांगों को मान लिया गया. जवानों का वेतन दस हजार से बढ़कर बारह कर दिया गया और जेसीओ का वेतन 15 हजार कर दिया गया. इनकी छुट्टी भी बढ़ाकर बीस से चालीस दिन कर दी गई. भर्ती के वक्त कहा गया था कि इन्हें बिहार पुलिस की तरह ही वर्दी भत्ता चार हजार दिया जाएगा, लेकिन अबतक इन्हें 2600 ही मिलता रहा. पांच साल बाद अब इनके वर्दी भत्ते को बिहार पुलिस के समतुल्य किया गया है. कुल मांगों के साथ सैप के जवान हड़ताल पर गए थे. सारी मांगें नहीं मानी गई है. सैपर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष धर्मदेव सिंह कहते हैं कि अगर हमारी सभी मांगें नहीं मानी गईं और और हमारे साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार बंद नहीं हुआ तो हम फिर से आंदोलन को मजबूर होंगे. भारतीय नौ सेना से सेवानिवृत्त हुए एक जवान पटना के ही एक कारा में कक्षपाल हैं, कहते हैं कि जेल में बिहार पुलिस के कक्षपाल और अधिकारियों के द्वारा हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया जाता है. यह कहकर हमारा मजाक उड़ाया जाता है कि हमें भाड़े पर लाया गया है. प्रदेश अध्यक्ष धर्मदेव सिंह सैप के जवान और बिहार पुलिस के बीच बेहतर सामंजस्य के अभाव की भी बात करते हैं. पिछली जुलाई में औरंगाबाद के गोह थाना पर नक्सलियों ने हमला किया था. इस हमले में सैप के तीन जवान शहीद हो गए थे. धर्मदेव कहते हैं कि कई बार औरंगाबाद जिला पुलिस मुख्यालय को कहा गया था कि यहां मोर्चा बनाने की आवश्यकता है, नक्सली हमले हो सकते हैं. लेकिन हमारी बातों पर अमल नहीं किया गया और जिला पुलिस की लापरवाही की वजह से हमारे तीन साथी शहीद हुए. कितने सैप जवानों को अबतक मुआवजा मिला है, इस पर धर्मदेव कहते हैं कि हमने आरटीआई के तहत इसकी जानकारी छह महीने पहले विभाग से मांगी थी कि अब तक बिहार में कितने सैप के जवान नक्सली हमले में शहीद हुए और कितनों को मुआवजा मिला है, लेकिन अभी तक विभाग ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है. साथ ही यह भी बताते हैं कि बीस लाख मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन विभाग दोहरा रवैया अपनाते हुए कहता है कि यह सिर्फ माओवादी घटना में मिलेगा, किसी अन्य वजह से हताहत हुए तो क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी. कुछ सैप जवान तो यह भी बताते हैं कि पुलिस अधिकारी हमें बेवजह प्रताड़ित भी करते हैं. शाम के समय अगर कहीं सब्जी लाने या चाय पीने भी चले गए तो अनुपस्थित मान लिया जाता है. इतना ही नहीं, ड्युटी पर जाने के वक्त कमान भी नहीं दिया जाता है. अगर कमान मांगा जाता है तो अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर अनुबंध रद्द कर देने की धमकी तक दी जाती है. सूत्र बताते हैं कि इन्हीं सब उपेक्षाओं और पक्षपातपूर्ण रवैये की वजह से अबतक 70 से 80 सैप जवान नौकरी छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सैप जवानों की हो रही उपेक्षा से शायद अंजान हैं. तभी तो पिछले जनता दरबार में उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जिसने भूतपूर्व सैनिकों की सेवा लेनी शुरू की है. और हमने सेवानिवृत सैनिकों के लिए जितना किया है, किसी ने नहीं किया और हमें इसके लिए किसी से प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन इसे मुख्यमंत्री का भ्रम ही कहेंगे. अभी गत जून माह में ही भूतपूर्व सैनिक सेवा परिषद की बैठक हुई थी. इसमें भी राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया था कि पूर्व सैनिक, उनकी विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए बिहार सरकार कुछ भी नहीं कर रही है. सूबेदार एसजीत शर्मा ने इस बैठक में मांग की थी कि बिहार में मौजूद सैनिक कल्याण निदेशालय को एक अलग विभाग का दर्जा दिया जाए. साथ ही यह आरोप भी लगाया गया कि बिहार सरकार हमारी समस्याओं के निदान के लिए तत्पर नहीं दिखती है.■

feedback@chauthiduniya.com

पानी की कमी के कारण अब यहां के अधिकतर किसानों ने मोरारका फाउंडेशन की कोशिशों से ट्रे-कल्टीवेशन को अपनाना शुरू कर दिया है. बलेरिया गांव में ही नेमीचंद महला पुत्र भाना राम भी रहते हैं, जो एक जागरूक किसान हैं. उनके पास अपनी सफलता की कई कहानियां हैं.

ट्रे-कल्टीवेशन तकनीक

किसानों में जगाती उम्मीद

मोरारका फाउंडेशन ने ट्रे-कल्टीवेशन की नई तकनीक के सहारे खेती को जो आयाम दिए हैं, उससे किसानों में एक नई उम्मीद जगी है. आज खेती करना आसान नहीं रह गया है. महंगाई और किसानों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच किसानों के लिए यह तकनीक जहां फ़ायदेमंद साबित हो रही है, वहीं तेज़ी से बढ़ती हुई शहरों की आबादी की आवश्यकताएं भी इस नई तकनीक से पूरी हो रही हैं.

डॉक्टर क़मर तबरेज़

ज़माना तेज़ी से बदल रहा है. ऐसे में भला हमारे देश का किसान स्वयं को दूसरों से कैसे पीछे रख सकता है. किसानों के लिए आज सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि सरकार की अनदेखी के कारण इनके खेत सूख रहे हैं. सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं है. किसान जो फसलें अपने खेतों में पैदा करते हैं, उनका उन्हें उचित मुआवज़ा नहीं मिल रहा है. सरकार की नीतियों से विवश होकर देश के अधिकतर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं. किसान भी परिवर्तन के इस दौर में स्वयं को ज़माने की रफ्तार के अनुसार चलाना चाहता है, लेकिन उसे चारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है. ऐसे में मोरारका फाउंडेशन ने उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण पैदा की है. ट्रे-कल्टीवेशन की नई तकनीक उनके लिए जहां फ़ायदेमंद साबित हो रही है, वहीं तेज़ी से बढ़ती हुई शहरों की आबादी की आवश्यकताएं भी इस नई तकनीक से पूरी हो रही हैं. कैसे? जानते हैं इस रिपोर्ट में...

क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन 3 लाख 42 हज़ार 239 किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस राज्य का लगभग एक तिहाई हिस्सा रेगिस्तान है. यहां के किसानों को खेतीबाड़ी के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है. राजस्थान के बारे में हमसब जानते हैं कि देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में यहां के लोग पानी की कमी की मार सबसे अधिक झेल रहे हैं. किसानों को अगर समय पर पानी ही नहीं मिलेगा तो वह भला खेती कैसे करेंगे और फिर हमारे घरों तक अनाज कैसे पहुंचेगा. अच्छी बात यह है कि मोरारका रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े वैज्ञानिक राजस्थान के किसानों को इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं कि पानी का कम से कम प्रयोग करके अधिक से अधिक फसल कैसे उगाई जाए. ये वैज्ञानिक हाइड्रोपोनिक तकनीक, ट्रे-कल्टीवेशन, ड्रिप सिस्टम आदि के द्वारा इन किसानों को खेती करना सिखा रहे हैं, जिनमें पानी का कम से कम प्रयोग होता है.

खेतों में सब्ज़ियां उगाना अब कल की बात हो चुकी है. देश के अधिकतर क्षेत्रों में पानी की ज़बरदस्त क़िल्लत के कारण किसानों के पास अब अपने खेतों में सब्ज़ियां उगाना महंगाई का सौदा साबित हो रहा है. यही कारण है कि अब अधिकतर किसान ट्रे में सब्ज़ियां उगाने को तेज़ी से अपना रहे हैं. यह तकनीक उन्हें मोरारका फाउंडेशन के वैज्ञानिकों की ओर से एक उपहार के रूप में मिली है. इस तकनीक से सब्ज़ियां उगाकर यह किसान न केवल आर्थिक रूप से मज़बूत बन रहे हैं, बल्कि शहरों के ऐसे लोग भी ट्रे-कल्टीवेशन की तकनीक को अपनाने की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है. ट्रे-कल्टीवेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि कोई भी आदमी अपने घर की छत पर ट्रे रखकर इसमें सब्ज़ियां उगा सकता है और अपने लिए अधिक सब्ज़िया प्राप्त कर सकता है.

इस तकनीक में प्लास्टिक की ट्रे में मिट्टी रखकर सब्ज़ियां उगाई जाती है. इससे कम लागत में गुणवत्ता वाली सब्ज़ियां पैदा की जा सकती हैं. इसके लिए सबसे पहले ट्रे में ग्रीन नेट और जूट बिछाकर इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला जाता है, फिर इसमें बीज या पौधे लगाते हैं. इसके बाद ट्रे में एग्री इनपुट्स और पौष्टिक तत्वों का समय-समय पर छिड़काव किया जाता है. यह तकनीक ऐसी सब्ज़ियां उगाने के लिए अधिक कारगर है, जिनका प्रयोग हम अपने प्रतिदिन के खाने में करते हैं. जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, करेला, ककड़ी, ग्वार फली आदि. इन सभी सब्ज़ियों को बड़ी आसानी से डेढ़ ईंच गहरी मिट्टी में उगाया जा सकता है. इस प्रकार एक किलो सब्ज़ी उगाने में केवल 30 से 70 लीटर पानी की ही आवश्यकता होती है, जबकि खेत में इतनी ही सब्ज़ी उगाने में 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है. इसमें कीटनाशक दवाओं के छिड़काव की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ट्रे के ऊपर नेट लगा देने से कीड़े-मकोड़े सब्ज़ियों को नुक़सान नहीं पहुंचा पाते. इस प्रकार फसल में साइकिलिंग की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ट्रे के अन्दर एक सब्ज़ी तैयार होते ही आप इसमें कोई दूसरी सब्ज़ी लगा सकते हैं.

ट्रे-कल्टीवेशन की सबसे बड़ी ख़ूबी यह है कि इसके लिए आपको किसान नहीं बनना पड़ेगा, बल्कि आप कोट पैंट, टाई लगाकर भी अपने घर की छत या बॉलकनी में इस प्रकार सब्ज़ियां उगा सकते हैं. मोरारका फाउंडेशन ने सबसे पहले 2011 में दिल्ली में एक प्रदर्शनी लगाकर इस तकनीक को दुनिया के सामने पेश किया था. यह तकनीक जब गांव में पहुंची तो किसानों ने इसे हाथों-हाथ लिया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि किसान खेतों की तुलना में ट्रे-कल्टीवेशन के द्वारा कम लागत पर अधिक सब्ज़ियां उगा कर अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं.

राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के नवलगढ़ क़स्बे के एक गांव बलेरिया में रहने वाले अधिकतर लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं. यहां के किसानों के पास ज़मीनें तो हैं, लेकिन फसलों की सिंचाई के लिए उनके पास पानी नहीं है, क्योंकि राजस्थान का यह क्षेत्र आधा रेगिस्तान है. पानी की इसी कमी के कारण अब यहां के अधिकतर किसानों ने मोरारका फाउंडेशन की कोशिशों से ट्रे-कल्टीवेशन को अपनाना शुरू कर दिया है. बलेरिया गांव में ही नेमीचंद महला पुत्र भाना राम भी रहते हैं, जो एक जागरूक किसान हैं. उनके पास अपनी सफलता की कई कहानियां हैं. नेमीचंद बताते हैं कि 1984 में एम कॉम करने के बाद उन्होंने अपने ख़ानदानी पेशे खेती को अपनाया, क्योंकि बचपन से ही उनकी रूचि खेती में थी. उनके कुल 65 बीघा ज़मीन है. कृषि क्षेत्र में मोरारका फाउंडेशन की नई-नई खोजों से प्रभावित होकर नेमीचंद ने 2005 से ही ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत कर दी और फाउंडेशन के वैज्ञानिकों की मदद से हर्बल कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, एनएसडील कंपोस्ट, वमी वॉश, हर्बल स्प्रे, जीव अमृत और नमी की फली तैयार करना सीखा और उनका प्रयोग अपने खेतों में करना शुरू किया. इन सभी उपायों से नेमीचंद ने यह सीखा कि मवेशियों के बिना खेती नहीं हो सकती. लिहाज़ा, उन्होंने मवेशियों को पालने पर भी ज़ोर दिया और इसी का नतीजा है कि आज उनके पास 21 मवेशी हैं. इन मवेशियों की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि खाद और कीड़े मार स्प्रे बनाने में इन्हीं मवेशियों के गोबर और पेशाब का अधिक प्रयोग होता है. इन चीज़ों के प्रयोग से नेमीचंद के खेती करने के तरीक़े में एक प्रकार की क्रांति आई और इसका आर्थिक लाभ किसानों को ख़ूब हुआ.

मोरारका फाउंडेशन से ही प्रभावित होकर नेमीचंद ने साल 2011 में ट्रे-कल्टीवेशन की नई तकनीक से सब्ज़ियां उगानी शुरू कर दीं. नेमी चंद, चूंकि ट्रे-कल्टीवेशन से पहली बार जुड़े थे, इसलिए उनके प्रोत्साहन के लिए मोरारका फाउंडेशन की ओर से 2011 में उन्हें पूरी तकनीक से लैस 96 ट्रे उपलब्ध कराए गए, जिसमें लोहे के स्टैंड, हरा व सफेद नेट कवर और जूट शामिल थे. इन सब सामाग्री के एवज़ में नेमीचंद से बतौर सिक्योरिटी 2000 रुपये जमा कराए गए. इस सिस्टम को लगाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक की ट्रे में नीचे की ओर ग्रीन नेट बिछाया गया और इसमें एक किलो कोकोपिट (नारियल का बुरादा) और 12 किलो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया गया. इसके बाद इन ट्रेनों में बीजों और पौधों को लगाया गया. किसान नेमी चंद ने पहले सीज़न यानी अगस्त 2011 में अपने कुल 96 ट्रे में पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मिर्च, भिंडी, पालक, नागोरी मेथी, बेंगने, चोला लोकी और तोरई के कुल 204 पौधे लगाए, जिनसे इसे जनवरी 2012 में 146 किलो सब्ज़ियां प्राप्त हुईं. इन सब्ज़ियों को बाज़ार में बेचकर नेमीचंद ने 4743 रुपये कमाए. इस प्रकार देखा जाए तो नेमीचंद ने मोरारका फाउंडेशन के पास सिक्योरिटी के रूप में जो 2 हज़ार रुपये जमा किए थे, उसे निकालकर इसे पहले सीज़न में इन सब्ज़ियों से 2743 रुपये का मुनाफ़ा हुआ.

पांच महीने में ही इतना अधिक आर्थिक लाभ देखकर नेमीचंद का हौसला बढ़ा और उसने अगले सीज़न में भी ट्रे-कल्टीवेशन की तकनीक से सब्ज़ियां उगाने का निर्णय कर लिया, लेकिन किसान को पहले सीज़न में एक बड़ी समस्या यह आई कि ट्रे में जो पानी दिया जाता था, वह फौरन ही बह जाता था, इसलिए बार-बार सिंचाई की आवश्यकता होती थी. इस समस्या को हल करने के लिए किसान ने आरंभिक उपायों में कुछ परिवर्तन किया. ट्रे में नीचे कॉकपिट (नारियल का बुरादा) की जगह पर दोमट मिट्टी का प्रयोग किया गया. नेमीचंद इस बीच समय-समय पर मोरारका फाउंडेशन के वैज्ञानिकों से भी सलाह लेते रहे. इसके अलावा उन्होंने अधिक ध्यान पत्ते और फूल वाली सब्ज़ियों पर दिया, जो कम समय में तैयार हो जाती हैं. दूसरे सीज़न यानी फरवरी 2012 में नेमीचंद ने अपने 96 ट्रे में कुल 196 पौधे लगाए. ये पौधे फूलगोभी, बैंगन, पालक, भिंडी, मिर्च, टमाटर, हरा धनिया, शिमला मिर्च, खीरा, टिंडसी और पत्ता साही के थे. इसी प्रकार जुलाई 2012 तक नेमीचंद को ट्रे-कल्टीवेशन से कुल 113.8 किलो सब्ज़ियं प्राप्त हुईं, जिन्हें बाज़ार में बेचकर उन्होंने 5254 रुपये कमाए.

इस प्रकार देखा जाए तो ट्रे-कल्टीवेशन की तकनीक को अपनाने से नेमीचंद की आमदनी में हर 6 माह बाद तेज़ी से बढ़ोत्तरी होने लगी, जिससे उनका जीवन समृद्ध हुआ. इस समय नेमीचंद की यही कोशिश है कि वह नवलगढ़ क़स्बे में रहने वाले इन सभी घरों तक अपनी सब्ज़ियां पहुंचाएं, जिनके पास सब्ज़ियां उगाने के लिए अपने खेत नहीं हैं. जो लोग नेमीचंद के द्वारा सप्लाई की गई सब्ज़ियों का प्रयोग करते हैं, उन लोगों का भी यही कहना है कि ऑर्गेनिक विधि से उगाई गई इन सब्ज़ियों का स्वाद रासायानिक विधि से उगाई गई सब्ज़ियों के मुक़ाबले बहुत बेहतर होता है और इन सब्ज़ियों के प्रयोग से इंसान के स्वास्थ्य भी ठीक रहता है.

मोरारका फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक मुकेश गुप्ता बताते हैं कि ज़मीन में धुरे से (नाला बनाकर) सिंचाई करके एक किलो अनाज उगाने में 200 लीटर पानी ख़र्च होता है, जबकि फव्वारे से खेती करने में 1400 लीटर पानी से एक किलो अनाज पैदा होता है. मुकेश गुप्ता यह भी बताते हैं कि ज़मीन में धुरे से सिंचाई करके एक किलो सब्ज़ी उगाने में 4000 लीटर पानी, फव्वारे से 2400 लीटर पानी और ड्रिप सिस्टम से एक किलो सब्ज़ी पैदा करने में 1400 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इन सबके मुक़ाबले ट्रे-कल्टीवेशन से काफी पानी बचाया जा सकता है. यही कारण है कि शहरों में भी अब लोग बड़ी तेज़ी से ट्रे-कल्टीवेशन से सब्ज़ियां उगाने की ओर आकर्षित हो रहे हैं. गांव में ट्रे- कल्टीवेशन से कुछ ही दिनों में यह क्रांति देखने को मिलेगी कि लोग कोट-पैंट और टाई लागकर खेती करते हुए दिखाई देंगे. अब खेती करना केवल अनपढ़ किसानों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पढ़े-लिखे लोग भी इस ओर तेज़ी से आकर्षित होंगे. एक ट्रे के अन्दर एक साल में औसत 4 किलो ग्राम सब्ज़ी उगाई जा सकती है और प्रत्येक किसान को एक ट्रे में सब्ज़ी उगाने से लगभग 60-70 रुपये की कमाई हो सकती है. मोरारका फाउंडेशन ने ट्रे-कल्टीवेशन की शुरुआत 30-40 किसानों से की थी, लेकिन अब बहुत से किसान अपने तरीक़े से इसमें नये परीक्षण कर रहे हैं. यह किसान अब ट्रे-कल्टीवेशन से सब्ज़ियों के बीज भी उगाने लगे हैं. जिस प्रकार जैविक खेती की शुरुआत करने का सेहरा नवलगढ़ को जाता है, शीघ्र ही ट्रे-कल्टीवेशन में भी सफलता का सेहरा नवगलगढ़ के नाम ही जाएगा. ■

tabrez@chauthiduniya.com

नेमी चंद (किसान)

सभी फोटो-प्रभात पांडेय

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

मोदी असली मुद्दों से भटक गए हैं

भारतीय जनता पार्टी ने बीते 13 सितंबर को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया. भाजपा 1970 के समय से ही कांग्रेस के ख़िलाफ़ गला फाड़ रही है. तब बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर इस बात का आरोप लगाती थी कि इंदिरा गांधी व्यक्तिगत रूप से ख़ुद को प्रभावशाली साबित कर रही हैं, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ख़तरा है. अब भारतीय जनता पार्टी भी उसी दौर में वापस लौट आई है. पार्टी के नेता पार्टी की नीतियों या विचारधारा की कोई बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमले कर रहे हैं. जो भी हो, यह उनका अपना मसला है, लेकिन पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार चुने जाने के बाद सबसे पहले मोदी ने क्या किया? उन्होंने रेवाड़ी में पूर्व-सैनिकों की एक रैली आयोजित की. मोदी ने कहा कि चूंकि पहले ही उन्होंने यह वादा किया था, जो कि उन्हें पूरा करना ही था. यह विडंबना ही है कि जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वह यह नहीं समझता कि अगर वह यह संदेश दे रहा है कि वह देश को सेना और पुलिस के माध्यम से चलाना चाहता है, तो प्रशासन में राजनेताओं की क्या जरूरत? सेना और पुलिस तो पहले से ही अपना काम कर रही हैं. और अगर देश चलाने के लिए यह दोनों पर्याप्त हैं तो फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है? अगर ऐसा है तो फिर हमें प्रधानमंत्री की कोई जरूरत नहीं. हमें सांसदों की कोई जरूरत नहीं. और हमें विधायकों की कोई जरूरत नहीं. वास्तव में वे मुद्दे से हट रहे हैं. एक गैर-सैनिक राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य होता है कि वह जनता की भावनाओं को समझ सके और उनके लिए समाधान प्रस्तुत करे. उन्होंने उस रैली में कहा कि देश की सेना के माध्यम से मैं पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा. क्या इसके लिए हमें प्रधानमंत्री की जरूरत है? सेना प्रमुख यह क़दम ख़ुद ही उठा सकते हैं. हमें ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, जो यह कहे कि मेरी कोशिश रहेगी की पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य बनें, जिससे सेना पर भी दबाव न रहे. वास्तव में प्रधानमंत्री का कर्तव्य ही यही है, न कि यह कहना कि पाकिस्तान पर हमला कर दो. सेना को किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है. वास्तव में वे मुद्दों से भटक गए हैं. यही भाजपा का असली चेहरा है. वे एक ऐसे प्रधानमंत्री का चुनाव करना चाहते हैं, जो देश में हिंसा के बारे में बात करे. अभी उन्हें प्रधानमत्री पद की ज़िम्मेदारी मिली भी नहीं और उन्होंने हिंसा की बात शुरू कर दी. देश पहले से ही हिंसा की चपेट में है. देश पहले से ही पाकिस्तान, चीन और माओवादियों द्वारा फैलाई हिंसा की मार झेल रहा है. हमें ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जो उन्माद के इस माहौल को कम कर सके.

निश्चित रूप से मौजूदा सरकार असफल साबित हुई है. इसमें कोई शक नहीं है. यह बड़े दुर्भाग्य की बात है और मैं यह समझ सकता हूं, जब कोई यह कहता है कि पाकिस्तान आए दिन युद्ध-विराम का उल्लंघन करता है और हम कुछ नहीं करते. ऐसा क्यों है, यह भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए यह समझना मुश्किल है, क्योंकि वे ठेठ आएसएस-भाजपा संस्कृति का हिस्सा हैं. और यह संस्कृति कहती है कि हम विरोध के स्वरों की अनदेखी नहीं करेंगे. हम लोकतंत्र को बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम उन सभी को सबक सिखाएंगे, जो हमारा विरोध करेंगे, भले ही उनमें हमारे अपने लोग ही क्यों न शामिल हों. इसलिए जो भी कट्टर हिंदू नहीं है, वह अब मुश्किल में हैं. उनमें मैं भी शामिल हूं. निश्चित तौर पर मुसलमानों पर आने वाले दिनों में संकट रहेगा. ईसाइयों पर भी मुश्किलें आएंगी. यहां तक कि आम नागरिक, जो कि शांतिप्रिय है, वो भी मुश्किल में होगा, क्योंकि वह भाजपा के कट्टर राष्ट्रवाद का समर्थक नहीं है. मोदी रोटी-कपड़ा और मकान की बात नहीं कर रहे हैं. वे इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों का जीवन शांति और सुखमय हो. वे इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से मुद्रास्फीति कि दर नीचे आए. इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से चालू खाते में होने वाले घाटे पर नियंत्रण किया जाए.

यह सभी वे मुद्दे हैं, जिनके बारे में प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए, जबकि वे पाकिस्तान को सबक सिखाने के बारे में बात कर रहे हैं. वे इसे प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पहली भूमिका समझते हैं. बावजूद इसके भी अगर देश की जनता उन्हें चुनती है तो फिर देश ऐसे ही सरकार के लायक है. क्या देश की जनता एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहती है, जो पड़ोसियों को सबक सिखाना चाहता है, जिसके लिए यह उसी तरह है कि आप एक फ्लैट किराये पर लीजिए और अपने पड़ोसियों से रोज झगड़ा कीजिए. आप अपने दोस्त तो बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी नहीं. पाकिस्तान और चीन हमेशा ही हमारे पड़ोसी बने रहेंगे.

हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, जो समझदार हों. जवाहरलाल नेहरू में वह समझदारी थी. हां, यह सही है कि चीन ने उनका भरोसा तोड़ा और उन्हें यह बुरा भी लगा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने चीन से बेहतर संबंध बनाए रखे. इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सेना बेहद सशक्त थी. पाकिस्तान का विभाजन हुआ. इसका श्रेय इंदिरा गांधी को ही जाता है कि उनके नेतृत्व में सेना ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई, लेकिन उन्होंने अपने भाषणों में कभी भी हिंसा की बात नहीं की. लोगों को उनकी भूमिका बताना और उसका पाठ पढ़ाना, यह प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं है. अगर केवल लॉ-आर्डर को ही ठीक करना है तो फिर एक जिलाधिकारी ही पर्याप्त है. तब हमें किसी मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं है फिर तो कलेक्टर और पुलिस ही पर्याप्त हैं. उनके पास बंदूकें हैं. उनके पास कार्रवाई करने का आदेश है. उनके पास लाठी है. हमें राजनेताओं की जरूरत है, ताकि देश की जनता का इस्तेमाल कोई अपने मंसूबों के लिए न कर सके. अगर जनता किसी बात को लेकर नाराज़ है तो नेता को इस योग्य होना चाहिए कि वह उन्हें समझाए. उन्हें शांत करे. अगर आपको केवल कलेक्टर और पुलिस के माध्यम से ही शासन करना है तो फिर चुनावों पर वक्त और पैसा जाया करने का क्या मतलब है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके नये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वास्तव में यही चाहते हैं. अन्य सभी पार्टियों को चाहिए कि वे एकजुट होकर भाजपा को हराएं, ताकि वह अपने नापाक मंसूबे हासिल न कर पाए. यही वक्त की ज़रूरत है. ■

feedback@chauthiduniya.com

यह विडंबना ही है कि जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वह यह नहीं समझता कि अगर वह यह संदेश दे रहा है कि वह देश को सेना और पुलिस के माध्यम से चलाना चाहता है, तो प्रशासन में राजनेताओं की क्या जरूरत? अगर ऐसा है तो फिर हमें प्रधानमंत्री की कोई जरूरत नहीं. वास्तव में मोदी मुद्दे से हट रहे हैं.

कमज़ोर हो रहा है लोकतंत्र

ठाकुर दास बंग

लोकसभा और राज्य विधान-मंडलों की शक्ति बराबर क्षीण होती जा रही हैं. 1980 से लोकसभा के काम करने के दिन बराबर कम हो रहे हैं. सार्वजनिक महत्व के मामलों पर लोकसभा में बहस को दबाने और लोकसभा में जानकारी न देने या एकदम गलत जानकारी देने की कोशिशें बराबर होती रहीं हैं और आज भी हो रही हैं. अंतुले ट्रस्ट, कुओ आयल सौदे, थाल वैशेट परियोजना तथा अन्य कई मौक़ों पर ये बातें एकदम प्रत्यक्ष हो चुकी हैं. अरुण शौरी ने एक केंद्रीय मंत्री पर लोकसत्ता में झूठ बोलने का खुला आरोप लगाया और लोकसभा को यह चुनौती भी दी कि वह उन (शौरी) पर विशेषाधिकार भंग का जुर्म लगाए, लेकिन सत्तारूढ़ दल ने इस मामले को न उठाना ही ठीक समझा, क्योंकि इससे सदन में विस्तृत बहस छिड़ जाती.

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पांच हजार करोड़ रुपयों के कर्ज़ की शर्तों को सरकारी तौर पर अंधेरे में रखा गया, जबकि अमेरिका के प्रत्येक समाचार-पत्र पाठक को इसके बारे में जानकारी थी. सभी लोकतांत्रिक देशों में ऐसे कर्ज़ों की शर्तों पर पर बहस होती है और वे उनकी पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत होती हैं, सिवाय भारत के. आपातकाल के दौरान श्री सी ए स्टीफेन की अध्यक्षता में नियुक्त एक कमेटी ने लोकसभा में बहस रोकने के उद्देश्य से कमेंटियों के गठन की सिफ़ारिश की थी. इस विचार को अभी हाल में फिर जीवित किया गया है और प्रधानमंत्री ने अगस्त, 1982 में लोकसभा में यह बयान दिया था कि पार्लियामेंट की कार्यविधि के संबंध में उनके मन में गंभीर आक्षेप हैं. लोकसभा अध्यक्ष ने हाल में सदस्यों से यह कहना शुरू कर दिया है कि वे उनके कक्ष में आकर मामलों पर विचार-विमर्श करें, न कि लोकसभा में वाद-विवाद को प्रश्रय दें.

लोकसभा के अधिकारों में सबसे गंभीर कटौती बजट के टैक्स व खर्च प्रस्तावों की स्वीकृति के संबंध में हुई. लोकसभा का यह एक बहुत ही पवित्र अधिकार है, लेकिन 1980 से कर तथा राजस्व बढ़ाने वाले अन्य उपाय बजट के बाहर ही निर्धारित किए जा रहे हैं. दिसंबर 1982 में भारत सरकार ने कई मदों पर सीमा व आबकारी शुल्क बढ़ा दिए, इससे तीन सौ करोड़ रुपयों की अतिरिक्त राजस्व आय की आशा की गई थी. फरवरी, 1983 में ठीक पहले मिट्टी का तेल, डीजल तेल तथा

वैमानिक पेट्रोल उत्पादनों का दाम बढ़ाकर 300 करोड़ से भी अधिक आय की उम्मीद की गई थी. डाक-तार व टेलीफोन की दरों में परिवर्तन बजट पेश किए जाने के कुछ दिन पहले घोषित हुआ. पहले के वर्षों में पेट्रोल-उत्पादनों और रेलवे भाड़ों में ऐसे ही बजट-पूर्व व बजट-उपरांत आकस्मिक परिवर्तनों में बृद्धि की गई थी.

इस संदर्भ में यह ध्यान में रखना चाहिए कि सत्तारूढ़ दल पार्लियामेंट की सर्वोच्चता पर बेहिसाब बात करता है, क्योंकि वह लोक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन जैसा कि पहले दिए तथ्यों से यह साफ हो गया होगा कि देश के भाग्य-निर्णायक के तौर पर पार्लियामेंट की शक्ति को हर तरह से क्षीण करने की कोशिश की जा रही है. इसकी सर्वोच्चता की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि उसे एक औजार के तौर पर इस्तेमाल कर संविधान का मौलिक ढांचा बदला जाय और देश पर तानाशाही लाद कर लोक इच्छा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए.

बिना मतादाता सूची में सुधार किए असम में राज्य-विधानसभा चुनाव कराने का निर्णय लोकतंत्र पर सुविचारित रूप से प्रहार का सबसे ताज़ा उदाहरण है. अरुण शौरी ने सारी घटना को विस्तार से प्रमाणबद्ध किया है, यदि इस घटना को बिना चुनौती के जाने दिया गया तो इससे जो उदाहरण प्रस्तुत होगा, वह भारतीय लोकतंत्र को इस तरह बदल देगा कि उसे पहचाना न जा सके.

एकदम साफ तौर पर ग़ैरक़ानूनी बातों में से कुछ को ही गिनाया जाय तो यह स्पष्ट है कि मतदाता सूची को जान-बूझकर चार वर्ष तक सुधारा नहीं गया. इस असंदिग्ध संवैधानिक निर्देशन के बावजूद कि उसे प्रतिवर्ष सुधारा जाय. मुख्य चुनव आयुक्त ने यह तर्क दिया है कि उन्हें चुनाव की तारीख़ों का पता ही चुनाव के छह एक हफ़्ते पहले पता चला. यह एक सरासर झूठ है, क्योंकि असम के पिछले विधानसभा चुनाव यानी 1978 से ही सबको पता था कि 1983 मार्च के पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए.

मतदाता सूची असमिया भाषा में हाथ द्वारा लिखी हुई थी, क्योंकि राज्य कर्मचारियों के असहयोग के कारण उसे छपाया न जा सका और राज्य के बाहर लाया गया चुनाव-संबंधी लगभग प्रत्येक कर्मचारी असमिया भाषा नहीं जानता था.

ज्यादातर चुनाव बूथ पर एक मुख्य अधिकारी नियुक्त था, जबकि क़ानूनन तीन या चार अफसर होने चाहिए. चुनाव अधिकारियों की एक लंबी संख्या, शायद कई सौ, चुनाव-बूथों पर गई ही नहीं और डाक बंगलों या ऐसे ही किसी सुरक्षित स्थान में रहकर उन्होंने अपनी रपटें तैयार कीं. नतीजा यह हुआ कि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में एक प्रतिशत से भी कम वोटों से चुने हुए विधायकों द्वारा सरकार बनाई गई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

यह ध्यान में रखना चाहिए कि सत्तारूढ़ दल पार्लियामेंट की सर्वोच्चता पर बेहिसाब बात करता है, क्योंकि वह लोक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन जैसा कि पहले दिए तथ्यों से यह साफ हो गया होगा कि देश के भाग्य-निर्णायक के तौर पर पार्लियामेंट की शक्ति को हर तरह से क्षीण करने की कोशिश की जा रही है. इसकी सर्वोच्चता की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि उसे एक औजार के तौर पर इस्तेमाल कर संविधान का मौलिक ढांचा बदला जाय और देश पर तानाशाही लाद कर लोक इच्छा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए.

पाठकों की दुनिया

तथ्यों पर आधारित समाचार पत्र

चौथी दुनिया समाचार पत्र में प्रकाशित मनीष जी का लेख *इतिहास के आईने में एक ईमानदार प्रधानमंत्री* व *मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं*, पढ़कर काफी अच्छा लगा इतना सटीक और तथ्यात्मक विश्लेषण मैंने पहली बार पढ़ा. आपने वह हकीकत बताई है जो आज तक किसी मैगजीन या समाचार-पत्र में पढ़ने को नहीं मिला. बड़ा अफसोस होता है कि मीडिया किसी न किसी दबाव या प्रभाव में काम करता है, ऐसी धारणा लोगों के मन में बन गई है, लेकिन आपने उस मिथक को तोड़ दिया और लोगों को सच्चाई के बारे में बताया है. मनीष जी इस लेख के लिए बधाई के पात्र हैं. देश की वर्तमान दशा क्या है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह सरकार आम आदमी को मुश्किल में डालकर बद्तर जीवन जीने को मजबूर कर रखा है. सरकार घोटालों से देश को खोखला कर रही है. ऐसी निकम्मी सरकार से आप बेहतरी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जिसके मुखिया का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ है और वह सरकार चला रहा है. आपके समाचार-पत्र की खबरें निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित होती हैं, जो पढ़कर अच्छा लगता है. आप की भविष्यवाणी सच हो जाए तो देश को बहुत खुशी होगी.

-अनिरुद्ध कुमार सिंह, इलाहाबाद

वाह रे सरकार

भारतीय अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है. डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत का लगातार कम होना राजकोषीय घाटा और विकास दर में प्रतिदन गिरावट आना ये विकास के लक्षण नहीं हैं. रुपये के कमजोर होने से विदेशी कर्ज और आयात के मूल्य में बेहताशा वृद्धि हुई है. विकास के अर्थशास्त्री पैमाने लगातार धाराशायी होते जा रहे हैं. सरकार की गंभीरता इस बात पर है कि आने वाले चुनावों में जीत कैसे हो. मुझे लगता है कि सरकार चुनाव से पहले लोगों को दिखाने के लिए और कुछ कदम उठा सकती है, उससे अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने में कोई वास्तविक मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार अब तक जितने भी उपाय किए हैं सारे खोखले निकले. यह दौर अर्थव्यवस्था के लिए इसलिए भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनावी वर्ष में गैर-योजनागत व्ययों की बयार आएगी, जिससे संकट और गहराएगा. फिलहाल जहां तक विदेशी मुद्रा भंडार का है तो बढ़ते आयात व गिरते रुपये के मूल्य के सामने यह कितने दिन चलेगा? नीतिगत फैसले लेने में असक्षम सरकार इस स्थिति के लिए 100 फीसदी जिम्मेदार है. एक अनुभवी कर्तव्यनिष्ठ विचार का दावा करने वाली सरकार से यह देश क्या चाहेगा.

-अशोक निर्मोही, दरभंगा

हिंदी को न भूले

देश कई बार विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया है, लेकिन लंबा शासन करने में मुख्यत: मुगल और ब्रिटिशों को ही सफलता मिली. भारत जब गुलाम नहीं था, तब यहां मुगल और ब्रिटिश आए. क्योंकि उस समय देश में किसी न किसी जगह क्रांति चलती रहती थी और यहां के लोगों ने प्राण गवाएं, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की. आज देश के एक बड़े वर्ग ने पराधीनता स्वीकार ली है और अब उनका उद्देश्य पूरे भारत को पराधीन बनाने का है. इस कार्य को बड़ी कुशलता के साथ क्रियान्वित कर रहे हैं. उन्होंने चारों तरफ ऐसा जाल बिछाया है कि किसी भी भारतवासी में आत्मसम्मान या आत्मविश्वास जागृत न हो पाए. वह अपने को हीन भावना से ग्रस्त समझे. वर्तमान में पूरे विश्व में यह अकेला देश ऐसा है, जहां के लोगों में अपनी भाषा में लिखने-पढ़ने-बोलने में शर्म आती है. जो ब्रिटेन और अमेरिका की नौकरी करना पसंद करते हैं. यहां के उद्योगपति नौकरी पेशा या थोड़ा सा भी संपन्न व्यक्ति अंग्रेजी बोल कर बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है. यहां किसी भाषा का विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन हमें अग्रेजी को एक साधारण भाषा से कुछ नहीं समझना चाहिए. जैसा कि चीन, जापान, रूस, स्पेन आदि के लोग समझते हैं. यह प्रत्यक्ष भी है कि भाषा ज्ञान की पर्यायवाची नहीं होती है और कोई राष्ट्र अपनी भाषा में ही तरक्की कर सकता है, वरना उसकी तरक्की कुछ ही लोगों तक सीमित रहती है.

हम सभी को इस तथ्य को समझ लेना चाहिए कि राष्ट्र भाषा किसी देश की रीढ़ होती है. बिना राष्ट्र भाषा के किसी राष्ट्र का निर्माण कैसे संभव? इसलिए हिंदी के अधिकाधिक उपयोग के द्वारा हमें भारत को एक डोर में बांधकर उसके विकास को सुनिश्चित करना चाहिए.

-विकास पाटनी, झुमरी तलैया

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

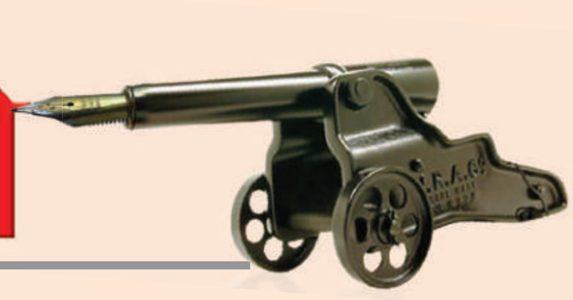

कलंकित हो रहा है पत्रकारिता का आदर्श

हम अपनी कुछ रिपोर्टों के बारे में कहना चाहते हैं, जिनमें सबसे पहली रिपोर्ट कोयला घोटाले को लेकर थी. हमने इसे देश में सबसे पहले छापा. इससे पहले हमने रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट अपने अख़बार में छापी थी और चुनौती दी थी कि सरकार कहे कि यह रिपोर्ट झूठी है. इस रिपोर्ट को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में काफ़ी हंगामा हुआ. अंतत: लोकसभा के इतिहास में पहली बार 45 से 50 सांसद चौथी दुनिया अख़बार लेकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इसके ऊपर जवाब दें. प्रधानमंत्री को रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का आश्वासन देना पड़ा और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट देश के सामने आई. ये अलग बात है कि सरकार ने रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट की सिफ़ारिशों के ऊपर कुछ भी नहीं किया है. इसी तरह सबसे पहले हमने कोयला घोटाले को उजागर किया और हमने कहा कि ये 26 लाख करोड़ का घोटाला है. जब हमने यह रिपोर्ट छापी, तब राजनीतिक पार्टियों की नज़र इस पर गई. लोकलेखा समिति ने इसके ऊपर जांच शुरू की. सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और आज कोयला घोटाला देश में सबसे बड़े भ्रष्टाचार का सवाल बनकर खड़ा हुआ है, जिस पर सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है. सरकार के कब्ज़े से फ़ाइलें गायब हो जाती हैं, सरकार को पता नहीं चलता. मानो कोई टहलता हुआ आया और फ़ाइलें उठाकर चला गया. ये उस सरकार का हाल है, जो सरकार पाकिस्तान के, चीन के भेदियों से घिरी हुई है और ये पता नहीं लगा पा रही है कि सरकार के भीतर कौन पाकिस्तान का भेदिया है और कौन चीन का भेदिया. हमारे देश में कई ख़ुफ़िया एजेंसियां काम कर रही हैं, जिनमें मोसाद, आईएसआई, सीआईए और सबसे कमज़ोर रूस की केजीबी भी है. इनमें से किसके पास कौन अफसर है और किसके पास कौन मंत्री, पता नहीं चलता, लेकिन नतीजा सामने है कि मंत्रालय से फ़ाइलें गायब हो जाती हैं. ये तो संयोग की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सख़्त रुख़ अपनाया और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, नहीं तो कितने केसों के कितने संवेदनशील विषयों की फ़ाइलें विदेशी ताक़तों के पास, हमारे दुश्मनों के पास पहुंच जाती हैं, कहा नहीं जा सकता.

हमने सबसे पहले यह उजागर किया कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह को 14 करोड़ के घूस की पेशकश की गई. ये मज़े की बात है कि शोर-शराबा हुआ, लोगों की भौंहें तनीं, सीबीआई को जांच सौंपी गई और सीबीआई ये कहती है कि क्योंकि उन्हें जो सीडी सौंपी गई, वो सीडी करप्ट थी, इसलिए उनके हाथ में कोई सबूत नहीं है. ये तर्क समझ में नहीं आता, क्योंकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है कि कोई भी चीज अगर हार्डडिस्क में है, रिकॉर्ड हुई है, तो रिकवरी की जा सकती है. ऐसा सीबीआई ने क्यों नहीं किया. अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि हथियारों के दलाल, जो साउथ ब्लॉक में घूमते हुए देखे जा सकते हैं, जिनके फाइव स्टार होटलों में सुईट हैं, जो बड़ी-बड़ी पार्टियां देते हैं, जिनमें से कुछ अंदर हैं, तो कुछ बाहर हैं. जिनके संपर्क में मंत्रियों के बेटे और बेटियां हैं, दामाद हैं, वो सारे लोग शायद ज़्यादा भारी हैं, बनिस्बत भारत सरकार की ख़ुफ़िया एजेंसियों के और भारत सरकार की इज़्ज़त के. हमने ये सूची भी अपने अख़बार में छापी है कि नक्सलवादी संगठनों को कौन-कौन से उद्योगपति नियमित रूप से पैसा देते हैं. सरकार इस रिपोर्ट पर आंख बंद कर के बैठी है. विपक्ष भी इस रिपोर्ट पर चुप्पी साधे हुए है.

हमने यूआईडी यानी आधार कार्ड को लेकर सबसे पहले रिपोर्ट छापी, जिसमें हमने ये कहा कि आधार कार्ड को बनाने का फ़ैसला विदेशी कंपनियों के लिए लिया गया. विदेशी जासूसी एजेंसियों के लिए लिया गया और ख़र्चा हमारे ख़ून-पसीने की कमाई से भारत सरकार ने किया. 60 हज़ार करोड़ का बजट यूआईडी के लिए रखा गया, जिसका फ़ैसला संसद में नहीं हुआ, यह फ़ैसला एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ. एक झटके में 60 हज़ार करोड़ पानी में चले गए और आधार कार्ड की आवश्यकता को लेकर बड़े-बड़े विज्ञापन, बड़े-बड़े कैंपेन चलाए गए. हमने हर बार कहा कि ये पैसा खाया जा रहा है और जिन लोगों की मदद से ये आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है. ग़लत पते, ग़लत नाम, ग़लत जगहों से आधार कार्ड बने. अविश्वसनीय आधार कार्ड बने, लेकिन सही-ग़लत डाटा विदेशी मार्केटिंग कंपनियों और विदेशी जासूसी एजेंसियों के पास पहुंच गया. हमने ये भी शक ज़ाहिर किया कि जब कभी इस देश में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नरसंहार का फ़ैसला होगा, तब ये आधार कार्ड का डाटा उनके लिए मार्गदर्शक नक्शे का काम करेगा. हमें ख़ुशी है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले को अपनी सख़्त निगरानी में रखा है, वैसे ही उसने एक अहम फ़ैसला दिया है कि आधार कार्ड लाज़िमी नहीं है. इसने हमें एक बार फिर सही साबित किया. भारत सरकार आधार कार्ड को लाज़िमी बनाना चाहती थी. नंदन नीलेकणी ने इस आधार कार्ड के सारे बजट को दाएं-बाएं करके बर्बाद किया और उन्होंने पिछले चार साल सरकार के दामाद की तरह वक्त काटा. अब वो राज्यसभा के ज़रिये संसद में आना चाहते हैं. ज़ाहिर है नंदन नीलेकणी कि वजह के कुछ लोगों को हज़ार या दो हज़ार करोड़ का फ़ायदा हुआ है. वे ज़रूर नंदन नीलेकणी को राज्य सभा में लाना चाहेंगे.

हम इन रिपोर्टों का ज़िक्र इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके पहले देश में तकरीबन 80 रिपोर्ट ऐसी छापीं जो न केवल देश में पहले आईं, बल्कि उन्होंने उन लोगों को चौंकाया जो सचमुच समाचार और समाचार के पीछे के कारणों को जानना चाहते हैं. आज जबकि पत्रकारिता पैसे लेकर लोगों के हितों को साध रही है. जर्नलिज़्म ऑफ़ करेज का लेबल देकर जर्नलिज़्म ऑफ़ दलाली चल रही है. इस बीच अपने साथियों में ऐसे लोग नहीं हैं जो ऐसी पत्रकारिता का विरोध करें तो लगने लगता है कि यह पत्रकारिता का राक्षस है, जो हमें खा जाएगा. तब हमें लगता है कि हम इस कहानी को भूल गए और इस सत्यता को भी भूल गए कि चींटी बड़ी आसानी से हाथी को मार सकती है. ऐसी पत्रकारिता का विरोध होना चाहिए और जो लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वे लोग कायर हैं ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन वे लोग पत्रकारिता की इस स्थिति से निराश ज़रूर हैं. ऐसे सभी निराश साथियों से हमारा अनुरोध है कि आज अगर निराशा का बादल नहीं हटाया तो कल यह निराशा का बादल निराशा के तूफ़ान में बदल जाएगा.

»» आज जब पत्रकारिता पैसे लेकर लोगों के हितों को साध रही है. जर्नलिज़्म ऑफ़ करेज का लेबल देकर जर्नलिज़्म ऑफ़ दलाली चल रही है. इस बीच अपने साथियों में ऐसे लोग नहीं हैं जो ऐसी पत्रकारिता का विरोध करें तो लगने लगता है कि यह पत्रकारिता का राक्षस है जो हमें खा जाएगा. हमें लगता है कि हम इस सत्यता को भी भूल गए कि चींटी बड़ी आसानी से हाथी को मार सकती है. ऐसी पत्रकारिता का विरोध होना चाहिए. आज अगर निराशा का बादल नहीं हटाया तो कल यह निराशा के तूफ़ान में बदल जाएगा.

सबसे ज़्यादा अफ़सोस इस बात का है कि जिस अख़बार को श्री रामनाथ गोयनका ने पत्रकारिता के सर्वोच्च आदर्शों के लिए अलंकृत कर रखा था, जो अख़बार सत्ता की चापलूसी से कोसों दूर था और जिन रामनाथ गोयनका ने सत्ता को कभी अपना आदर्श नहीं माना, उन्हीं रामनाथ गोयनका के बेटे विवेक गोयनका के नेतृत्व में चलने वाला यह अख़बार इस समय न केवल सत्ता की चापलूसी में लिप्त है, बल्कि उसकी सारी रिपोर्ट पत्रकारिता के मानदंड़ों के विपरीत भ्रष्टाचार के पक्ष में छपती दिखाई दे रही हैं. जो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बोलने की कोशिश भी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ यह अख़बार मुहिम चलाता दिख रहा है. अब इस अख़बार को जनता की तकलीफ़ों से कोई वास्ता नहीं. अब इस अख़बार को रामनाथ गोयनका के आदर्शों से कुछ लेना-देना नहीं, अब यह अख़बार ऐसी पत्रकारिता के साथ चल रहा है जिसमें पैसा है. वह पैसा चाहे दलाली से आए, हथियारों के सौदागरों की दलाली से आए या फिर विदेशी ताकतों के पक्ष में रिपोर्ट लिखकर आए.

अच्छी बात यह है कि इस अख़बार के पत्रकारों का बहुमत अपने अख़बार की इस नीति के ख़िलाफ़ है. इस अख़बार के बहुत सारे लोग जब हमें मिलते हैं तो बताते हैं कि वे इस जर्नलिज़्म से कोई सरोकार नहीं रखते, कोई वास्ता नहीं रखते, वे सिर्फ़ नौकरी कर रहे हैं. यह बात सही है कि आज के बाज़ारवाद और महंगाई के इस दौर में नौकरी एक बड़ी चीज़ है. लेकिन अंतरात्मा या पत्रकारिता के आदर्श भी जीवन में कुछ स्थान तो रखते ही हैं. जो लोग पत्रकारिता में शुद्धि चाहते हैं, उन्हें किसी न किसी तरह यह आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ताकि दलाली और देशद्रोह की पत्रकारिता के ऊपर लगाम लग सके. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

भारत की विचारधारा

»» क्या यह बेहतर नहीं होगा कि संविधान के आधार पर सभी भारतीयों के साथ एक नागरिक के तौर पर व्यवहार किया जाए? ऐसे नागरिक जिनके समान अधिकार हैं और राज्य का दायित्व है कि उसकी सुरक्षा करे और सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करे. क्या हमें सलमान रुश्दी और एमएफ हुसैन की अभिव्यक्ति की आज़ादी की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए, यह ध्यान दिए बिना कि वे हिंदू कट्टरता पर हमला कर रहे हैं या मुस्लिम कट्टरता पर?

अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 के चुनाव 1977 के बाद सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में एक होंगे. कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जिसे उसने बड़ी चतुराई से भारत की विचारधारा के रूप में पेश किया है, को आधारभूत तौर पर चुनौती मिलने जा रही है. इस चुनाव में भारत की विचारधारा चुनावी मुद्दा बनेगी.

धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिकता और वाम झुकाव का विचार, जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की उपज था. इसका संबंध मूलत: गांधी के विचारों से है, लेकिन जैसा कि नेहरू योजना और औद्योगीकरण और राष्ट्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए सेनाओं की तैनाती में विश्वास करते थे, (यद्यपि वे इसमें कम ही सफल हुए), ये गांधी के आदर्श नहीं हैं. नेहरू ने ऐसे समाज का तर्क पेश किया, जो जाति-विहीन, वर्ग-विहीन, आधुनिक और तार्किक हो, धार्मिक अंधविश्वास से दूर हो, सहिष्णु हो और जहां विभिन्न विचारों का आदर करते हुए खुले विमर्श किए जा सकें. इस सबसे परे उन्होंने एक ऐसी पार्टी की अगुआई की, जिसका आधार बहुत ही व्यापक था और इस पार्टी की मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों पर तर्क-वितर्क हुए, जिनमें से कुछ उन्होंने गवां दिए.

यह विचार लेकर विश्वविद्यालयों के बुद्धिजीवी उनपर बहसें करते हैं. इन बहसों और विचारों के परिष्कार ने एक ऐतिहासिक आधार प्रदान किया, जिसकी वजह से समन्वयात्मक भारत इतिहासलेखन में एक स्तर तक पहुंच सका. राष्ट्रवादी हिंदुओं का वैकल्पिक इतिहास लेखन, जो भारतीय विद्या भवन से प्रकाशित हुआ, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में कभी शामिल नहीं किया गया. भारत का इतिहास जिस तरह से लिखा गया, उस पर कांग्रेस का खासा प्रभाव रहा है. स्वतंत्रता आंदोलन के वे शहीद, जिन्होंने हिंसा का रास्ता अख़्तियार किया, उन्हें कमतर आंका गया, मुख्यत: सुभाष चंद्र बोस को.

आज़ादी के शुरुआती 20 साल तक यह विचार राष्ट्रीय चेतना का आधार रहा है. मैं इसी विचार रूपी छतरी की छाया में बडा हुआ. कांग्रेस एक पार्टी से आगे भी बहुत कुछ थी. कांग्रेस एक व्यवस्था थी. सूचनाएं जनसाधारण से केंद्र की तरफ जाती थीं और व्यवस्था उच्च स्तर से नीचे की ओर गांवों तक जाती थी. एक ही कांग्रेस थी, एक ही भारत था और एक ही भारत की विचारधारा थी.

आने वाले चुनावी समर में कांग्रेस भारत के इस विचारधारा का बचाव कर रही है. लेकिन यह विचारधारा नेहरू की मृत्यु के बाद लगातार क्षीण होती गई है. बंटवारे के समय दंगों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, देश में कहीं भी साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते थे. 1965 के बाद से देश ने दंगों का सामना करना शुरू किया और तब से 1995 तक दंगों में 7500 लोग मारे गए. 1969 में कांग्रेस के विघटन का अर्थ ही था कि यह अब व्यापक आधार वाली पार्टी नहीं रह गई थी जो बहुध्रुवीय सत्ता संरचना में विभिन्न विचारों के प्रति सहिष्णु रहती. यह नेताओं की निजी जागीर बन गई थी और सभी तरह के तर्क-वितर्क समाप्त हो गए थे. धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों से निरपेक्ष होना नहीं, बल्कि सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो गया. धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा जनसंघ की विचारधारा के विरोध में गढ़ी गई थी, जिसका मक़सद मुस्लिम वोट बैंक को सुरक्षित करना था. आपातकाल ने भारत की इस विचारधारा को खंडित कर दिया. आपातकाल फासीवादी शासन के तौर पर जाना गया. पुरानी कांग्रेस और जनसंघ के नेता जेल भेज दिए गए. जब आपातकाल ख़त्म हुआ, जनसंघ और भाजपा भारतीय राजनीति का सम्माननीय हिस्सा बनकर उभरी. जब इंदिरा गांधी फिर सत्ता में लौटीं तो उनकी धर्मनिरपेक्षता हिंदू रंग में रंगने लगी. यह राजीव गांधी थे, जिन्होंने अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा की अनुमति दी और शाह बानो पर कोर्ट के निर्णय के ख़िलाफ़ गए. इस तरह हिंदू कट्टरता को मुस्लिम कट्टरता के साथ संतुलित किया गया. धर्मनिरपेक्षता को मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसके आधार धार्मिक नेताओं से समझौते हुए. दुख है कि इसने मुस्लिम जनता को उनके पिछड़ेपन और महरूमियत से उबरने में कोई मदद नहीं की. धर्मनिरपेक्षता मलाईदार तबके के लिए है, असर्फी वर्ग के लिए, जिसे संरक्षण प्राप्त है.

अब वह समय आ गया है, जब इस जंग लगी विचारधारा को खुले तौर पर चुनौती देने की ज़रूरत है. क्या यह बेहतर नहीं होगा कि संविधान के आधार पर सभी भारतीयों के साथ एक नागरिक के तौर पर व्यवहार किया जाए? ऐसे नागरिक जिनके समान अधिकार हैं और राज्य का दायित्व है कि उसकी सुरक्षा करे और क़ानून के समक्ष सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करे. क्या हमें सलमान रुश्दी और एमएफ हुसैन की अभिव्यक्ति की आज़ादी की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए, यह ध्यान दिए बिना कि वे हिंदू कट्टरता पर हमला कर रहे हैं या मुस्लिम कट्टरता पर? क्या प्रत्येक को उसकी जाति और धर्म के बजाय उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए? यदि ऐसा होता है तो, जैसा कि महात्मा गांधी ने यूरोपीय सभ्यता के बारे में कहा था, उसी तरह भारत की विचारधारा बेहतर होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

सूचना का अधिकार चौथी दुनिया की पहल

स्कूल की हालत कैसे सुधरेगी

चौथी दुनिया ब्यूरो

सरकारी स्कूल इस देश के करोड़ों बच्चों के लिए किसी लाइफ लाइन से कम नहीं हैं. वजह, निजी स्कूलों का ख़र्च उठा पाना देश की उस 70 फ़ीसदी आबादी के लिए बहुत ही मुश्किल है, जो रोज़ाना 20 रुपये से कम की आमदनी पर अपना जीवन यापन करती है. ऐसे में सरकारी स्कूल ही एक रास्ता बचता है, जहां ग़रीब बच्चों को शिक्षा मिल सके. निश्चित तौर पर सरकार ने शिक्षा और ख़ासकर, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं और वह इन योजनाओं पर अरबों रुपये ख़र्च भी कर रही है. सर्वशिक्षा अभियान इसका बेहतरीन उदाहरण है. बावजूद इसके, अभी भी ऐसी हालत है कि गांवों में अधिकांश प्राथमिक स्कूलों की इमारतें जर्जर अवस्था में हैं. यही नहीं, कभी इन स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होता है तो चाक नहीं होती. चाक होती है तो बैठने के लिए मेज-कुर्सियां नहीं होतीं. होती भी हैं तो टूटी-फूटी. ऐसा नहीं है कि स्कूलों को इन चीजों के लिए पैसा नहीं मिलता. हर स्कूल को हर साल इन ज़रूरी चीजों के लिए बजट आवंटित किया जाता है. अब सवाल उठता है कि आख़िर पैसा मिलने के बाद भी प्राथमिक स्कूलों की हालत ख़राब क्यों रहती है.

ऐसी स्थिति में यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए इस बात पर नज़र रखें कि आख़िर स्कूल के विकास के लिए आने वाले पैसों का कहीं ग़लत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है. ऐसी ख़बरें आती रही हैं कि स्कूल के विकास के लिए आने वाले पैसों का हेडमास्टर, मुखिया-प्रधान एवं अधिकारी मिलकर गबन कर जाते हैं. हमें पैसों की इस चोरी को रोकने के लिए क़दम तो उठाना ही होगा, क्योंकि यह हमारा ही पैसा है, जो हम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं और सरकार फिर उन पैसों को हमारे विकास के लिए ख़र्च करती है. तो क्या हम अपने विकास के लिए आने वाले पैसों का हिसाब नहीं मांगना चाहेंगे? आइए, इस अंक में प्रकाशित आवेदन पत्र का इस्तेमाल कीजिए और अपने इलाक़े के सरकारी स्कूल के विकास से जुड़े ख़र्च का हिसाब-किताब मांगिए. आप इस आवेदन पत्र के माध्यम से पूछ सकते हैं कि किसी खास साल में आपके क्षेत्र के स्कूल के विकास के लिए कितनी रकम आवंटित की गई, यह रकम किन कार्यों के लिए आवंटित की गई, किन एजेंसियों के माध्यम से उक्त काम कराए गए, किन लोगों ने उक्त कार्यों को सही बताया और ठेकेदार को भुगतान की अनुमति दी, ठेकेदार को उक्त कार्य के लिए कितनी रकम का भुगतान किया गया? यदि आप इस तरह की सूचना मांगते हैं तो तय मानिए, इस आवेदन से एक तरह का दबाव बनेगा, उन लोगों पर, जो विकास का पैसा हजम कर जाते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आप इस आवेदन का इस्तेमल ज़रूर करेंगे और साथ ही अन्य लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करेंगे. ■

सूचना के सिपाही वीरपाल लाखा

एटा (उत्तर प्रदेश) के अवागढ़ में रहने वाले वीरपाल लाखा एक आम नागरिक हैं, लेकिन वह आम होते हुए भी ख़ास हैं, क्योंकि उनका काम ख़ास है. वह आम आदमी होते हुए भी आम आदमी को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं. वीरपाल लाखा दरअसल अपने क्षेत्र में सूचना का अधिकार क्रांति की अलख जगा रहे हैं, स्थानीय स्तर पर आरटीआई क़ानून को लेकर जन जागरण कर रहे हैं. लोगों को इस क़ानून के बारे में बताकर उन्हें एक सजग-सशक्त नागरिक बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं. वीरपाल लाखा किसी अन्य स्रोत से मदद लिए बिना वह काम कर रहे हैं. चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए वीरपाल लाखा बताते हैं कि उन्हें यह काम शुरू करने में सबसे ज़्यादा मदद मिली चौथी दुनिया में प्रकाशित होने वाले आरटीआई के नियमित कॉलम से. पिछले एक साल से वह इस कॉलम को सहेज कर रख रहे हैं और लोगों के बीच जाकर उन्हें आरटीआई के बारे में बताते हैं, लोगों को इस क़ानून के इस्तेमाल के तरीक़े सिखाते हैं, उनकी मदद करते हैं. चौथी दुनिया अख़बार ख़रीदने के लिए वीरपाल लाखा को ज़िला मुख्यालय तक जाना पड़ता है, लेकिन वह नियमित तौर पर यह अख़बार ख़रीदते हैं और लोगों के बीच मुफ्त में बांटते हैं. वीरपाल लाखा ख़ुद भी आरटीआई का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार के कई मामलों का ख़ुलासा कर चुके हैं. वह कहते हैं कि गांव के लोग भले ही ज़्यादा पढ़े-लिखे न हों, लेकिन इस अख़बार में प्रकाशित आरटीआई कॉलम को देखकर आरटीआई आवेदन बना लेते है.

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301 ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

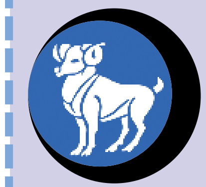

मेष

21 मार्च से 20 अप्रैल

इस सप्ताह व्यापारी अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे. घरेलू जीवन भी सुखमय रहेगा. किसी राजनीतिक और उच्च अधिकारी के सहयोग से बिगड़े कार्य बनेंगे. कुछ अनसुलझे मुद्दों का भी समाधान मिलेगा. पारिवारिक जीवन में भी सुखी रहेंगे. किसी भी कार्य से पहले कोई आलस्य न करें. स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा.

वृष

21 अप्रैल से 20 मई

इस सप्ताह आप भाग्यशाली साबित होंगे और धनोपार्जन भी ठीक ठाक करेंगे. विद्यार्थी को सफलता के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है. इस सप्ताह आपकी व्यस्तता बढ़ने वाली है. आपकी पराक्रम और उत्साह में भी वृद्धि होगी, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आर्थिक रूप से आप कुल मिलाकर अच्छा समय रहेगा. स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा.

मिथुन

21 मई से 20 जून

इस सप्ताह अपने महत्वाकांक्षा को नियंत्रण में रखें और अपने धुन में कार्य करते चलें, फल की चिंता न करें. आप अपनी प्रगति की बातें सब जगह जाकर न बोलें, उससे आपके शत्रु बनेंगे. किसी को कर्ज देने से पहले मंथन जरूर कर लें. नौकरी पेशा लोगों के लिए भाग्य से ज्यादा कर्म का महत्व बनेगा. अधिकारी का कोपभाजन न बनें.

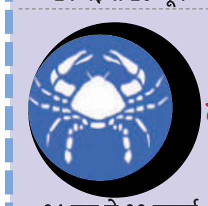

कर्क

21 जून से 20 जुलाई

इस सप्ताह आपके प्रति लोगों का व्यवहार सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक होगा. इस सप्ताह आपके मान सम्मान बढ़ने का प्रबल योग रहेगा. स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या बनेगी. कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर आप प्रभावी और फायदे में रहेंगे. कोई यात्रा भी हो सकती है.

सिंह

21 जुलाई से 20 अगस्त

इस सप्ताह अपने आत्मविश्वास पर कार्य करेंगे. संपत्ति की खरीद विक्री भी संभव है. परिजनों के साथ रिश्ता तनावपूर्ण रहेगा. प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को मेहनत की जरूरत है. किसी को क़र्ज़ देने से पहले सोचें.

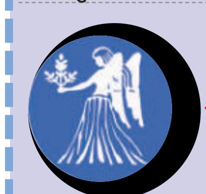

कन्या

21 अगस्त से 20 सितंबर

इस सप्ताह आपको अच्छी सफलता मिलेगी. व्यवसायी लोग काफी खुश रहेंगे और उन्नति करेंगे. नौकरी पेशा लोग सावधानी से खर्च करें. किसी साजिश के शिकार न हों. इस सप्ताह आप बीमारी से बचे रहेंगे और स्फूर्ति से सराबोर रहेंगे. इस सप्ताह कोई बिना उम्मीद का धन प्राप्त होगा. विवादित मामलो से बचें. बच्चों का सहयोग प्राप्त रहेगा.

तुला

21 सितंबर से 20 अक्टूबर

इस सप्ताह व्यवसायी बहुत खुश रहेंगे और विस्तार योजना को कार्यरूप देंगे. कोई पैतृक संपत्ति का भी विवाद सुलझेगा. स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा. पारिवारिक सुख भी मिलेगा. इस सप्ताह पुराने कार्यों में सफलता मिलेगी और आप अपने आप में एक नई उर्जा पाएंगे. आर्थिक मामलों में आप थोड़ा चिंतित रहेंगे. आपके कार्यक्षेत्र का भी विस्तार होगा.

वृश्चिक

21 अक्टूबर से 20 नवंबर

ये सप्ताह आपका उत्साह और उमंग का सप्ताह रहेगा. परिवार की ओर से शुभ समाचार मिलेगा. आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी. विरोधी के स्वर थोड़े उंचे रहेंगे. किसी यात्रा की योजना बनेगी और आप लाभान्वित रहेंगे. आपका पारिवारिक और सामाजिक दायित्व भी बढ़ेगा. परिवार में बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

धनु

21 नवंबर से 20 दिसंबर

इस सप्ताह आपका प्रबंधन बहुत ही अच्छा रहेगा. पूंजी निवेश थोड़े मंथन के बाद करें. कोई भी निर्णय उत्तेजना में न लें. मानसिक परेशानी को अपने ऊपर हावी न होने दें. आर्थिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी. अपने अधिकारी से अच्छे सम्बन्ध बना कर चलें. आकस्मिक यात्रा की योजना बनेगी.

मकर

21 दिसंबर से 20 जनवरी

इस सप्ताह ऐसे दोस्तों से सावधान रहें, जिनके मन में आपके लिए अच्छी भावना नहीं है. आपका मन इस सप्ताह चिड़चिड़ा रहेगा. आपकी इकठ्ठा की हुई पैसे का निवेश सतर्क होकर करें. संतान के प्रति चिंता बढ़ेगी. साथ कार्य करने वाले लोगों से वैमनस्यता बढ़ सकती है. अधिक व्यय भी बाधा बनेगा. नये संपर्क मददगार साबित होंगे.

कुंभ

21 जनवरी से 20 फरवरी

इस सप्ताह आपको सफलता मिलेगी, लेकिन संतुष्टि नहीं. नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों को सफलता मिलेगी. भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है. जमीन जायदाद से संबंधित व्यवसाय करने वाले लोग थोड़ा तनाव महसूस करेंगे. स्वास्थ्य हलके उतार चढ़ाव के साथ अच्छा रहेगा.

मीन

21 फरवरी से 20 मार्च

इस सप्ताह आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी. व्यवसायी थोड़े उलझन में रहेंगे. कानूनी मामलों में सतर्क रहें. धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. दांपत्य जीवन और संतान सुख प्राप्त होगा. इस सप्ताह आपकी सोची हुई चीजें पूर्ण होंगी. कोई पदोन्नति की खबर प्राप्त हो सकती है. आप भाग दौरे से धन इकठ्ठा करेंगे.

ज़रा हट के

शराब के नशे में सांप ले आया

शराब के नशे में लोग न जाने क्या-क्या कर बैठते हैं. ऐसा ही कुछ दिनों पहले मेरठ जिले के रहमापुर गांव में एक वाकया देखने को मिला. एक व्यक्ति शराब के नशे में जंगल से सांप (कोबरा) पकड़ लाया. वह सांप के साथ पूरे दिन खेलता रहा, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. वह कभी सांप को हाथ में ले लेता तो कभी गले में डाल लेता. उससे अपनी जीभ पर भी डसवाता. जब शराब का नशा खत्म हो गया और सांप के जहर ने उस आदमी पर असर किया तो उसकी मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया. वहां के लोगों के अनुसार, वह शराब का आदी था और उसने उस दिन सुबह लगभग दस बजे ही शराब का सेवन कर लिया था. नशे में ही हस्तिनापुर पांडेश्वर मंदिर के निकट जंगल से एक कनस्तर में सांप बंद कर गांव ले आया. गांव वालों ने जब उससे सांप को जंगल में छोड़कर आने को कहा तो वह कहने लगा कि यह सांप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. इसके बाद वह सांप से खेलने लगा और वह कभी उसे गले में डालता तो कभी हाथ में लेकर घूमता. उसने यह सब लगभग सात घंटे तक किया. इस दौरान ग्रामीणों के बार-बार समझाने के बावजूद, उसने सांप से खेलना बंद नहीं किया. लोग यह देखकर चकित हो गए कि वह सांप से अपनी जीभ पर डसवाने लगा. ऐसा तब तक चलता रहा, जब तक उस पर शराब का नशा था. शाम लगभग चार बजे नशा कम होने पर सांप के जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया. इसके बाद लगभग पांच बजे उसकी मौत हो गई. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

गिनीज बुक में सबसे छोटी कार

दुनिया की सबसे छोटी कार आ गई है, जिसे आप सुरक्षित तरीके से सड़कों पर चला सकते हैं. इस कार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकाड्र्स में दर्ज कर लिया गया है. इस कार की ऊंचाई केवल 25 ईंच और लंबाई चार फीट है. इसमें बमुश्किल बस एक इंसान(कार चालक) ही सवारी कर सकता है. देखने में भले ही ये कार खिलौने जैसा लगे, लेकिन इंजन समेत इसके सभी कल-पुर्जे असली कार जैसे ही हैं

कस्टम कार निर्माता ऑस्टिन कॉलसन की इस कार ने अमेरिका में पहले ही सबसे छोटी कार होने का तमगा हासिल कर लिया था. इस कार को कानूनी तरीके से सड़क पर चलाया जा सकता है. कॉलसन कहते हैं कि वह हमेशा से अपनी कार को गिनीज बुक में दर्ज कराना चाहते थे. उनको हमेशा से ही कारों से बहुत प्यार है. उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह से खुद को गिनीज बुक में दर्ज कराना चाहते थे और उन्होंने जब मौजूदा रिकॉर्ड कार के विषय में देखा तो उन्होंने तय कर लिया कि वह नया कीर्तिमान हासिल करेंगे. कॉलसन की कार माप में 25 ईंच यानी करीब दो फीट 1.75 ईंच ऊंची और चार फीट व 1.75 ईंच लंबी है. इस कार पर टेक्सास राज्य की वेनिटी लाइसेंस नंबर प्लेट भी लगी है, जिस पर अंग्रेजी में आइएम बिग लिखा हुआ है. गिनीज की वेबसाइट के अनुसार, कॉलसन को सड़क पर चलने योग्य वाहन के तौर पर उत्तीर्ण होना होगा. इसमें सेफ्टी ग्लास, विंडशीट, विंडशीट वाइपर, सिगनल लाइट, सीट बेल्ट और हॉर्न आदि सभी आवश्यक मानक हैं. ■

एक साथ 5 बच्चों को जन्म

कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है. ऐसा ही कुछ देखने को मिला नवादा के एक निजी नर्सिंग होम में, जब एक महिला ने एक साथ पांच बच्चों को जन्म दिया. नवादा जिले के सदर प्रखंड के अंबिका बिगहा गांव की रहने वाली सपना पिछले पांच वर्षों से मां बनने का सपना संजोए हुई थी. सपना पूरा करने की गुहार लगाते हुए वह मंदिरों और मजारों पर गई, कई चिकित्सकों से सलाह ली, लेकिन वर्षों तक उसको कोई बच्चा नहीं हुआ. इस बीच सपना की गोद हरी हो गई और उसका सपना हकीकत बन गया. वह भी ऐसा कि लोग दंग रह गए. नवादा के एक निजी नर्सिंग होम में सपना ने एक-दो नहीं, एक साथ पांच बच्चों को जन्म दिया. नर्सिंग होम की चिकित्सक डॉ. सुधा शर्मा ने बताया कि पहले बच्चे के जन्म के कुछ ही समय के दौरान बारी-बारी से पांच बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें तीन लड़के और दो लड़कियां हैं. डॉ सुधा ने बताया कि पांचों बच्चों का जन्म बिना ऑपरेशन के हुआ. सभी बच्चों का वजन 600 से 700 ग्राम के बीच था. हालांकि तीन बच्चों की कुछ ही समय के अंतराल पर एक-एक कर मौत हो गई, जबकि एक लड़का और एक लड़की अभी पूर्णत: स्वस्थ हैं. उन्होंने बताया कि बच्चों को शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ महेश कुमार की निगरानी में रखा गया है. आम तौर पर जन्म के बाद औसतन शिशु का वजन दो किलोग्राम या उससे ज्यादा होता है. इधर, सपना पांच बच्चों को जन्म देने के बाद खुश थी, लेकिन अब उसे यह चिंता सता रही है कि कहीं भगवान बचे हुए दो बच्चों को भी न छीन ले. ■

आज तक विश्व के किसी भी देश ने दुख प्रकट करने और अफसोस व्यक्त करने के सिवा आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए न तो सार्थक प्रयास किया और न ही ये देश एकजुट हुए, जबकि इन हमलों में ब्रिटेन, घाना, चीन, फ्रांस, अमेरिका और नीदरलैंड जैसे देशों के नागरिक भी मारे गए हैं. जबकि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, जो आतंकी घटनाओं से प्रभावित न हुआ हो.

धर्म की आड़ में इंसानियत का क़त्ल

आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता. उनका मक़सद होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत का ख़ून करना. केन्या और उसके बाद पाकिस्तान में किए गए हमलों में हमलावरों ने भले ही ख़ुद को मुस्लिम बताया, लेकिन उन्होंने वहां जो ख़ूनी खेल खेला, वह मुस्लिम या किसी अन्य धर्म की हिफ़ाज़त के लिए नहीं था, बल्कि वह मुसलमानों को बदनाम करने के लिए था, ताकि आतंकियों द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जा सके. सही मायने में देखा जाए तो उनका मक़सद था धर्म की आड़ में इंसानियत का ख़ून. इसीलिए उन्होंने महिलाओं और दुधमुंहे बच्चों को भी नहीं छोड़ा और लोगों के हाथ-पैर तक काट दिए.

राजीव रंजन

तुम किस धर्म को मानते हो? तुम कहां के रहने वाले हो? मोहम्मद साहब की मां का नाम क्या था? ये सवाल उन निरीह लोगों से पूछे गए, जिन्हें पाकिस्तान या केन्या के नैरोबी हमले से पहले यह नहीं पता था कि उनकी हत्या सिर्फ हिंदू, ईसाई या किसी और धर्म को मानने के कारण हो जाएगी. भारत के जम्मू में पिछले दिनों हमले में 10 लोग मारे गए. प्रत्यक्षदर्शी सोहनलाल के अनुसार, वहां आतंकियों ने उससे नाम पूछा. उसने अपना नाम सलीम खान बताया. इसके बाद उन्होंने पूछा-तुम कहां के रहने वाले हो. सोहनलाल ने जवाब दिया-डोडा. इस पर आतंकियों ने उससे कहा-तू अल्लाह का बंदा है, इसलिए हम तुझे छोड़ रहे हैं. सोहनलाल इसलिए बच गया, क्योंकि उसने जो नाम बताया, उसके साथ खान जुड़ा हुआ था. ये सवाल उन आतंकियों ने पूछे, जो खुद को इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं, लेकिन सच पूछा जाए तो वे इस्लाम के नाम पर कलंक हैं. उनकी पहचान सिर्फ एक दहशतगर्द की है. वे आतंकवादी हैं. मानवता के हत्यारे हैं. इन आतंकवादियों को सिर्फ और सिर्फ खून और खून की महक से मतलब है. उन्हें इस्लाम से कुछ मतलब नहीं. उन्होंने जो भी किया, उससे सिर्फ एक खास मजहब बदनाम हुआ. आतंकी अगर अपने काले कारनामों को धर्म की आड़ में इसी तरह से अंजाम देते रहे तो आम मुसलमान का जीना दूभर हो जाएगा. इस्लाम धर्म को मोहरा बना कर ये आतंकी इस्लाम धर्म के प्रति अन्य धर्मों में घृणा पैदा कर रहे हैं. ऐसा कर वे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं. जागरूक मुसलमान ऐसे घृणित विचारों का जबरदस्त विरोध करते हैं. इस्लाम धर्म का मानना है कि किसी भी बेगुनाहों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है. इस्लाम दहशतगर्दी को कभी इजाजत नहीं देता. जेहाद को लेकर आतंकवादी संगठनों द्वारा आम लोगों को गुमराह किया जाता है, जबकि इस्लाम में जेहाद का मतलब है बुरी ख्वाहिशों या आदतों पर काबू पाना.

पाकिस्तान के पेशावर, केन्या के नैरोबी या भारत के जम्मू में हमला अपनी विभीषिका और उसमें छिपे पैगाम, इन दोनों ही लिहाज से इतना अहम है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. पाकिस्तान में 130 साल पुराने चर्च पर यह हमला उस वक्त हुआ, जब वहां की नवाज शरीफ सरकार तालिबान से बातचीत के लिए बेताब नजर आ रही है. नवाज सरकार तालिबान से किसी भी तरह से बातचीत को पटरी पर लाने के लिए लगातार सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित कर रही है और वह चाहती है कि तालिबान और अन्य मजहबी चरमपंथी गुटों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई रोककर उनसे बातचीत की जाए. ये बात समझ से परे है कि ऐसे चरमपंथी गुटों से पाकिस्तान आखिर क्या बात करना चाहता है, जिनकी दहशतगर्दी आतंकवादियों की क्रूर और अमानवनीय मानसिकता को जाहिर करती हैं. प्रश्न यह भी है कि जिन लोगों की ऐसी मानसिकता हो, क्या उनसे बातचीत कर शांति बहाल करने की कोशिश कामयाब हो सकती है. भारत की चिंता इस बात को लेकर जायज है कि पाकिस्तान में बनते-बिगड़ते हालात का भारत के सुरक्षा संबंधी हितों से सीधा संबंध है. इसलिए हम वहां के घटनाक्रम को नजरअंदाज कर नहीं चल सकते. भारत की नजर अमेरिका पर भी है, क्योंकि अमेरिका जल्द ही तालिबान को वैध करार दे सकता है. चर्च पर हमले से एक दिन पहले पाकिस्तान ने तालिबान के बड़े नेता मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को रिहा किया. ताजा हमले के बाद अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सबक लेना चाहिए, लेकिन लगता नहीं कि वे कोई ठोस कदम उठाएंगे.

1 केन्या में गैर मुस्लिमों पर हमला

केन्या के नैरोबी के वेस्टगेट मॉल में आतंकी संगठन अल-शबाब ने हमला करने से पहले मुस्लिमों को जाने को कहा और बाकी बचे गैर मुस्लिमों पर गोलियों की बौछार कर दी. कहा जाता है कि इस हमले के पीछे व्हाइट विडो का हाथ था, जिसका पूरा नाम सामंथा ल्यूथवेट है. व्हाइट विडो के नाम से मशहूर ये आतंकी महिला उसी आत्मघाती हमलावर की बीवी है, जिसने 2005 में लंदन के ट्यूब में आतंकी धमाका किया था. सामंथा ल्यूथवेट 7/7 के हमलावर जर्मेन लिंडसे की विधवा है. 7/7 हमले के कुछ ही दिनों बाद वो पूरे परिवार के साथ लंदन से गायब हो गई थी. बाद में वो सोमालिया के आतंकी संगठन अल शबाब से जुड़े गई और फिर वो व्हाइट विडो के नाम से मशहूर हो गई. ■

2 पाकिस्तान में चर्च में धमाका

पाकिस्तान के पेशावर शहर में ख़ैबर पख़्तून की राजधानी के 100 साल से भी पुराने चर्च पर आत्मघाती हमला हुआ. कोहाटी गेट इलाके में ऑल सेंट्स चर्च में प्रार्थना के बाद लोग बाहर निकल ही रहे थे, तभी दो हमलावर 30 सेकेंड के अंतराल पर उनके पास पहुंचे और खुद को विस्फोट से उड़ा दिया. इससे पहले उन्होंने फायरिंग भी की. घटना के समय वहां लगभग 700 लोग मौजूद थे. धमाका इतना जोरदार था कि कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं. दो आत्मघाती हमले में लगभग 81 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायलों की संख्या खबर लिखे जाने तक 145 तक पहुंच गई थी. यह पाकिस्तानी ईसाई समुदाय पर अब तक का सबसे भीषण हमला था. ■

आतंकियों के नापाक मंसूबे

आतंकियों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दीं हैं. केन्या में आतंकियों ने लोगों को लाइन लगाकर उनसे धर्म पूछा. एक भारतीय ने जवाब दिया-इस्लाम. आतंकी ने इस्लाम संबंधी प्रश्न पूछा. जब वह भारतीय जवाब नहीं दे पाया, तो उसने उसे गोली मार दी. आतंकियों ने गर्भवती महिलाओं को भी नहीं बख्शा. उन्होंने बंधकों के हाथ-पैर भी काट दिए. हमले में मारे गए भारतवंशियों की पहचान तमिलनाडु के 40 वर्षीय श्रीधर नटराजन तथा मनोज जैन के आठ वर्षीय बेटे परमशु जैन के रूप में की गई है. जब परमशु जैन का शव भारत लाया गया तो उनकी मां अपनी सुधबुध खो चुकी थीं. पिता का कहना था कि काश! परमशु को स्कूल भेज दिया होता. उस घटना की चश्मदीद पूर्वी का कहना है कि आतंकवादियों ने हम सभी को घेरने के बाद मुस्लिम महिलाओं को जाने को कहा. यह सुनकर कई औरतें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलीं. आतंकवादियों की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि कौन गैर मुस्लिम महिला है. भागती महिलाओं में से एक महिला को उन आतंकवादियों ने पहचान लिया कि वो गैर मुस्लिम महिला है. इसके बाद उस महिला के दुधमुंहे बच्चे को एक हाथ से एक आतंकी ने ऊपर उठाया और उस पर गोली चला दी. बच्चे को मारने के बाद उन्होंने महिला को भी मार दिया. आतंकी पहले सरकार या सरकार के महकमों को निशाना बनाते थे या वे ऐसी वारदातों को अंजाम देते थे, जिससे सरकार सबसे ज्यादा प्रभावित हो और वे अपनी मांगें मनवा सकें या अपनी मनमानी कर सकें. ये पहली बार है कि उन्होंने मजहब को निशाना बनाया और हिन्दुओं और ईसाइयों या गैर मुस्लिमों को चुन-चुन कर मारा. हालांकि ऐसा कर वे यह भले ही जताना चाह रहे हों कि उनका उद्देश्य इस्लाम धर्म या मुसलमान को बचाना या उनका संरक्षण करना है, लेकिन सत्य इससे काफी दूर है. वे यह सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ताकि वे अपनी मांगे मानने के लिए सरकार को बाध्य कर सकें. उन्होंने यह काम बहुत सोच-समझकर किया है, क्योंकि उनके इस कदम से उन देशों की सरकारें सकते में आ गईं हैं और पूरा विश्व प्रभावित हुआ है सो अलग.

अमेरिका छोड़े अपनी दादागीरी

पाकिस्तान हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान से जुड़े एक चरमपंथी संगठन ने लेते हुए कहा है कि ये क़बायली इलाक़ों में हो रहे अमरीकी ड्रोन हमलों का बदला है. एक बड़ा सवाल आतंकी हमलों से हमेशा ही जुड़ा रहता है कि आखिर विश्व में जितने भी आतंकी हमले होते हैं, उनमें से अधिकांश के पीछे अमेरिकी दादागिरी कारण क्यों बन जाता है. आखिर अमेरिका ने पूरे विश्व में क्यों एक छद्म युद्ध छेड़ दिया है. सच मायने में देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने अपने निजी हितों को साधने के लिए पूरे विश्व को अशांत-सा कर दिया है. जहां एक ओर चीन और रूस जैसे महाशक्तियों से अमेरिका की तनातनी है, वहीं दूसरी ओर छोटे देशों के नाक में अमेरिका ने दम कर दिया है. विश्व के प्रमुख आतंकी संगठन अलकायदा हो या तालिबान, अमेरिका से खार खाए बैठे हैं, इसीलिए वे किसी देश में अमेरिकी हस्तक्षेप या उस देश का अमेरिका से लगाव को सहन नहीं कर पाते और अमुक देश में आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं. हालांकि आतंकी वारदातों को इसके लिए किसी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उनके लिए अमेरिका की ये कार्रवाइयां बहाना जरूर बन जाती हैं.

एकजुट होना होगा

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने केन्या के राष्ट्रपति केन्याता के साथ बातचीत में अपनी चिंता प्रकट की. ब्रिटेन के विदेश मंत्री विलियम हेग ने भी घटना के प्रति चिंता प्रकट की. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी कहा कि ऐसी कार्रवाइयां आतंकवादियों की क्रूर और अमानवीय मानसिकता को जाहिर करती हैं. भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और पूरे विश्व को एकजुट होकर इस तरह की घटनाओं से लड़ने की बात कही, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक विश्व के किसी देश ने दुख प्रकट करने और अफसोस व्यक्त करने के सिवा आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए न तो सार्थक प्रयास किया और न ही ये एकजुट हुए, जबकि इन हमलों में ब्रिटेन, घाना, चीन, फ्रांस, अमेरिका और नीदरलैंड जैसे देशों के नागरिक भी मारे गए हैं.

आर्थिक प्रभाव

भारत की आर्थिक स्थितियां अभी ठीक नहीं हैं. अभी अमेरिका की मार से भारत उबरा भी नहीं था कि केन्या और पाकिस्तान की घटनाओं ने भारत की आर्थिक परिस्थितियों को लपेटे में ले लिया. भले ही लोगों को पहली नजर में इस घटना का आर्थिक प्रभाव नहीं दिखता हो, लेकिन केन्या में आतंकी हमले से भारतीय निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है. केन्या भारत के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य है. भारत केन्या में पांच सबसे बड़े निवेशकों में शामिल है. भारत, केन्या को कपड़ा, पेट्रोलियम उत्पाद, चिकित्सा उपकरण और औषधि, लोहा और इस्पात उत्पाद, बिजली के उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण मशीन, विशेष उपयोग वाले वाहन और ट्रक जैसी चीजों का निर्यात करता है, जिसका सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. केन्या में भारत की कम से कम 40 शीर्ष कंपनियों के कार्यालय हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है. केन्या से भी बड़ी संख्या में युवा भारत में शिक्षा या प्रशिक्षण हासिल करने के लिए आते हैं, जिससे भारत को राजस्व की प्राप्ति होती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं

> शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सवों में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है. कोपरगांव में गोपालराव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे. वे बाबा के परम भक्त थे, उनकी तीन पत्नियां थी, लेकिन एक को भी संतान न थी. साईबाबा की कृपा से उन्हें पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई.

एक बार...

मंदिर-मस्जिद एक समान

चौथी दुनिया ब्यूरो

जब सदगुरु ही नाव के खेवैया हों तो वे निश्चय ही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भवसागर के पार उतार देंगे. श्री साईबाबा के मनोहर रूप के दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भाव की जागृति होकर आत्मानुभव के आनंद का आभास होने लगता है. मैं और तू का भेद (द्वैतभाव) नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ही ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है. जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं. जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण में जाता है, उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही में प्राप्त हो जाते हैं. ईश्वर के पास पहुंचने के चार मार्ग हैं- कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति. इन सबमें भक्तिमार्ग अधिक गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है, लेकिन सद्गुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते और पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाएंगे तो हम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर के समीप आसानी से पहुंच जाएंगे. साईबाबा ने निश्चयात्मक स्वर में कहा है कि स्वयं ब्रह्म और उनकी विश्व उत्पत्ति, रक्षण करने आदि की भिन्न-भिन्न शक्तियों के पृथकत्व में भी एकत्व है. इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है. भक्तों के कल्याणार्थ साई बाबा ने स्वयं इन वचनों से आश्वासन दिया था,

मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा. यह मेरी विशेषता है कि जो भक्त मेरी शरण आ जाते हैं और अंत:करण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूं. कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है, इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता न करो. यदि कुछ मांगने की ही अभिलाषा है तो ईश्वर को ही भिक्षा में मांगो. सांसारिक मान व उपलब्धियां त्यागकर ईश्वर-कृपा तथा अभयदान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हों. किसी वस्तु से आकर्षित न हो, सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो, ताकि वह देह, संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत न हो. इस प्रकार की मन:स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है. यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता है.

शिरडी में मनाये जाने वाले उत्सवों में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है. कोपरगांव में मेंगोपालराव गुंड नाम के एक इंसपेक्टर थे. वे बाबा के परम भक्त थे, उनकी तीन स्त्रियां थी, लेकिन एक को भी संतान न थी. साईबाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई. इस हर्ष के उपलक्ष्य में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स करवाना चाहिए. उन्होंने यह विचार शिरडी के सभी भक्तों के पास विचारणार्थ प्रगट किया. उन सभी को यह विचार पसंद आया तथा उन्हें बाबा की भी स्वीकृत और आश्वासन प्राप्त हो गया. मेले के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना-पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, लेकिन ग्राम कुलकर्णी (पटवारी) के आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त न हो सकी, लेकिन बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो चुका था. अत: पुन: प्रत्यन करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई. बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन मेला का कार्यक्रम निश्चित हुआ. उरूस व रामनवमी के उत्सवों का एकीकरण तथा हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है. प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई. अब द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थित हुई. शिरडी तो एक छोटा सा ग्राम था और पूर्व काल से ही वहां जल का अभाव बना रहता था. गांव में केवल दो कुएं थे, जिनमें से एक तो प्राय: सूख जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था. बाबा ने उसमें फूल डाल कर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को पर्याप्त हो सकता था, इसलिए तात्या पाटील ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया. गोपालपाव गुंड के एक मित्र दामू-अण्णा कासार अहमदनगर में रहते थे. वे भी संतानहीन होने के कारण दु:खी थे. साई बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई थी. गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा. एक ध्वज नानासाहेब निमोणकर ने भी दिया. ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारकामाई के नाम से पुकारते थे, उसके कोनों पर फहरा दिया गया. यह कार्यक्रम अभी पूर्ववत ही चल रहा है इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी श्री गणेश हुआ, जो चंदनोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है. यह कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर सक्कर दलाल की सोच थी. बहुत-सा चंदन घिसकर बहुत सी चंदन-धूप थालियों में भरी जाती है तथा लोहबान जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचा कर जुलूस समाप्त हो जाता है. थालियों का चन्दन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जता है. इस उत्सव का प्रबन्ध प्रथम तीन वर्षों तक अमीर सक्कर ने किया और उनके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया. इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों के द्वारा चन्दन का जुलूस एक साथ चलने लगा और अभी तक उसी तरह चल रहा रामनवमी का दिन साई बाबा के भक्तों के लिए अत्यंत ही प्रिय और पवित्र है. कार्य करने के लिए बहुत से स्वयंसेवक तैयार हो जाते थे और वे मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे. बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटील और भीतर के कार्यों में साई बाबा की एक परम भक्त महिला राधाकृष्णा माई सम्मिलित थी. इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था. साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थीं. दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती, वह था मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना आदि. मस्जिद की फर्श तथा दीवारें निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ गई थी. जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते, तब वे यह कार्य कर लिया करती थी. समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात वे पूर्ववत सजा दी जाती थी. बाबा का अत्यन्त प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का एक अंग था. इस कार्य के लिए बड़ा भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती थी. यह सब कार्य राधाकृष्णमगई के निवासस्थान पर ही होता था. बहुत से भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे. साई बाबा सामाजिक सदभाव के प्रतीक थे. ■

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश,
पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

स्वास्थ्यवर्द्धक आहार ज़रूरी

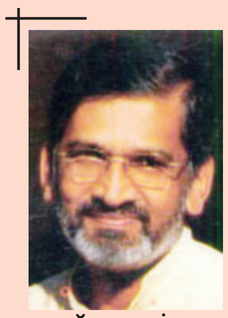

डॉ. अभय बंग

स्वास्थ्य के लिए आहार की जानकारी में बारंबार फाइबर (रेशेदार पदार्थ) की आवश्यकता का उल्लेख आता है. आहार में केवल कैलोरीज व प्रोटीन्स ही महत्व के नहीं होते, फाइबर भी महत्व के होते हैं. रोज के आहार में कम से कम 40 ग्राम फाइबर होना चाहिए, ऐसी भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन ने सिफारिश की है. आहार में पाए जाने वाले फाइबर दो प्रकार के होते हैं.

1. अघुलनशील फाइबर- ये मुख्यत: गेहूं की भूसी में होते हैं, इसके कारण कब्जियत का कष्ट नहीं होता. आटे का चोकर छानकर निकाल दिया जाता है तो बचे हुए मैदे में यह फाइबर नहीं होता. अत: मैदा बुरा और चोकर सहित आटा अथवा उससे बनाई हुई ब्राउन ब्रेड अच्छी होती है.

2. घुलनशील फाइबर- ये शरीर का कॉलस्ट्राल कम करने में मदद करते हैं और खाने के बाद खून में बढ़ने वाली शक्कर को सीमित करते हैं. ये प्रमुख रूप से पालिश न किए हुए चावल, छिलके सहित दालों व बीन्स में होते हैं. कुछ कम अनुपात में गाजर, शकरकंद, आलू, फल, सब्जियों, में होते हैं. मेथी दाने में भरपूर होते हैं.

फाइबरहीन पदार्थ- मैदा, शक्कर, दूध, फैट से बने हुए बेकरी प्रोडक्ट्स, मिठाइयां, अंडे, मांस, मछली ये फाइबरहीन पदार्थ हैं. इन्हें खाना यानी शरीर को अनैसर्गिक आहार की तकलीफ देकर आधुनिक सभ्यता के रोग का निर्माण करना है, यह बात मुझे समझ में आ गई.

मुझे अच्छे लगने वाले अधिकांश पदार्थ को अब छोड़ने की नौबत आ गई थी. ऐसे छोड़ने योग्य पदार्थों का ही शौक मुझे अभी तक था. आज तक बहुत प्यार हो गया है, अब शौक और आदतें बदलने की बारी थी. मैने अपने भोजन में फाइबरयुक्त पदार्थ, पत्ता-सब्जियां, सलाद, अंकुरित अनाज, फल भरपूर बढ़ा दिए. मेथी के भिगोए हुए दाने रोज चार चम्मच खाने लगा. मेथी के दानों में भरपूर फाइबर होता है. उसकी बजह से खून में बढ़ने वाली शर्करा कम बढ़ती है. कॉलेस्ट्राल भी कम होता है. निसर्गोपचार अथवा शाकाहारी आंदोलन का एक तर्क मुझे विचार करने योग्य प्रतीत होता है. आज के मनुष्य का 98 प्रतिशत शरीर आदिमानव के शरीर से ही बना हुआ है. उत्क्रान्ति की गति से मानव शरीर में जैविक बदलाव आने में लाखों वर्ष लगते हैं. गत 10 हजार वर्षों में मानवी शरीर रचना में एक बड़ा जैविक बदलाव नहीं हुआ है. अर्थात हमारा शरीर आदिमानव का ही है, लेकिन जीवनशैली व आहार आमूल बदल गए. पहले पशुपालन अवस्था में, फिर कृषि संस्कृति में, और पिछले सौ वर्षों में उद्योग प्रधान संस्कृति के कारण हमारे आहार में गजब का बदलाव आया. शरीर आदिमानव का परंतु रहन-सहन आधुनिक-इस बेजोड़ संगति के कारण शरीर टूट रहा है. मानो हवाई जहाज के इंजन से बस की बॉडी जोड़ दी गई हो. अब अगर विमान की गति से चलेगी तो, बस की बॉडी चरमराएगी ही न.

> **शाकाहारी आंदोलन का एक तर्क मुझे विचार करने योग्य प्रतीत होता है. आज के मनुष्य का 98 प्रतिशत शरीर आदिमानव के शरीर से ही बना हुआ है. मानव शरीर में जैविक बदलाव आने में लाखों वर्ष लगते हैं. पिछले 10 हजार वर्षों में मानव की शरीर रचना में एक भी बड़ा जैविक बदलाव नहीं हुआ है. अर्थात हमारा शरीर आदिमानव का ही है, लेकिन जीवनशैली व आहार आमूल बदल गए.**

मैंने विचार किया, हमारे मूल पूर्वज थे कौन? करीब-करीब तीस लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के विक्टोरिया सरोवर के आसपास पैदा हुई एक आदिमानुषी को जिसकी केवल हड्डियां मिली हैं, वैज्ञानिक सारी आदिमानव जाति की आदिमाता मानते हैं. उसको उन्होंने ल्यूसी नाम दिया है. हम सबका बहुतांश शरीर 98 प्रतिशत जींस, उस काल के आदिमानव से ही प्राप्त हुए हैं. हमारी जड़े ल्यूसी में ही हैं. मैं विचार करने लगा, ल्यूसी क्या खाती होगी? किस प्रकार अन्न के लिए उसका शरीर बना होगा? उस समय पशु भी नहीं पाले जाते थे अतएव दूध, घी इत्यादि भी नहीं थे. फिर हमारी यह परनानी ल्यूसी क्या खाती होगी?

शायद उसका आहार बंदर जैसा होगा. अर्थात नैसिर्गक रूप से पाई जाने वाली वनस्पतियों से मिलने वाला आहार, पत्ते, कंदमूल और फल, उसमें भरपूर फाइबर रहता होगा. ऐसा नैसर्गिक आहार खाने वाले बंदर, गाय आदि को कब्ज होते हुए किसी ने देखा है? आधुनिक मानव का शरीर जैविक स्तर पर अभी भी उसी ल्यूसी के आहार के बिना बना हुआ है और मेरे मरने तक या उससे भी आगे हजारों वर्षों तक यह मानव शरीर नहीं बदलेगा. फिर मैं अपना आहार ल्यूसी के आहार के थोड़ा करीब कैसे लांऊ?

शोधग्राम में ल्यूसी- आहार जैसी खाने की चीजें बनाने की प्रतियोगिताएं शुरू कीश्रविवार को हाट बाजार से खरीदारी करके आने पर सोमवार को सब लोग अपनी-अपनी कल्पना से नई-नई चींजे बनाने लगे. पत्ती-भांजी, चटनियां, सलाद, सूप. आगे चलकर मजे के लिए एक बार बिना दूध की खीर बनाने की प्रतियोगिता हुई. उसमें इतने प्रकार के शाकखीर के व्यंजन प्रस्तुत किए गए कि शोधग्राम निवासियों की कल्पनाशक्ति से मैं चकित रह गया. पढ़ते-पढ़ते एंटी-ऑक्सीडेंट नाम एक की नई चीज से सामना हुआ. शरीर में नैसर्गिक रासायनिक प्रक्रियाओं में फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स बनते रहते हैं. ये कॉलेस्ट्राल (एल.डी.एल घटक) से संयोग करके रक्तनलिकाओं में रुकावट करने वाले रोग पैदा करते हैं. वैसे ही वे कैंसर पैदा करते हैं. शारीरिक रोग पैदा करने में और बुढ़ापा लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. कढ़ाई में उबलते तेल में तले हुए पदार्थ बनाते समय(पकौड़े, समोसे, कचौरी, पूरी) इन फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है. सौभाग्य से भोजन के कुछ घटक एंटी-ऑक्सीडेंट, इन फ्री-ऑक्सीजन रेडिकल्स से शरीर का बचाव करते हैं. इन ऑक्सीडेंट्स पर आज-कल खूब खोज चल रही है और इनसे बड़ी उम्मीदे हैं. फल, हरी, सब्जियां, आदि में एंटी-ऑक्सीडेंट गुणधर्म होते हैं. फिर से विज्ञान की सुई आहार के उसी विशिष्ट प्रकार, फाइबर युक्त शाकाहार की ओर इंगित कर रही है. मेरे शरीर की हर कोशिका में स्थित ल्यूसी लाखों वर्षों बाद भी अपना प्रभाव और प्रभुत्व जमा रही है. ■

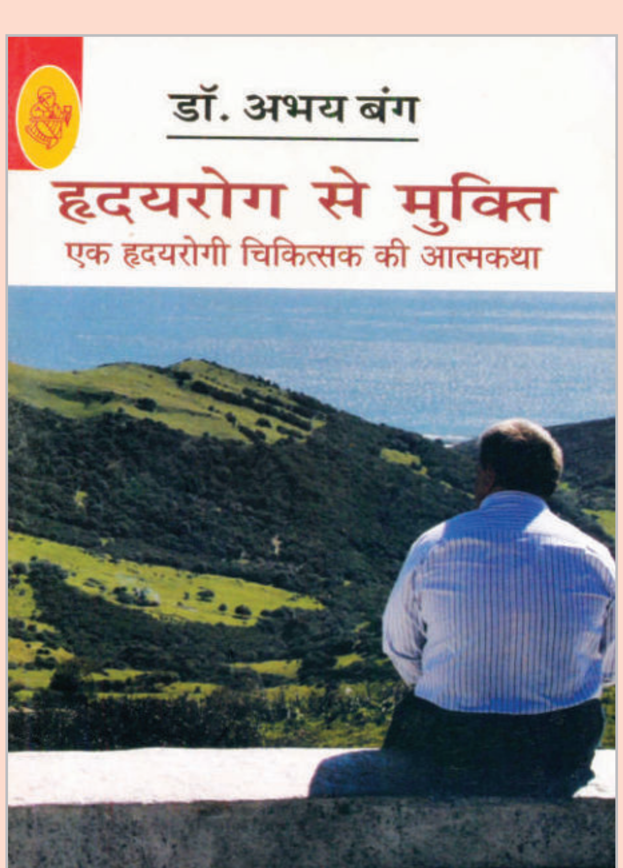

राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

आत्मज्ञान

विश्व प्रसिद्ध संत तिरुवल्लुवर एक बार अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे. रास्ते में एक आदमी मिला. उसने संत तिरुवल्लुवर से कहा-आप लोगों से यह क्यों कहते फिरते हैं कि शराब घृणित चीज है, मत पिया करो. क्या अंगूर खराब और चावल बुरी चीज है? अगर ये दोनों चीजें अच्छी हैं तो इनसे बनने वाली शराब कैसे बुरी हो गई?

संत मुस्कराकर बोले-भाई, अगर तुम पर मुट्ठी भरकर कोई मिट्टी फेंके या कटोरा भर कर पानी डाल दे तो क्या इससे तुम्हें चोट लगेगी?

शराबी ने ना में सिर हिलाया तो संत ने फिर कहा-लेकिन इसी मिट्टी में पानी मिलाकर उसकी ईंट बनाकर तुम पर फेंकी जाए तब..?

शराबी ने कहा-जाहिर सी बात है, उससे तो मैं घायल हो जाऊंगा.

संत तिरुवल्लुवर ने शराबी को फिर समझाते हुए कहा-भाई, जब मिट्टी में पानी मिलाकर उसकी ईंट बनाकर तुम पर फेंकी जाए तब तुम उससे घायल हो जाओगे. इसी प्रकार अंगूर और चावल भी अपने आप में बुरे नहीं हैं. मगर यदि इन्हें मिलाकर शराब बनाकर सेवन किया जाए तो यह मनुष्य के लिए नुकसानदेह है. दोस्तों, संत की इस बात का उस शराबी पर गहरा असर पड़ा और उसने उस दिन से शराब से तौबा कर ली. यही नहीं वह दूसरों को भी शराब छोड़ने की सलाह देने लगा और उसका जीवन बदल गया.

शिक्षा: समझदार के लिए इशारा ही काफी है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

विश्व साहित्य

यह विडंबना है कि नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने राजनीतिक नेतृत्व के पतन में अहम भूमिका निभाई. वो नेहरू, जिन्होंने जेल से इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर नैतिक शिक्षा दी थी. नेहरू के पत्रों का वो संग्रह अब भी लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं. बाबजूद इस पारिवारिक परिवेश के, इंदिरा गांधी अध्ययन और मनन-चिंतन से दूर रहीं.

साहित्य चिंतन

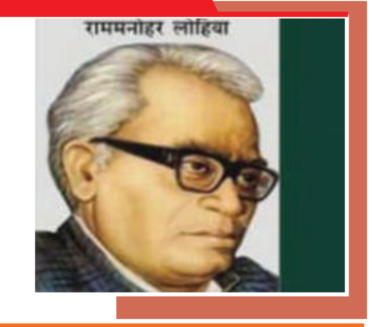

नेतृत्व की विचारशून्यता

आज़ादी आंदोलन के दौरान और उसके बाद नेहरू युग में राजनीतिक बिरादरी में पढ़ने-लिखने का ज़बरदस्त शौक़ था. नेता न सिर्फ़ पढ़ते थे, बल्कि समय-समय पर उन अमूल्य विचारों को व्यक्त भी करते थे. उनकी तुलना में अगर आज हम देखें तो पढ़ने-लिखने वाले विचारवान नेताओं की संख्या बहुत ही कम है. मौलिक चिंतन तो सिरे से ग़ायब ही है. इसकी क्या वजह हो सकती है कि हमारे वर्तमान दौर के नेताओं का पढ़ने-लिखने से वास्ता छूटता चला गया और वो ख़ालिस राजनीति में मशगूल हो गए?

अनंत विजय

एक बेहद दिलचस्प वाक़या है. जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और श्रीकृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री. जवाहर लाल नेहरू की छवि एक पढ़ने-लिखने वाले नेता की थी. वो हर विषय पर सिर्फ़ अपनी राय रखते ही नहीं थे, बल्कि जहां भी मौक़ा मिलता था, उसको लिखकर व्यक्त भी करते थे. उसी दौर की बात है, श्रीकृष्ण सिंह पंडित जवाहर लाल नेहरू से मिलने उस वक्त के प्रधानमंत्री निवास-तीनमूर्ति हाउस पहुंचे. प्रधानमंत्री को संदेश भेजा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण बाबू मिलने आए हैं. तक़रीबन बीस मिनट के बाद जवाहरलाल नेहरू श्रीकृष्ण सिंह से मिलने अपने ड्रॉइंग रूम में पहुंचे. नेहरू जी के हाथ में एक क़िताब थी. अपने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों के साथी का बीस मिनट का इंतज़ार श्रीबाबू को खल गया था. जवाहरलाल जी के आते ही उन्होंने उलाहना देते हुए कहा-अब आपसे मिलने के लिए मुझे भी बीस मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा? जवाहरलाल जी ने विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगते हुए अपने हाथ की क़िताब श्रीबाबू की ओर बढ़ाई और कहा कि ये नई क़िताब आई थी. जब आपके यहां आने की सूचना मिली तो सोचा कि ये नई क़िताब आपको भेंट करूं. इस क़िताब को ढूंढने में ही इतना वक़्त लग गया. श्रीबाबू ने नेहरू जी के हाथ से क़िताब ली, उलटा-पलटा और फ़ौरन धन्यवाद सहित पंडित जी को वापस कर दिया. नेहरू जी हतप्रभ. नेहरू जी के चेहरे का भाव देखकर श्री बाबू ने धन्यवाद दिया और कहा कि वो उस क़िताब को दो महीने पहले पढ़ चुके हैं. नेहरू जी ने अपने चिरपरिचित अंदाज़ में ठहाका लगाया और दोनों फिर से राजनीतिक बातों में मशगूल हो गए. ये संवाद था एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के बीच का. इस क़िस्से को बताने का मक़सद सिर्फ़ इतना बताना है कि आज़ादी के बाद के दौर के हमारे ज़्यादातर नेता अपना काफ़ी वक़्त अध्ययन, चिंतन और मनन में बिताते थे. एक से एक पढ़ाकू और लिक्खाड़. बिहार के मुंगेर में श्रीकृष्ण सेवासदन के नाम से एक पुस्तकालय है. इस पुस्तकालय में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की तमाम क़िताबें भरी हैं. मैं नब्बे के दशक के शुरुआती वर्षों में वहां जाया करता था. उस वक़्त श्रीबाबू के व्यक्तिगत संग्रह को देखकर आतंकित होता रहता था. उन क़िताबों में इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन से लेकर समकालीन विश्व राजनीति की तमाम क़िताबें थीं. ख़ास बात यह थी कि हर क़िताब में रंगीन पेंसिल से निशान लगाए हुए थे. वहां मौजूद सज्जन ने बताया कि श्रीबाबू क़िताबों को पढ़ने के दौरान अलग-अलग रंगों की पेंसिल से निशान लगाते थे. तब गूगल का ज़माना नहीं था. अध्ययन और स्मृति के सहारे ही ज्ञानार्जन होता था.

इसके अलावा भी अध्ययन और चिंतन करनेवाले नेताओं की

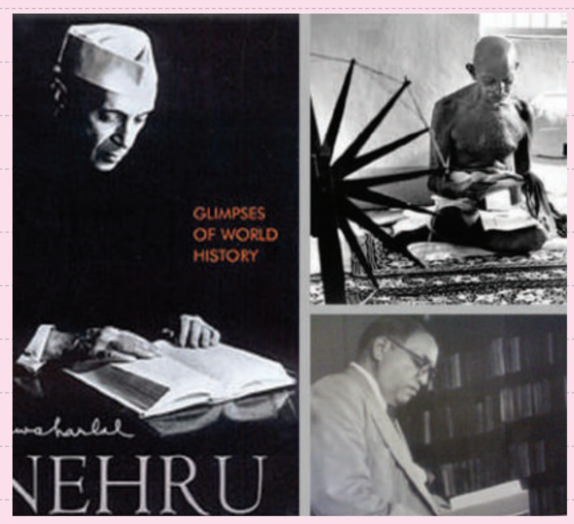

एक लंबी फेहरिश्त है. चाहे आप पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करें, चाहे मौलाना आज़ाद की या फिर सी राजगोपालाला-चारी की या फिर भीमराव अंबेडकर की या एम एलस गोलवलकर की. उस दौर के अन्य नेताओं के बारे में बात करें तो भी उनके हिस्से में कई मौलिक क़िताबें हैं. उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हिंदी से लेकर अन्य भारतीय भाषाओं के नेता पाठक भी थे और लेखक भी. गांधी जी ने तो इतना लिखा कि उनके लेखन के बारे में कुछ कहना सूरज को दीया दिखाने जैसा है. गांधी के लिखे पर तो अब भी दुनिया भर के विद्धान क़लम चलाते रहते हैं और उनको नये सिरे से समझने और उनके विचारों को पुनर्उद्घाटित करने में लगे रहते हैं.

उनकी तुलना में अगर आज हम देखें तो पढ़ने-लिखने वाले विचारवान नेताओं की संख्या बहुत ही कम है. लिखकर अपने विचार व्यक्त करने वाले तो और भी कम. मौलिक चिंतन तो सिरे से ग़ायब ही मालूम पड़ता है. इतना अवश्य है कि पत्रकारिता की पृष्ठभूमि से जो लोग राजनीति में गए हैं, वो यदा कदा लिखते हैं. इसकी क्या वजह हो सकती है कि हमारे देश के वर्तमान दौर के नेताओं का पढ़ने-लिखने से वास्ता छूटता चला गया और वो ख़ालिस राजनीति में मशगूल हो गए? इसकी वजह की तलाश में हमें इंदिरा युग में जाना होगा. भारत की राजनीति में जिस तरह से नेहरू युग को मूल्यों और प्रतिभा की राजनीति का दौर माना जाता है, उसी तरह से इंदिरा युग में प्रतिभाहीन नेताओं और चापलूसों के शीर्ष पर पहुंचने का स्वर्णकाल कहा जा सकता है. इंदिरा गांधी के दौर में विचार और विचारक नेता पृष्ठभूमि में चले गए. प्रतिभाशाली नेता दरकिनार होते चले गए और इंदिरा गांधी प्रतिभाहीन नेताओं से घिरती चली गईं. *इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया* का जयकारा लगाने वाले लोग अचानक से सत्ता के गलियारों में शक्तिशाली नज़र आने लगे. यह विडंबना है कि जवाहर लाल की बेटी इंदिरा गांधी ने इस तरह से राजनीतिक नेतृत्व के पतन में अहम भूमिका निभाई. वो नेहरू, जिन्होंने जेल से इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर नैतिक शिक्षा दी थी. नेहरू के पत्रों का वो संग्रह अब भी लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं. नेहरू हमेशा से इंदिरा को शिक्षा देते रहते थे. मार्च, 1926 में अपने नवजात बेटे की मौत के बाद जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी और बेटी के साथ मुंबई से पानी के जहाज़ से वेनिस जा रहे थे. जब उनका जहाज़ स्वेज नहर से गुज़र रहा था तो उन्होंने इंदिरा गांधी से मिस्र की सभ्यता के बारे में बेहद लंबी बातचीत की और एतिहासिक सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बताया. बाबजूद इस पारिवारिक परिवेश के, इंदिरा गांधी अध्ययन और मनन-चिंतन से दूर रहीं. राजेन्द्र पुरी ने 1975 में छपी अपनी किताब- इंडिया दे वेस्टेड इयर्स में लिखा है- इंदिरा गांधी का अपना कोई स्टाइल नहीं था. वो हमेशा नेहरू की अदाओं की नक़ल करती थीं, चाहे तेज़ चलना हो, भीड़ में घुस जाना हो या फिर भीड़ को डांट देना हो, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग इन अदाओं में उसके पिता की छवि देखते हैं. उस छवि को इंदिरा ज़िंदा रखना चाहती थीं. लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी नेहरू की लिखने-पढ़ने वाले नेता की छवि की चिंता नहीं की.

नेहरू के दौर के ही कुछ नेताओं ने लिखने-पढ़ने का काम जारी रखा, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी और राम मनोहर लोहिया प्रमुख हैं. इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह ने भी अपनी आत्मकथाएं लिखीं हैं, नटवर सिंह ने भी कई क़िताबें लिखीं. कुछ वामपंथी नेताओं ने आयातित विचारधारा के आधार पर लेखन किया, जिसे नजरअंदाज़ नहीं करना चाहिए. लेकिन ज़्यादातर नेता पढ़ने-लिखने से ज़्यादा गणेश परिक्रमा कर अपनी सत्ता बचाने में लगे हैं. इस वक़्त के नेताओं पर गौर करें तो पूरे परिदृश्य में एक अजीब तरह की विचारशून्यता दिखाई देती है. नेताओं के विचारों को जानने-समझने का अवसर प्राप्त नहीं होता है. अभी के परिदृश्य में शशि थरूर सबसे गंभीर काम कर रहे हैं. बुद्धिजीवी बनने के चक्कर में नेता लोग अपने भाषणों का संग्रह छपवाने में जुटे हैं. प्रकाशक इस वजह से छाप देते हैं, क्योंकि उसमें उनको कारोबारी संभावना नज़र आती है. दरअसल, गिरावट समाज के हर क्षेत्र में आई है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व को जनता दूसरे नज़रिये से देखती है और उनके क्रियाकलापों का असर होता है, लिहाजा उनसे अपेक्षाएं भी होती हैं. इन अपेक्षाओं पर खरे उतरने को अगर आज के नेता स्वीकार करने का साहस दिखा पाते हैं तो विचारक नेताओं का स्वर्णिम युग लौट सकता है. कहावत भी है कि-इतिहास अपने को दोहराता है. इस कहावत को कहने वाले ने हालांकि इतिहास के दोहराने की समय सीमा नहीं बताई थी. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं.)

anant.ibn@gmail.com

कविता

मन का देश

विपिन चौधरी

मन के मानचित्र पर
पूर्वी हवाएं आकर दरख़्तों की ज़ुल्फ़ें बिखेर देती हैं
मन के आहते में
रखी एक बड़ी सी मेज़ पर
तुम्हारी याद का दस्तरख़ान बिछा हुआ है

मन के भीतर फूटते रास्तों की कहानी भी कम रोचक नहीं
एक बड़े से माल रोड से निकलती सड़क
एक कोने में जा कर गुम हो जाती है
छोटी-छोटी गलियां हिचकते हुए जैसे अपने लिए
क़दमों का जुगाड़ करती हैं

मन के बीचो-बीच एक बड़ा-सा चौबारा है
जहां उम्मीदों के बेल बूटे तराशे हुए हैं.
नज़दीक ही सुख के फूलों से लदे-फंदे हरे-भरे दरख़्त हैं
झड़े हुए पीले पत्तों का दूर तक शासन है

ऐसे में एक भूला भटका मुसाफ़िर
उस लड़की का पता-ठिकाना पूछता है
जो कभी ख़ूब बोलती है और कभी चुप रहती है

मैं जैसे नींद से जागती हूं
और हड़बड़ाते हुए बोल उठती हूं
कहो, कौन हो तुम?

विश्व साहित्य

बुकर पुरस्कार की दौड़ में बंगाली कहानी

कृष्णकांत

भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका झुंपा लाहिड़ी को उनके नये उपन्यास *द लोलैंड* के लिए *मैन बुकर* और अमेरिका के *नेशनल बुक अवॉर्ड* के लिए नामित किया गया है. *द लोलैंड* 1960 के दशक में कोलकाता में रहने वाले दो भाइयों सुभाष और उदयन की कहानी पर आधारित है, जो नक्सली आंदोलन से प्रभावित होकर राजनीति में सक्रिय होते हैं. अप्रवासी भारतीयों को अपने लेखन का विषय बनाकर कहानियां रचने वाली झुंपा लाहिड़ी ने इस बार एकदम अलग विषय चुना है.

भारतीय मूल की लेखिका झुंपा लाहिड़ी एक बार फिर चर्चा में हैं. *पुलित्ज़र* पुरस्कार विजेता इस लेखिका को उनके नये उपन्यास *द लोलैंड* के लिए अमेरिका *नेशनल बुक अवॉर्ड* के लिए उपन्यास श्रेणी में नामित किया गया है. इसके अलावा इसी उपन्यास के लिए उन्हें प्रतिष्ठित *मैन बुकर* पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है. बुकर के लिए लाहिड़ी के अलावा पांच अन्य लेखक दौड़ में हैं, जिनमें से तीन महिलाएं हैं. इसकी घोषणा 15 अक्टूबर को होनी है. जबकि नेशनल बुक अवॉर्ड की दौड़ में लाहिड़ी के द लोलैंड के साथ टॉम ड्रूरी का पेसिफिक, एलिजावेथ ग्रैवर्स का द एंड ऑफ द प्वाइंट और रचेल कुशनर का द फ्लेमथ्रोअर्स भी है. नेशलन बुक फाउंडेशन की ओर से कहा गया है कि अंतिम दौर में पहुंचने वाले लेखकों के नाम की घोषणा 16 अक्टूबर को होगी और विजेता का नाम 20 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा.

द लोलैंड 1960 के दशक में कोलकाता में रहने वाले दो भाइयों सुभाष और उदयन की कहानी पर आधारित है. इस उपन्यास की समीक्षा में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि लाहिड़ी ने भारतीय अप्रवासियों के अमेरिका में ख़ुद को ढालने की कोशिश की ध्यानपूर्वक पड़ताल कर लिखी गई कहानियों से अपनी पहचान बनाई थी. उनका नया उपन्यास *द लोलैंड* इसके विपरीत आश्चर्यजनक रूप से पेश किया पेश किया गया ओपरा है. यह निश्चित ही लाहिड़ी का सबसे महत्वाकांक्षी कार्य है. उदयन एक आदर्शवादी छात्र है, जो माओ से प्रभावित क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय है. उपन्यास की शुरुआत में ही राजनीतिक हिंसा में उदयन की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसका प्रतिबद्ध और कर्त्तव्यनिष्ठ भाई सुभाष उसकी गर्भवती विधवा गौरी से शादी कर लेता है. वह उसे लेकर भारत से अमेरिका जाता है और इस तरह वे नये देश में नई शुरुआत की कोशिश करते हैं. हालांकि, उनकी शादीशुदा जिंदगी उदयन की यादों से प्रभावित होती है. कहानी में यह भी देखने में आता है कि गौरी के भीतर तमाम भयावह रहस्य जज्ब हैं. लाहिड़ी की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि वे अपने पात्रों की भावुकता और मन:स्थिति को विस्तार से पकड़ती हैं और बेहद नाटकीय अंदाज में गद्य रचती चलती हैं.

उदयन प्रेरणा देने वाला भाई है, लेकिन स्वभाव से बाग़ी है. उसके बिना सोचे-समझे निर्णय उसे प्रेम करने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं. सुभाष स्वभाव से शालीन और तार्किक है जो अपने भाई की करतूतों की वजह आई परेशानियों से लड़ते हुए जीवन का ज़्यादातर हिस्सा बिता देता है. वहीं गौरी एक गुस्सैल और स्वार्थी स्त्री है. सुभाष उसे नई ज़िंदगी देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उदारता और करुणा के बदले में गौरी उसकी अवहेलना करती है. सुभाष की मां उसे गौरी से शादी करने से रोकते हुए कहती है कि वह उदयन की बीवी है, तुम्हें प्रेम नहीं करेगी और उसका स्वभाव जैसा है, वह एक मां के प्रकृति से बहुत दूर है. बाद में सुभाष की मां की यह बातें सच साबित होती हैं, जब गौरी उदयन से पैदा हुई अपनी बेटी को अपनी दर्शन की पढ़ाई और अकादमिक कॅरियर को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ देती है, जिसे सुभाष ने उसके साथ मिलकर बड़े प्रेम से पाला था. कहानी में गौरी का चरित्र बेहद क्रूर रूप में सामने आता है.

इससे पहले झुंपा लाहिड़ी को 2000 में कहानी संग्रह *इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़* के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया था. इस पुस्तक के लिए उन्हें पीईएन-हेमिंग्वे अवॉर्ड भी मिला था. इसमें झुंपा ने अमेरिका में भारतीय अप्रवासियों को विषय बनाया था. यह पुस्तक काफी चर्चित रही थी. 2003 में उनका चर्चित उपन्यास आया *द नेमसेक*. इसपर फिल्मकार मीरा नायर ने इसी नाम से फिल्म बनाई. इसके अलावा उनका एक अन्य कहानी संग्रह है-*अनअकस्टम्ड अर्थ* जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स बुक रिव्यू में शीर्ष दस पुस्तकों में जगह दी गई थी. 46 वर्षीय झुंपा लाहिड़ी लंदन में जन्मी हैं और न्यूयॉर्क के ब्रूकलिन में रहती हैं. उनके माता पिता कोलकाता से लंदन जाकर बस गए थे. झुंपा लाहिडी अप्रवासियों को लेकर किए गए अपने लेखन को लेकर जानी जाती हैं, हालांकि, द *लोलैंड* की कहानी में उन्होंने अपनी इस पहचान को तोड़कर भारत की उत्तर उपनिवेशवादी राजनीति और समाज को विषय बनाया है. द *लोलैंड* की कहानी के बारे में लाहिड़ी कहती हैं कि यह किताब एक बेहद दुखद घटना पर आधारित है. घटना तब की है जब मैं अपनी किशोरावस्था में थी और पहली बार भारत आई थी. हिंसक राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय दो भाइयों को उनके परिजनों के सामने मारा जाता है. वे कहती हैं कि इस घटना के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मैं दहल गई और अंतत: इसने मुझे किताब लिखने को प्रेरित किया. हालांकि, अपने उपन्यास में उन्होंने घटना को जस का तस न लिखकर उसमें फेरबदल भी किया है. बकौल लाहिड़ी, मैंने सोचा कि यह बहुत ही दिलचस्प होगा कि दो भाइयों में विरोधाभास पैदा किया जाए, एक राजनीति में सक्रिय है और दूसरा उससे दूर है. मेरा ख्याल था कि यह दोनों भाइयों में स्वाभाविक द्वंद्व पैदा करेगा.

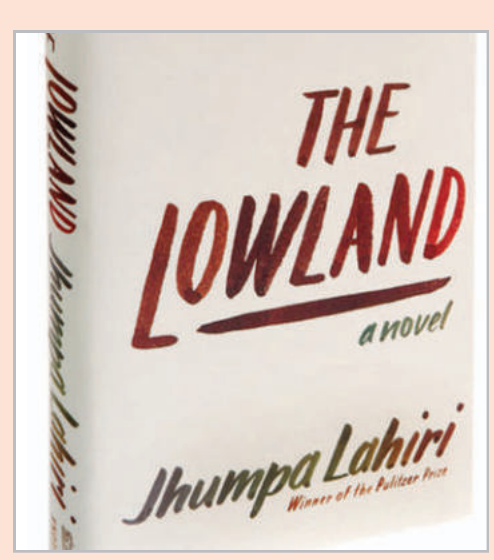

द *लोलैंड* की कहानी के बारे में लाहिड़ी कहती हैं कि यह किताब एक बेहद दुखद घटना पर आधारित है. घटना तब की है, जब मैं अपनी किशोरावस्था में थी और पहली बार भारत आई थी. हिंसक राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय दो भाइयों को उनके परिजनों के सामने मारा जाता है. इस घटना के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मैं दहल गई और अंतत: इसने मुझे किताब लिखने को प्रेरित किया.

बहरहाल, झुंपा लाहिड़ी अपनी इस किताब को लेकर चर्चा में हैं और दो-दो पुरस्कारों के लिए नामित हो चुकी हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही मैन बुकर और यूएस नेशनल बुक अवॉर्ड झुंपा लाहिड़ी की झोली में होंगे. ■

एयरसेल के मुख्य विपणन अधिकारी अनुपम वासुदेव और माइक्रोमैक्स के सह संस्थापक विकास जैन ने बताया कि माइक्रोमैक्स के नए हैंडसेट खरीदने वाले और एयरसेल का नया कनेक्शन लेने वालों ग्राहकों को तीन महीने तक करीब 12 हजार रुपये की सेवाएं मुफ्त दी जाएगी.

रेल यात्रियों के लिए खास ऐप

आईआरसीटीसी ने यह नया ऐप माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर बनाया है. कहा जा रहा है कि इस ऐप से ई-टिकटिंग तक यूजर की पहुंच और अधिक होगी. इस ऐप के जरिये यूजर ट्रेनों का पूरा ब्योरा, ट्रेन रूट मैप, ऑनलाइन कैंस्लेशन और प्रीवियस हिस्ट्री जैसे ऑप्शंस एक क्लिक से पा सकेंगे.

भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की ओर से रेल यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट के अलावा विंडोज़ फोन और विंडोज़ 8 के लिए नया ऐप शुरू किया है, जिसके जरिये ई–टिकटिंग की सुविधा का फायदा उठाया जा सकता है. आईआरसीटीसी ने यह नया ऐप माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर बनाया है. कहा जा रहा है कि इस ऐप से ई–टिकटिंग तक यूजर की पहुंच और अधिक होगी. इस ऐप के जरिये यूजर ट्रेनों का पूरा ब्योरा, ट्रेन रूट मैप, ऑनलाइन कैंस्लेशन और प्रीवियस हिस्ट्री जैसे ऑप्शंस एक क्लिक से पा सकेंगे. इसके लॉन्च के बाद आईआरसीटीसी के सीएमडी राकेश टंडन ने कहा कि इस ऐप के जरिये हम बुकिंग का एक और विकल्प लोगों को मुहैया करा रहे हैं. इससे यात्रियों को ई–टिकट बुक कराने में ज्यादा सहूलियत होगी. वैसे यह ऐप विंडोज़ डिवाइसेज़ के लिए ही है. यानी विंडोज फोन, विंडोज 8 डेस्कटॉप, टैबलट के लिए तो काम का है ही साथ ही विंडोज़ 8 इस्तेमाल करने वाले लैपटॉप/डेस्कटॉप यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार विंडोज़ फोन स्टोर और विंडोज़ स्टोर से यह ऐप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि रेलवे के वर्तमान गाइडलाइन्स के मुताबिक, यह सुविधा सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और रात 11:30 से 12:30 तक काम नहीं करेगी. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ब्लैकबेरी का नया फोन

ब्लैकबेरी ने भारत में नया स्मार्टफोन ब्लैकबेरी 9720 लॉन्च कर दिया है. ब्लैकबेरी 9720 कंपनी के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी ओएस 7.1 पर चलता है. इसमें 806 मेगाहर्ट्ज के प्रोसेसर के साथ 512 एमबी रैम है. इसमें क्वार्टी की–पैड के साथ 2.8 ईंच की टचस्क्रीन भी है. स्क्रीन में 214 पीपीआई (पिक्सल/ईंच) पिक्सल डेंसिटी के साथ 480–360 पिक्सल्स का रेजॉल्यूशन है. ब्लैकबेरी 9720 में मल्टीकास्ट फीचर है, जिसकी मदद से कई सोशल नेटवर्क्स पर एक साथ पोस्ट डाली जा सकती है. इस फोन में ब्लैकबेरी मेसेंजर (बीबीएम) के लिए अलग बटन दिया गया है. इसमें 512 एमबी इंटरनल स्टोरेज है और 32 जीबी तक का मेमरी कार्ड लगाया जा सकता है. कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 3जी, वाई–फाई, ब्लूटूथ और जीपीएस शामिल हैं. एलईडी फ्लैश के साथ 5 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है. हालांकि इसमें फ्रंट कैमरा नहीं है. इसमें स्टीरियो एफएम रेडियो और 1450 एमएच की बैटरी है. इसकी कीमत 15,990 रुपये रखी गई है. कंपनी ने अभी इसको काले और सफेद रंग में उतारा है. यह फोन बाद में नीले रंग में भी आएगा. ■

टीवीएस का ज्यूपिटर

वाहन बनाने वाली टीवीएस मोटर कंपनी ने स्कूटर सेगमेंट में अपना 110 सीसी ज्यूपिटर मॉडल लॉन्च किया है. इस सेगमेंट में कंपनी का यह चौथा प्रोडक्ट है. स्कूटी पेप, स्कूटी स्ट्रीक और वेगो जैसे मॉडल कंपनी के पास पहले से ही मौजूद हैं. ज्यूपिटर का पावरट्रेन 5.88 केडब्ल्यू (8 बीएचपी) की मैक्सिमम पावर देता है. इसका फ्यूल टैंक 5 लीटर का है. कंपनी का दावा है कि यह 62 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है. इसमें 17 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी है. ज्यूपिटर टाइटेनियम ग्रे, मरक्यूरी व्हाइट, मिडनाइट ब्लैक और वोल्कैना रेड कलर्स में उपलब्ध है. इसकी कीमत है 44,200 रुपये. ■

लेनोवो का गेमिंग लैपटॉप

लेनोवो ने भारत में गेमिंग लैपटॉप और ऑल–इन–वन डिवाइस लॉन्च किए हैं, जिसमें ऑल–इन–वन आइडिया सेंटर होराइज़न 27, आइडिया पैड वाई510पी और आइडिया पैड ज़ेड510 शामिल हैं. ये तीनों विंडोज़ 8 पर चलते हैं और कंपनी के मुताबिक यह बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए हाई–परफॉर्मेंस ग्राफिक्स और ऑडियो से लैस हैं. ■

लेनोवो आइडिया सेंटर हॉरिजन 27

यह ऑल–इन–वन पीसी मल्टी टच सपोर्ट करता है और आम टैबलेट के दोगुने से ज्यादा बड़ा है. इसमें 27 ईंच का डिस्प्ले है. इसमें इंटेल कोर आई7 (थर्ड जेनरेशन–आईवी ब्रिज) प्रोसेसर है. इसमें डायरेक्ट एक्स 11 के साथ एनवीडिया जीफोर्स जीटी 620एम 1 जीबी/2 जीबी ग्राफिक्स है. डॉल्बी होम थियेटर के साथ स्टीरियो स्पीकर्स हैं. इसका वजन 8.6 किलो है. ■

लेनोवो आइडिया पैड वाई 510 पी

इस गेमिंग लैपटॉप में 15.6 ईंच का फुल एचडी एलईडी ग्लेयर डिस्प्ले है. इसमें इंटेल कोर आई7 प्रोसेसर (फोर्थ जेनरेशन–हैसवेल) है. इसमें ड्यूल एनवीडिया जीफोर्स जीटी 750एम 2 जीबी ग्राफिक्स है. इसमें 8 जीबी रैम और 1 टीबी हार्ड डिस्क ड्राइव है. बाकी फीचर्स में टचपैड के साथ बैकलिट ऐक्युटाइप की–बोर्ड, यूएसबी 3.0, एचडीएमआई आउटपुट और 720 एचडी वेबकैम शामिल हैं. इसमें डॉल्बी होम थियेटर वी4 के साथ जेबीएल स्पीकर्स हैं. यह डस्क ब्लैक कलर में है. ■

लेनोवो का नया गेमिंग लैपटॉप

इस गेमिंग लैपटॉप में 15.6 ईंच का डिस्प्ले है. इसमें इंटेल कोर आई7 प्रोसेसर (फोर्थ जेनरेशन – हैसवेल) है. इसमें 16 जीबी रैम है. इसमें बड़े डिस्प्ले पर कॉन्टेंट स्ट्रीमिंग के लिए इंटेल वायरलेस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है. इसमें वन–की रिकवरी है, जिससे डेटा बैकअप और रिकवरी आसान हो जाती है. इसमें डॉल्बी थियेटर सर्टिफिकेशन के साथ स्टीरियो स्पीकर्स हैं. ■

एयरसेल और माइक्रोमैक्स की साझेदारी

एयरसेल ने अपने डाटा कारोबार को बढ़ाने के उद्देश्य से मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी माइक्रोमैक्स के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की. इसके तहत नये ग्राहकों को तीन महीने तक करीब 12 हजार रुपये की सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी.

एयरसेल के मुख्य विपणन अधिकारी अनुपम वासुदेव और माइक्रोमैक्स के सह संस्थापक विकास जैन ने इसकी घोषणा की. उन्होंने बताया कि माइक्रोमैक्स के नए हैंडसेट खरीदने वाले और एयरसेल का नया कनेक्शन लेने वालों के लिए यह यह खास पेशकश की गई है. इस करार से दोनों कंपनियों को प्रति महीने तीन लाख से अधिक ग्राहक मिलने की उम्मीद है. नये हैंडसेट में नया सिम लगाने पर मुफ्त सेवाएं स्वत: चालू हो जाएंगी. वासुदेव ने बताया कि माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन (थ्रीजी) के ग्राहकों को तीन महीने तक स्थानीय कॉलिंग के लिए एक पैसा प्रति दो सेकेंड और एसटीडी एक पैसा प्रति सेंकेड का भुगतान करना होगा. इस अवधि में प्रति महीने दो जीबी डाटा और 10 हजार रुपये मूल्य का डव्ल्यूएपी कंटेंट मुफ्त मिलेगा. इस दौरान पॉपकार्न टीवी, इंटरनेट टीवी, एप्लिकेशन का मुफ्त में उपयोग किया जा सकेगा. ■

अब मोबाइल नंबर नहीं बदलना पड़ेगा

अब जल्द ही आपको नंबर बदलने की झंझट से छुटकारा मिलने वाला है. पहले शहर बदलते ही नंबर बदलने की मजबूरी बन जाती थी, लेकिन अब आपको इससे निजात मिलने जा रही है. दूरसंचार नियामक ट्राई अगले छह माह में फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने जा रही है. इसके तहत ग्राहकों को एक टेलीकॉम सर्किल से दूसरे सर्किल में जाने पर भी अपना नंबर बरकरार रखते हुए दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर की सेवा लेने की सुविधा मिलेगी. ट्राई ने ग्राहकों को एमएनपी का असली लाभ दिलाने के लिए सिफारिश की है. एमएनपी के तहत अभी तक ग्राहकों को केवल एक ही सर्किल में ऑपरेटर बदलने की सुविधा है. राष्ट्रीय स्तर पर एमएनपी लागू होने के बाद सर्किल बदलने पर ग्राहकों को मोबाइल नंबर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ट्राई ने फुल एमएनपी लागू करने के तरीके को लेकर इसी साल विभिन्न संबंधित पक्षों से राय मांगी थी. साथ ही इसके लिए मौजूदा नियमों में बदलाव की जरूरतों पर भी राय मांगी गई थी. नियामक ने एक बयान में कहा कि विभिन्न मसलों पर विचार–विमर्श के बाद फुल एमएनपी के लिए सिफारिशें दूरसंचार विभाग (डॉट) को सौंपी गई है. इन सिफारिशों को लागू करने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों को छह माह का समय दिया जाएगा. ट्राई ने कहा कि फुल एमएनपी लागू होने पर ऑपरेटर को किसी भी लाइसेंस सर्विस एरिया (एलएसए) के ग्राहक की एमएनपी रिक्वेस्ट स्वीकार करनी होगी. फुल एमएनपी लागू करने के लिए डॉट एमएनपी सर्विस लाइसेंस के मौजूदा नियमों में जरूरी बदलाव कर सकता है. नियामक ने कहा कि डॉट ऑपरेटरों की मांगों पर विचार करके स्वीकार्यता परीक्षण शुल्क में 25 फीसद की कमी कर सकता है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

धोनी के धुर प्रशंसक एवं दिग्गज टेनिस खिलाड़ी विजय अमृत राज ने धोनी के नए हेयर स्टाइल की प्रशंसा करते हुए कहा कि धोनी की कोई मिसाल नहीं वह हर हेयर स्टाइल में अच्छे लगते हैं. धोनी के लंबे बालों के प्रशंसक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी थे.

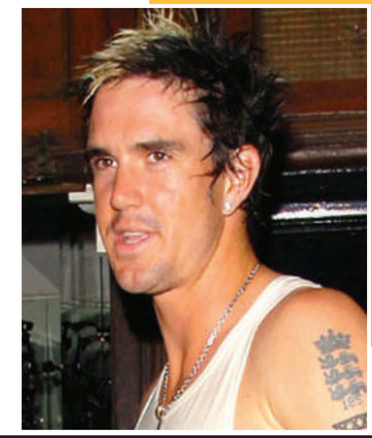

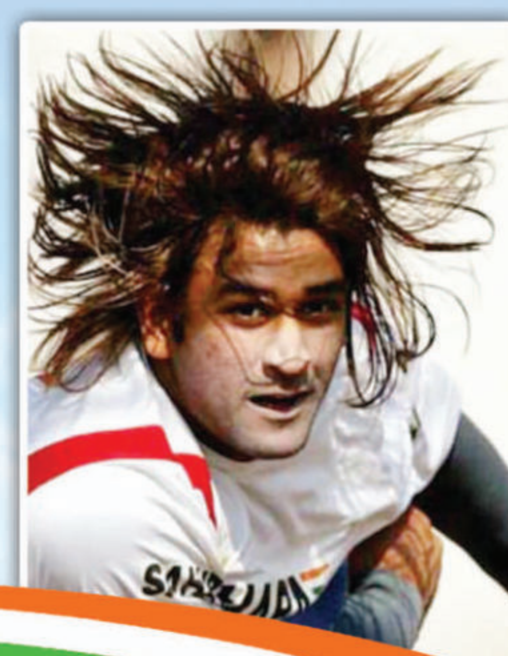

खेल के मैदान में फैशन परेड

खेल, खिलाड़ी और फैशन का बहुत गहरा और पुराना रिश्ता है. अकसर खिलाड़ी फिल्मों और रैंप में नज़र आते हैं. कई खिलाड़ियों तो अपने धमाकेदार खेल के साथ-साथ स्टाइलिश लुक के लिए जाने जाते हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इसी श्रेणी में आते हैं. वह आज देश के खेल आइकन के साथ साथ फैशन आइकन भी हैं.

नवीन चौहान

कुछ लोग हमेशा सुर्खियों में बने रहने की कला जानते हैं. इस विधा में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी माहिर हैं. उनकी बल्लेबाजी के साथ साथ उनका लुक सुर्खियों में रहता है. लंबे बालों के साथ अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरूआत करने वाले धोनी ने जितनी बार भी अपने हेयर स्टाइल में बदलाव किए, हर बार उनका प्रयोग सफल साबित हुआ और एक नया स्टाइल बन गया. इस बार चैंपियंस लीग में माही एक नए अंदाज में दिखाई दिये. धोनी प्रशंसकों के सामने पहले लंबे, छोटे और बिना बालों के नज़र आ चुके हैं, लेकिन इस बार माही ने अपने बालों के साथ एक नया प्रयोग किया है. वह इस बार फुटबॉलरों के बीच लोकप्रिय रहे बाल्ड बज कट स्टाइल में दिखे. इस स्टाइल में दोनों कानों की तरफ बिल्कुल भी बाल नहीं होते हैं और बीच में एक चोटी सी या कहें मुर्गे की कलगी जैसी दिखाई पड़ती है. फुटबॉल की दुनिया में इस हेयर स्टाइल को इटली के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी मारियो बालोटेली ने सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाया. धोनी की निजी हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवानी ने बताया कि चूंकि धोनी टेरीटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं इसलिए उनका हेयर स्टाइल द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाकों के हेयर स्टाइल से प्रेरित है. धोनी के धुर प्रशंसक एवं दिग्गज टेनिस खिलाड़ी विजय अमृत राज ने धोनी के नए हेयर स्टाइल की प्रशंसा करते हुए कहा कि धोनी की कोई मिसाल नहीं वह हर हेयरस्टाइल में अच्छे लगते हैं. धोनी के लंबे बालों के प्रशंसक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी थे. उन्होंने धोनी को भारत के पाकिस्तान दौरे के दौरान अपने लंबे बाल न कटाने का मशवरा दिया था.

खेलों की दुनिया में ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्हें उनके हेयर स्टाइल या दूसरे फैशनेबल एकस्पेरीमेंट करने वाले खिलाड़ियों के रूप में जाना जाता है, आइए ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों पर नज़र डालते हैं, जिन्हें उनके हेयर स्टाइल या फैशनेबल अंदाज ने खेल के मैदान से इतर एक अलग पहचान दिलाई. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

आंद्रे अगासी

आठ ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले मशहूर अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की एक ट्रेंड सेटर टेनिस खिलाड़ी के रूप में पहचान है. उनके लंबे बाल उनका ट्रेड मार्क हुआ करते थे. लंबी चोटी और कान में बाली पहनकर आगासी ने कोर्ट पर ऐसा जलवा बिखेरा कि उन्हें आज भी एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी के रुप में जाना जाता है. आगासी अपने करियर के शुरूआती दौर में लंबे बाल रखा करते थे लेकिन अचानक 1999 में उन्होंने अपने बाल कटवा दिए. 2009 में आगासी ने अपनी आत्मकथा ओपेन में स्वीकार किया कि उनके बाल कभी भी लंबे नहीं रहे. उनका शेर की लॉयन मेन लुक एक छलावा था. हकीॉकत में वह लंबे बालों वाले विग का इस्तेमाल किया करते थे. 1990 में उन्होंने पहली बार विग पहना था और 1999 तक वह ऐसा करते रहे. ■

लसिथ मलिंगा

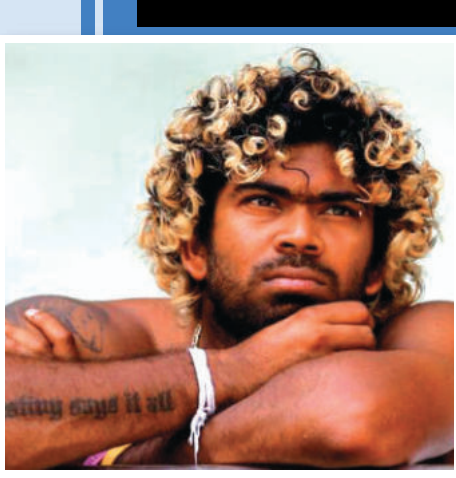

मलिंगा अपने गोल्डन कर्ली बालों की वजह से पिछले कुछ सालों से चर्चा में हैं. वह इस तरह के लुक में पहली बार 2007 में वेस्टइंडीज में हुए विश्वकप में नज़र आए थे. 2007 के विश्वकप के दौरान मलिंगा को आकर्षक कर्ली हेयर स्टाइल, आई-ब्रो में रिंग पहनने और शरीर में आकर्षक टैटू बनवाने के कारण दि बारबाडोस नाम की मैगजीन ने विश्व का सबसे सेक्सी क्रिकेटर चुना था. उनके फंकी हेयर स्टाइल की वजह से मैच के दौरान रंग बिरंगे विग पहनने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, अब यही लुक उनकी पहचान है, अपने इस हेयर स्टाइल की वजह से वह मैदान में बब्बर शेर की तरह नज़र आते हैं. ■

केविन पीटरसन

पीटरसन मैदान और मैदान के बाहर की गतिविधियों की वजह से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले इंग्लिश क्रिकेट खिलाड़ी हैं. वह अक्सर अपने नए और अनोखे हेयर स्टाइल की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. अगस्त 2005 में ऐशेज सीरीज के दौरान वह नीले रंग के बालों में मैदान में नज़र आए थे. उनके इस लुकको डेड स्कंक नाम दिया गया था. इसके बाद भी वह कई बार अपना हेयरस्टाइल बदल चुके हैं. पीटरसन को टैटू बनवाले का भी शौक है. उनके बारे में कहा जाता है कि वह आत्मविश्वास से भरे खिलाड़ी हैं. वह अपने हेयर स्टाइल और दूसरे प्रयोगों के जरिए हमेशा सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं. इन्हीं हथकंडों के जरिए वह विपक्षी टीमों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं. ■

मारियो बालोटेली

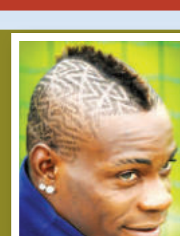

इटली का यह मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी अपने खेल के साथ साथ अपने अनोखे हेयर स्टाइल के लिए जाना जाता है. धोनी का हेयरस्टाइल इनके हेयर स्टाइल से मिलता जुलता है. ये हमेशा रंग बिरंगे और डिजाइन वाले बाल्ड बज कट में नज़र आते हैं. बेकहम से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमियार तक सभी खिलाड़ी खेल के मैदान के बाहर के लाइफस्टाइल से सुर्खियां बटोरते हैं. इसमें बालोटेली ने अपने बदलते हेयर स्टाइल की वजह से अपनी एक अलग जगह बनाई है और इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता है. ■

डेविड बेकहम

इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम दुनिया भर में एक फैशन ऑइकन के रुप में जाने जाते हैं. अपने फुटबॉल करियर में उन्होंने कई बार अपना हेयर स्टाइल बदला और हर बार उसके लिए सुर्खियां बटोरी. कई बार वह खिलाड़ी से ज्यादा एक बिजनेस मेन और मॉडल की तरह नजर आए. 2002 में जापान और कोरिया में हुए विश्वकप के दौरान उनका हेयर स्टाइल पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ था . उन्हें इस हेयर स्टाइल ने एक स्टाइल ऑइकन के रूप में वैश्विक पहचान दिलाई थी. ■

रोनाल्डो

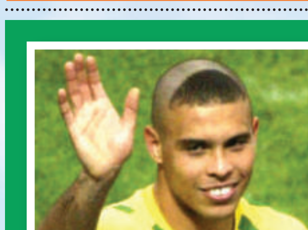

ब्राजील के पूर्व स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का भी अपना एक अनोखा हेयर स्टाइल था, वह अपने माथे के सामने की ओर एक त्रिकोण जैसा बनाते थे. इसके अलावा उनके सिर पर एक भी बाल नहीं होता था. 1998 और 2002 के फुटबॉल विश्वकप के दौरान उनका यह स्टाइल बहुत चर्चित हुआ था. ■

सेरेना और वीनस विलियम्स

विलियम्स बहने टेनिस कोर्ट पर अपने दमदार खेल के साथ अपने फैशनेबल ऑउटफिट और हेयरस्टाइल के लिए जानी जाती हैं. दोनों बहनों ने टेनिस की तस्वीर ही बदल दी है. हर टूर्नामेंट में दोनों ही नए हेयर स्टाइल में नजर आती हैं, खासकर छोटी बहन सेरेना को लोग फैशन वर्ल्ड में ट्रेंड सेटर के रूप में जानते हैं. 2012 में ओलंपिक के दौरान भी दोनों बहनें बेहतरीन हेयर स्टाइल में दिखाई दीं थीं. ■

क्रिस गेल

कैरेबियाई खिलाड़ियों को हमेशा से ही खुशमिजाज और रंगबिरंगे कपड़े पहनने वाले लोगों के रुप में जाना जाता है. कैरेबियाई पुरुष अपने बालों के साथ बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन फैशनेबल गेल अपने लंबे गुथे बालों के साथ क्रिकेट के मैदान में अपने बल्ले से प्रहार करते नज़र आते हैं. मैदान के बाहर उन्हें लंबे घुंघराले बालों में भी देखा गया है. वह अपने बालों के साथ हमेशा नए प्रयोग करते हैं. आईपीएल और टी-20 विश्वकप के दौरान उनके बालों के ड्रेडलॉक्स ने बहुत सुर्खियां बटोरी थीं. ■

द गुड रोड पहली गुजराती फिल्म है, जिसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए चुना गया है. इसकी अधिकांश शूटिंग गुजरात के कच्छ ज़िले में हुई है. द गुड रोड साल की शुरुआत में ही सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है. इसमें सोनाली कुलकर्णी और अजय गेही सरीखे कलाकार हैं.

ऑस्कर की रेस में गुजराती फिल्म

द गुड रोड

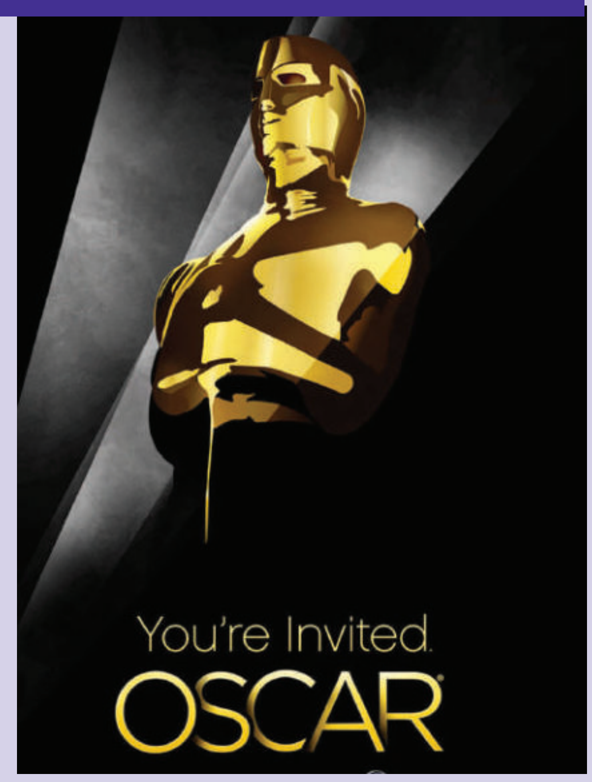

प्रियंका तिवारी

मार्च, 2014 में आयोजित होने वाले ऑस्कर में भारत की तरफ से इस बार एक गुजराती फिल्म द गुड रोड को चुना गया है. इस फिल्म के निर्देशक ज्ञान कोरिया हैं. द गुड रोड पहली गुजराती फिल्म है, जिसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए चुना गया है. इसकी अधिकांश शूटिंग गुजरात के कच्छ ज़िले में हुई है. द गुड रोड साल की शुरुआत में ही सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है. इसमें सोनाली कुलकर्णी और अजय गेही सरीखे कलाकार हैं. हालांकि इस फिल्म को लेकर विवाद भी चल रहा है. माना जा रहा है कि इस फिल्म में गुजरात की जो तस्वीर पेश की गई है, असल में वह वैसा है नहीं. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (एफएफआई) द्वारा गठित चयन समिति के अध्यक्ष, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता गौतम घोष के मुताबिक, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएफडीसी) द्वारा प्रस्तुत द गुड रोड का चयन, सर्वसम्मति से लिया गया एक निर्णय था. 19 सदस्यीय ज्यूरी ने सर्वसम्मति से इसे चुना. ज्यूरी के सदस्यों के बीच फिल्म का चयन करने के लिए पांच घंटे तक विचार-विमर्श चला.

इस साल ऑस्कर के चुनाव के लिए पूरे देश के विभिन्न हिस्सों से कुल 22 फिल्मों ने आवेदन किया था, लेकिन इसमें द गुड रोड ने बाज़ी मार ली. द गुड रोड में तीन अलग-अलग लोगों की कहानियां हैं. द गुड रोड की ख़ास विशेषता इसके किरदार ही हैं. पूरी फिल्म की कहानी दो ऐसे बच्चों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कच्छ में खो गए हैं. इसमें अहम भूमिका है ट्रक डाइवर पप्पू की, जो उन्हें उनके घरवालों से मिलाता है. यानी ट्रक ड्राइवर ही फिल्म का हीरो है. हालांकि ऑस्कर के लिए इस फिल्म के चुनाव को लेकर आम सहमति नहीं है. कुछ लोग इस निर्णय से भड़के भी हुए हैं. खासतौर पर ऐसे लोग जो भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए कुछ अन्य फिल्मों के चुने जाने की उम्मीद कर रहे थे. फिल्म लंच बॉक्स के को-प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप भी इस फ़ैसले से काफ़ी नाराज़ दिखे. उन्होंने ट्विटर पर एक के बाद एक कई ट्वीट कर अपनी नाराज़गी का इज़हार किया. उन्होंने ट्वीट किया कि ऑस्कर के लिए किसी मूवी को भेजने के लिए हमें स्पष्ट नीति बनानी चाहिए. अगर आप बेस्ट फिल्म भेजना चाहते हैं तो नेशनल अवॉर्ड विनर मूवी को भेजिए. नहीं तो उसे भेजिए, जिसके जीतने की संभावना ज़्यादा है. कश्यप ने लिखा कि वह पहली बार उत्साहित थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास चांस है. उन्होंने कहा कि अब वह निराशा में डूबा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनका फूट-फूट कर रोने का मन हो रहा है. वहीं फिल्म के डायरेक्टर रितेश बत्रा के साथ-साथ प्रेजेंटर करण जौहर ने भी नाराज़गी का इज़हार किया. बत्रा ने फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से नियुक्त समिति पर आरोप लगाया है कि उसमें समझ की कमी है. समिति के अध्यक्ष बंगाली फिल्म निर्माता गौतम घोष हैं.

रेस में पीछे छूटीं ये फिल्में

द गुड रोड के साथ भाग मिल्खा भाग, इंग्लिश विंग्लिश, विश्वरूपम, मलयालम फिल्म सेल्युलाइड और बांग्ला फिल्म शब्दो भी ऑस्कर के दौड़ में शामिल थीं. हालांकि चयनकर्ताओं को द लंच बॉक्स भी काफ़ी पसंद आई, लेकिन इनमें चुना गया द गुड रोड को.

ऑस्कर में अब तक बॉलीवुड की तीन फिल्में

100 साल के सिनेमा के इतिहास में अब तक बॉलीवुड की मात्र तीन फिल्में ही चुनी गईं. इनमें से एक है महबूब ख़ान के निर्देशन में बनी फिल्म मदर इंडिया (1957), मीरा नायर की सलाम बांबे (1988) और आशुतोष गोवारिकर की लगान (2001). ■

feedback@chauthiduniya.com

पाकिस्तानी फिल्म ज़िंदा भाग का भारत कनेक्शन

पाकिस्तान की ओर से ऑस्कर के लिए फिल्म ज़िंदा भाग भेजी गई है. इस फिल्म का गहरा कनेक्शन भारत से है. पाकिस्तान की तरफ़ से 50 साल से भी ज़्यादा समय के बाद ऑस्कर में भेजी जाने वाली यह पहली फिल्म है. फिल्म में न सिर्फ़ नसीरुद्दीन शाह प्रमुख भूमिका में हैं, बल्कि इसके तकनीकी दल के ज़्यादातर सदस्य भी भारतीय हैं. फिल्म की अधिकतर एडिटिंग मुंबई के प्रसाद फिल्म लैब में की गई. फिल्म के संपादक शाह मुहम्मद हैं, जो निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह ख़ान की आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की भी एडिटिंग कर रहे हैं. इसके सिनेमेटोग्राफर सत्यराय नागपाल हैं, जिन्हें पिछले साल पंजाबी फिल्म अन्हे घोड़े द दान के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था. फिल्म के साउंड डिजाइनर विपिन भट्ट हैं, जिन्होंने नागेश कुकुनूर की कई फिल्मों में काम किया है. ख़ास बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग नसीर ने लाहौर में गुपचुप तरीक़े से की थी. यही नहीं उन्होंने नये कलाकारों के लिए एक हफ्ते की वर्कशॉप भी आयोजित की थी. पंजाबी-उर्दू में बनी इस फिल्म की निर्देशक फरजाद नबी और मीनू गौड़ हैं. फिल्म की कहानी तीन ऐसे युवकों के ईद-गिर्द घूमती है, जो विदेश जाना चाहते हैं. ■

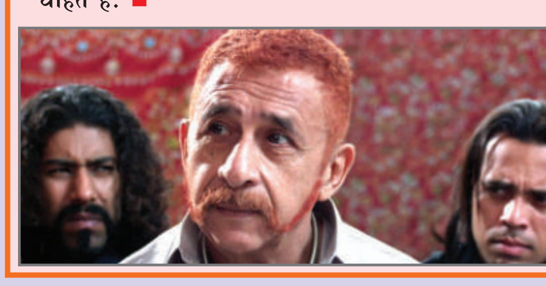

कामयाबी एक ख़ूबसूरत हसीना की तरह है: शाहिद कपूर

वैसे तो अभिनेता शाहिद कपूर ने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें विवाह और जब वी मेट जैसी फिल्मों से सफलता मिली. पर बाद में धीरे-धीरे उनके करियर का ग्राफ गिरता ही गया, लेकिन हाल ही आई उनकी फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो, ने उन्हें एक बार फिर हीरो बना दिया है. जी हां, यह एक शुद्ध मनोरंजक फिल्म है. इस फिल्म में शाहिद ने अपना लुक चेंज किया है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है. अपनी असफल फिल्मों के बार में वह कहते हैं कि मैंने हर फिल्म में अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया. बॉक्स-ऑफिस पर अगर फिल्म हिट कराने का कोई पैरामीटर होता, तो हर फिल्म मेकर फिल्म बनाने से पहले इसी पैरामीटर पर अपनी फिल्म बनाता. शाहिद कहते हैं कि मौसम और तेरी मेरी कहानी के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी. इन फिल्मों का सब्जेक्ट आम फिल्मों से कुछ अलग और नया था. इसके बावजूद इन फिल्मों को दर्शकों ने रिजेक्ट कर दिया, तो जरूर कुछ खामियां रही होंगी. पिता पंकज कपूर ने बेटे के करियर को संवारने की ख़ातिर बड़ी अरमानों से फिल्म मौसम बनाया था, लेकिन यह फिल्म सुपर फ्लॉप रही. इस बारे में शाहिद कहते हैं कि फिल्म की ज्यादा लंबाई और इंटरवल के बाद कहानी का ट्विस्ट दर्शकों की बड़ी क्लास को पसंद नहीं आया, जबकि आज कल लोग तीन-चार महीनों में फिल्में बना लेते हैं, वहीं डैड को मौसम बनाने में क़रीब दो साल लगे. यह फिल्म क़रीब साढ़े तीन घंटे से ज़्यादा की है. डैड फाइनल एडिटिंग में कोई सीन कटवाना नहीं चाहते थे, दूसरी ओर डिस्ट्रिब्यूटर्स ढाई घंटे की फिल्म चाहते थे. फिर भी तीन घंटे से कुछ ज़्यादा अवधि की फिल्म फाइनल की गई. शाहिद कहते हैं कि मौसम जब तक पूरी नहीं हुई, तब तक उन्होंने कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं की. वह कहते हैं कि हालांकि इस फिल्म की नाकामयाबी का उनसे ज़्यादा शॉक उनके डैड को लगा. शाहिद अपनी नाक़ामयाब फिल्मों के बारे में कहते हैं कि वह कामयाबी को एक ख़ूबसूरत हसीना समझते हैं. इस हसीना का मिजाज किसी के साथ कभी भी एक जैसा नहीं रहता. हालांकि वह यह भी मानते हैं कि करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत गलतियां कीं. पहली ही फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया. उन्हें खुद पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि करियर के शुरुआती दौर में जब मुझे उन्हें खूब काम करना चाहिए था, तब वह फिल्मों को लेकर काफी चूजी हो गए. हर महीने तीन-चार फिल्मों की स्क्रिप्ट रिजेक्ट करते. वह कहते हैं कि अब उन्होंने अपनी ग़लतियों से सिख लिया है. फटा पोस्टर के बाद वह जल्द ही प्रभु देवा की रैंबो राजकुमार में नजर आएंगे. ■

कंगना ने वेबसाइट लॉन्च की

कंट्रोवर्सी ऐंड ट्रैंट्रम क्वीन कंगना रनावत इन दिनों सेल्फ प्रमोशन में जुट गई हैं. ट्वीटर या फेसबुक पर समय देने की बजाय उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर लिया है. इस बारे में वह कहती हैं कि वह अब पहले से ज़्यादा करियर को लेकर सजग हो गई हैं. दरअसल ट्विटर और फेसबुक ज़्यादा टाइम टेकिंग हैं, ऐसे में उन्हें वेबसाइट लॉन्च करना ज़्यादा बेहतर लगा. वह मानती हैं कि आज तक उनके और उनके फैंस के बीच कम्युनिकेशन का कोई सही ज़रिया नहीं था. उनके नाम पर इतने सारे अकाउंट्स हैं और उससे उनके प्रशंसक मिसलीड होते रहते हैं. ऐसे में उन्हें लगा कि उनसे जुड़ी जानकारी सही माध्यम से बाहर नहीं जा पा रही हैं, इसलिए उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करने की योजना बनाई. साथ ही वह यह भी कहती हैं कि उनकी इमेज चाहे जैसी भी बन गई हो, लेकिन उनमें काफ़ी पैशन है अपने काम को लेकर, तभी वह यहां तक पहुंची हैं. चाहे लोग जो भी सोचें, पर सच तो यह हैं कि असल जीवन में भी वह फैमिली वैल्यूज में यकीन करने वाली लड़की हैं. उन्हें अपने भाई-बहन का साथ बहुत पसंद है. उनके साथ वह ख़ुद को ज़्यादा सिक्योर फील करती हैं. हालांकि वह खुद को एक करियर ओरिएंटेड औरत मानती हैं. वह यह भी स्वीकार करती हैं कि उनका स्वभाव थोड़ा जिद्दी और अड़ियल है. उन्हें कई बार बहुत ग़ुस्सा आ जाता है. पर वह हमेशा अपने दिल की सुनती हैं, वह बचपन से ही ऐसी हैं. कंगना कहती हैं कि लोग इसे बुरा मानते हैं, लेकिन उनका जिद्दी मिजाज ही उन्हें इस मुक़ाम तक लाया है. यही बदतमीजियां और जिद उन्होंने अपने पिता के घर में की, जिससे आज वह यहां हैं. फैशन, तनु वेड्स मनु जैसी परफॉर्मेंस प्रधान रोल्स करने के बाद रास्कल्स और डबल धमाल जैसी शो पीस वाली फिल्म करने की वजह कंगना बताती हैं कि दरअसल यह इंडस्ट्री काफ़ी असुरक्षित जगह है. कई बार आप इनसिक्योर होकर, तो कई दफा पैसों के लिए ऐसे रोल कर जाते हैं, जिन्हें लेकर आप खुद भी खुश नहीं होते. पर एक बार करके उन्होंने जान लिया है कि उन पर ऐसे रोल नहीं जमते. उन्हें ख़ास तरह के रोल ही करने होंगे. ■

प्रीव्यू

अग्ली

डायरेक्टर	:	अनुराग कश्यप
प्रोड्यूसर	:	फैंटम फिल्म्स ऐंड डीएआर मोशन पिक्चर्स
स्टार कास्ट	:	राहुल भट्ट, रॉनित रॉय, गिरीश कुलकुर्णी, तेजस्विनी कोल्हापुरी, विनीत कुमार सिंह विपिन शर्मा एवं सुरवीन चावला
संगीत	:	जीवी प्रकाश कुमार
रिलीज डेट	:	11 अक्टूबर, 2013

फ्रायडे, देव डी और गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसी सफल फिल्में बना चुके अनुराग कश्यप की अगली फिल्म है अग्ली. फैंटम और डीएआर मोशन पिक्चर्स के संयुक्त बैनर तले बनी यह फिल्म मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और भावनात्मक है. यह फिल्म एक ऐसी बच्ची पर आधारित है, जिसे पैसों के लिए अगवा कर लिया जाता है और उसका पिता पुलिस की मदद से उसे हासिल करने की कोशिश करता है. एक के बाद एक घटती घटनाओं के बाद शक़ की सूई बच्ची के पिता की तरफ ही घूमती है. अनुराग कश्यप द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म अगली का ट्रेलर बेहद रोमांच और सस्पेंस से भरपूर है. इस फिल्म में रोनित रॉय एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नज़र आ रहे हैं. ठीक इसी तरह का किरदार अक्षय कुमार की फिल्म बॉस में भी उन्होंने अदा किया है. इस फिल्म के ज़रिये मराठी अभिनेता गिरीश कुलकुर्णी भी बॉलीवुड में क़दम रखने जा रहे हैं. उम्मीद है अनुराग की अन्य फिल्मों की तरह यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करेगी. ■

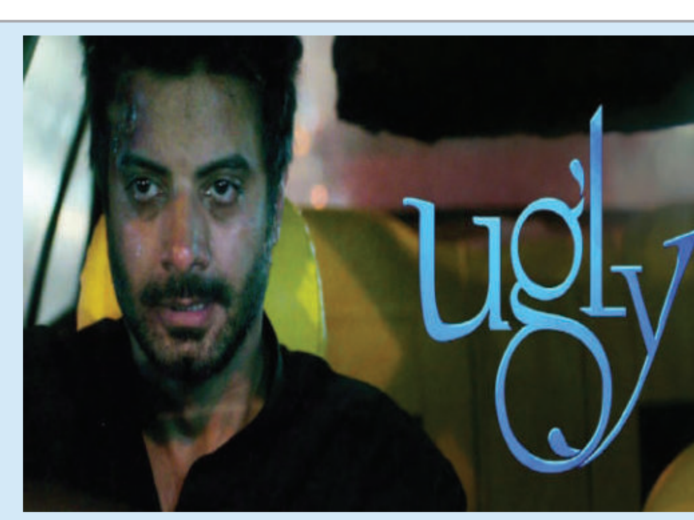

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

07 अक्टूबर-14 अक्टूबर 2013

बिहार – झारखंड

फोटो-प्रभात पाण्डेय

मोदी की हुंकार से गूंजेगा बिहार

पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान 27 अक्टूबर को एक बार फिर एक ऐसी रैली का गवाह बनने जा रहा है, जिसके बारे में भाजपाइयों का दावा है कि प्रदेश के इतिहास में न कभी ऐसी रैली हुई है और न आगे कभी होगी. यहां न केवल गांधी मैदान, बल्कि पूरे पटना शहर को पाटने के संकल्प के साथ भाजपाई इन दिनों नमो-नमो का जाप कर रहे हैं...

सरोज सिंह

गांधी मैदान में होने जा रहे इस रैली को लेकर विपक्षी पार्टियां इसे भाजपा का हसीन ख्वाब बता रही हैं, तो वहीं भाजपा इसे अपना अटल संकल्प. दोनों में से क्या निकलकर आएगा यह तो 27 अक्टूबर को ही साफ़ हो पाएगा, लेकिन इस रैली को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं, इसे देख कर तो यही लगता है कि बिहार भाजपा नरेंद्र मोदी को पटना की ज़मीन पर एक महानायक के तौर पर उतारना चाहती है. तैयारियों में जाने से पहले इस रैली की भाजपा के लिए ज़रूरत और महत्व को समझना बेहद ज़रूरी है. यह सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्लान 272 में बिहार का अहम रोल है. यहां से ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतना पार्टी के लिए जीवन मरण का सवाल है. ऐसा करके नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को अपनी आलोचनाओं का क़रारा जवाब देना चाहते हैं. जदयू-भाजपा गठबंधन टूटने में नरेंद्र मोदी को खलनायक के तौर पर पेश किया गया. इसलिए नरेंद्र मोदी की टीम चाहती है कि बिहार की चालीस में कम से कम 25 सीट जीतकर सारी आलोचनाओं का जवाब दे दिया जाए. इसके लिए ज़रूरी है कि 27 अक्टूबर की हुंकार रैली को ऐतिहासिक बनाया जाए, भारी भीड़ हो. टीम नरेंद्र मोदी का आकलन है कि अगर वह ऐसा करने में सफल रहे तो पूरे सूबे और देश में यह संदेश जाएगा कि अब नरेंद्र मोदी को रोकना नामुमकिन है. सफ़ल रैली के बाद उहापोह में फंसे नेता भी मोदी के गुणगान में सामने आ जाएंगे. भाजपा के कार्यकर्ताओं के उत्साह का आकलन करना मुश्किल हो जाएगा. इसके अलावा, प्रदेश की दूसरी पार्टियां जैसे राजद व जदयू के सामने तब अपने गढ़ को बचाना एक मुश्किल चुनौती हो जाएगी. ऐतिहासिक रैली कर भाजपा अपने केंद्रीय नेताओं के इस अपमान का भी बदला लेना चाहती है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान नीतीश कुमार ने उनका किया था. न्योता देकर डिनर को कैंसेल करने वाली घटना से उपजे घाव को भाजपाई भूल नहीं पा रहे हैं. पटना में 27 अक्टूबर को उमड़े जनसैलाब से ही यह घाव भर सकता है, ऐसा भाजपा के कार्यकर्ता मानते हैं. भाजपा ने हुंकार रैली को ऐतिहासिक बनाने का जो संकल्प लिया है, उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए. रैली को लेकर बिहार भाजपा की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे बिहार में कोई ज़िला ऐसा नहीं है, जहां पार्टी का बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो. हौसला बढ़ाने वाली बात यह है कि ज़िलास्तर पर भी भाजपा ने जो रैलियां कीं, उसमें भी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही. इससे उत्साहित भाजपा ने यह तय किया कि बिहार के हर गांव से हुंकार रैली में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए. गांव-गांव में नुक्कड़ सभाओं के मार्फत लोगों को पटना आने का न्योता दिया जा रहा है. संघ के लोग भी इस काम में अपना पूरा वक्त दे रहे हैं. पार्टी ने पंचायत स्तर पर भी अपने कार्यकर्ताओं को रैली को सफल बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी है.

......................शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

नरेंद्र मोदी गिरफ्तार हो सकते हैं

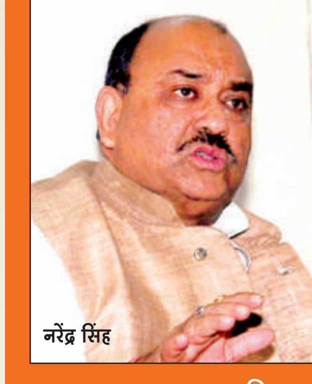

नरेंद्र सिंह

अयोध्या में राममंदिर निर्माण को लेकर लालकृष्ण आडवाणी की निकली रथ यात्रा को लालू प्रसाद ने समस्तीपुर में रोक कर और आडवाणी को गिरफ्तार कर देश की राजनीति की दिशा व दशा को बदल दिया था. लगता है कि एक बार फिर बिहार की ज़मीन पर यह इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन इस बार फ़ैसला लेने का काम करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशाने पर होंगे भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी. 27 अक्टूबर को हुंकार रैली में शिरकत करने के लिए नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं. रैली की भव्य तैयारियों से विपक्षी दलों की नींद उड़ी हुई है. अगर भाजपा की यह रैली सफ़ल हो गई तो आगामी चुनावों में इसका व्यापक असर पड़ सकता है. चर्चा है कि प्रशासन विधि व्यवस्था बनाए रखने और सांप्रदायिक माहौल के नाम पर नरेंद्र मोदी को पटना में रैली से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की टीम यह सोच रही है कि आडवाणी को गिरफ्तार कर जिस तरह लालू प्रसाद मुसलमानों के हीरो बन गए और राष्ट्रीय राजनीति में उनका क़द अचानक काफी बढ़ गया, ठीक यही नरेंद्र मोदी के मामले में भी होगा. अगर नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करने का फ़ैसला होता है तो नीतीश रातों रात मुसलमानों के हीरो बन जाएंगे और देश की राजनीति के केंद्र में होंगे. जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रवक्ता रामकिशोर सिंह कहते हैं कि किसी रैली को रोकने या किसी नेता को गिरफ्तार करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो क़ानून अपना काम करेगा. उस समय के हालात का आकलन कर फ़ैसला लिया जाएगा, लेकिन जदयू का स्पष्ट मानना है कि किसी भी दल या नेता को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं देनी चाहिए. रैली और धरना के नाम पर सिर्फ़ तनाव पैदा किया जा रहा है. वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि अब दुनिया की कोई ताक़त नरेंद्र मोदी को बिहार आने और प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती है. सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का बहाना अब चलने वाला नहीं है. जनता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की सच्चाई जान चुकी है. अगर नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करने या रैली पर रोक जैसे आत्मघाती क़दम सरकार उठाती है तो इसका परिणाम जदयू सरकार को भुगतना पड़ेगा. सिंह ने कहा कि तुष्टिकरण की नीति से किसी का भला नहीं होगा. इसलिए भगवान ऐसा सोचने वालों को सद्बुद्धि दें. ■

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

» एक नज़र «

मंडल कारा में स्वास्थ्य परीक्षण

सीतामढ़ी ज़िला मुख्यालय डुमरा स्थित मंडल कारा में लायंस क्लब सीतामढ़ी ने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया. शिविर में क़ैदी महिलाओं एवं बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. साथ ही नि:शुल्क दवा का भी वितरण किया गया. अध्यक्ष सरिता सर्राफ व पुष्पा लोहिया के नेतृत्व में आयोजित शिविर में डॉ. सुषमा सिंह, डॉ. वीणा गुप्ता, डॉ. केएन गुप्ता व डॉ. बीएन बाजोरिया ने जांच किया. कार्यक्रम में दीप्ती सरकार, निर्मला मिश्रा, रितु सर्राफ, इशा भवसिंका, किरण रानी, सविता अग्रवाल, सुनिता सिकारिया, सविता हिसारिया, गायत्री अग्रवाल, सुधा सिंह, रमावती गुप्ता, इंद्रा गुप्ता, विजय सर्राफ व मदन प्रसाद समेत अन्य थे.

– अभिलाषा द्विवेदी

पूर्व विधायक के निधन पर शोक जताया

सीतामढ़ी ज़िले के पुपरी विधान सभा क्षेत्र से चार बार विधायक रह चुके रामवृक्ष चौधरी के निधन से ज़िला कांग्रेस कमेटी में शोक व्याप्त है. ज़िला कांग्रेस कार्यालय ललित आश्रम में जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला के नेतृत्व में आयोजित शोक सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की. जिलाध्यक्ष शुक्ला ने कहा कि पूर्व विधायक ने पार्टी संगठन की मजबूती में अहम योगदान दिया है. उनके असामयिक निधन से ज़िला संगठन मर्माहत है. मौक़े पर राजद प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र पूर्वे, पूर्व सांसद रामश्रेष्ठ खिरहर, कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राम कृपाल शर्मा, उपाध्यक्ष सीताराम झा, डॉ. भुवनेश्वरी मिश्रा, मो. असद, ताराकांत झा, रामबली महतो, रंधीर प्रसाद सिंह, मोहन गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, शिव शंकर शर्मा, पप्पू प्रवीण, मो. परवेज आलम अंसारी, विजेंद्र कुमार यादव, ज़िला राजद अध्यक्ष मो. शफ़ीक खां, पूर्व अध्यक्ष शिव शंकर प्रसाद यादव, गणेश गुप्ता समेत दर्जनों थे.

भाजपा-आरएसएस सामाजिक सद्भाव ख़त्म कर रहे हैं : डॉ. पूर्वे

सीतामढ़ी में बिहार प्रदेश राजद अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि किसी भी सूरत में देश की एकता व अखंडता को बचाना है. भाजपा व आरएसएस बिहार में सामाजिक व धार्मिक सद्भाव ख़त्म करने पर तुली है. कर्पूरी दर्शन केंद्र में डॉ. पूर्वे ने कहा कि नमो मार्का सुमो के नेतृत्व का भाजपा व जदयू दोनों ही बिहार में सामाजिक सद्भाव का दुश्मन है. गोधरा कांड को लेकर नमो नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. आगामी चुनाव पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी दल को लालू जी से ही मिलना होगा. गठबंधन की संभावित चर्चा पर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि संभव है कि राजद-कांग्रेस व वामदल सांप्रदायिक शक्तियों को किनारा करने के लिए एक होंगे. बिहार में राजद का जनाधार बढ़ा है. उन्होंने यह भी कहा कि इस बार संभव है कि युवाओं को चुनाव में विशेष तरजीह दी जाए. मौक़े पर पूर्व सांसद राम श्रेष्ठ खिरहर, जिलाध्यक्ष मो. शफ़ीक खां, पूर्व अध्यक्ष शिव शंकर प्रसाद यादव व गणेश गुप्ता समेत अन्य थे. ■

– ब्रजेश

शेखपुरा ज़िला परिषद
आमने-सामने जदयू विधायक

ज़िला परिषद की राजनीति को शेखपुरा ज़िले का कलंक माना जाता है, जिस राजनीति की आग ने दस साल पहले नरसंहार की बुनियाद रखी, उसी ज़िला परिषद की राजनीति ने एक बार फिर से करवट ली है. इस बार जदयू के दोनों विधायक शेखपुरा विधायक रणधीर कुमार सोनी तथा बरबीघा विधायक गजानंद शाही उर्फ़ मुन्ना शाही आमने-सामने हैं.

अरुण कुमार

शेखपुरा की राजनीति में शह और मात का खेल तब शुरू हुआ, जब शेखपुरा विधायक ने बरबीघा विधायक से अपने पंचायत में बिना उनके पूर्व सूचना के कोई कार्यक्रम करने पर नाराज़गी जाहिर की. इसके बाद यह दूरी धीरे-धीरे आगे बढ़ती गई और अंत में ज़िला परिषद के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें शेखपुरा विधायक को मुंह की खानी पड़ी.

दरअसल, शेखपुरा ज़िले में ज़िला परिषद के कुल सात सीटें हैं, जिसमें एक को छोड़ सभी पर जदयू समर्थित सदस्य ही जीत कर आए हैं. बरबीघा से जदयू नेता और केवटी पंचायत के मुखिया डॉ. दीपक कुमार की पत्नी आशा देवी, शेखोपुरसराय से जदयू के जिलाध्यक्ष डॉ. अर्जुन प्रसाद, शेखपुरा पश्चिमी से जदयू नेता चंदन सिंह की पत्नी प्रीतम देवी, तो पुर्वी से जदयू नेता मनोज कुमार (तुफानी) की पत्नी रेशमा भारती. इसी तरह अरियरी से जदयू नेता नरेश महतो तथा चेवाड़ा से जदयू नेता दयानंद चौधरी ज़िला परिषद सदस्य हैं. एक मात्र घाटकोसुंभा सीट पर विरोधी राजद के नेता चंद्र प्रकाश उर्फ़ शिवली यादव का क़ब्ज़ा है. इसी समीकरण के तरह शेखपुरा विधायक रणधीर कुमार ने नरेश महतो को अध्यक्ष और दयानंद चौधरी को उपाध्यक्ष निर्वाचित करवाया. बाद में विधायक के मित्र रहे मनोज कुमार (तुफानी) की पत्नी रेशमा भारती के बढ़ते क़द को लेकर चिंतित विधायक ने उनका क़द छोटा करना चाहा तो अनबन शुरू हो गई. इसी वजह से जदयू सांसद आरसीपी के क़रीबी माने जाने वाले मनोज कुमार (तुफानी) और रेशमा भारती ने पहल कर अविश्वास प्रस्ताव लाया. उनके द्वारा शिवली यादव एवं चंदन सिंह तथा आशा देवी को अपने पक्ष में कर लिया गया. इस सारे खेल में शेखपुरा विधायक के क़रीबी रहे केवटी मुखिया डॉ. दीपक कुमार ने मुख्य भुमिका निभाई और दोनों की अगुआई में ज़िला परिषद पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया.

ज़िले की राजनीति में जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी को लगने वाला यह पहला झटका माना जाता है. इससे पूर्व राजनीति के मैदान में उनका एकक्षत्र राज था. अपनी सफलता पर रेशमा भारती कहती हैं कि विधायक समर्थित ज़िला परिषद अध्यक्ष द्वारा ज़िले के विकास की अनदेखी की जा रही थी और केवल अपने क्षेत्र का ही विकास किया जा रहा था, जिससे जदयू के समवेशी सरकार की छवि ख़राब हो रही थी. इसे संतुलित कर ठीक करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया. वहीं डॉ. दीपक कुमार की माने तो विधायक द्वारा उनके साथ वादाख़िलाफ़ी की गई और कई मोर्चों पर उनके क्षेत्र के विकास को दरकिनार कर दिया गया.

हांलाकि डॉ. दीपक कुमार कांग्रेसी नेता सुरेश सिंह के दमाद हैं और उनकी पत्नी आशा देवी ज़िला परिषद सदस्य. इसी वजह से जदयू जिलाध्यक्ष इसे विपक्ष की राजनीति का हिस्सा मानते हुए

कहते है कि यह जदयू को कमजोर करने के लिए विपक्ष से मिलकर किया गया काम है, लेकिन इस सब के बाद भी वे लोग हाईकोर्ट की शरण में गए हैं, जहां एक ही आवेदन पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाने को अवैध घोषित करने की मांग की गई, जिससे सारा मामला ख़त्म हो जाए. वहीं इस सारे मामले में बरबीघा विधायक मुन्ना शाही का भीतरी समर्थन प्राप्त है, लेकिन मुन्ना शाही किसी प्रकार के समर्थन से इंकार करते हुए कहते है कि ज़िला परिषद की राजनीति से उन्हें कोई लेना देना नहीं है और विकास के मुद्दे पर ज़िला परिषद सदस्यों ने ख़ुद पहल किया है. वहीं बरबीघा में आयोजित जदयू के सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में मुन्ना शाही समर्थकों ने मंच से ही ज़िलाध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव अंजनी कुमार के ख़िलाफ़ जम कर आग उगला था, जिससे दोनों विधायक खेमे की तल्ख़ी सामने आ गई थी. जिलाध्यक्ष को शेखपुरा विधायक ख़ेमे का माना जाता है. पर्दे के पीछे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी को भी माना जा रहा है. आख़िर अशोक चौधरी के ही प्रयास से पूर्व कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सुरेश सिंह जो जदयू में चले गए थे, अपने घर वापसी की है और उनकी पुत्री आशा देवी को ज़िला परिषद अध्यक्ष बनाने की चर्चा भी ज़ोरों पर है, जो भी हो पर ज़िला परिषद की राजनीति में शेखपुरा ज़िले की राजनीति के ठहरे तलाब में हलचल पैदा कर दी है और शेखपुरा विधायक के मात खाने को लेकर उनके चुप नहीं बैठने की चर्चा भी ज़ोरों पर है. अभी नए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव होना बाक़ी है और मामला पटना हाई कोर्ट में भी चला गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

शॉर्ट न्यूज

लालू अल्पसंख्यकों के रहनुमा: डॉ. उर्मिला

अल्पसंख्यक समाज आज विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है. वर्तमान राज्य सरकार अल्पसंख्यकों को सिर्फ़ ठगने का काम कर रही है. उक्त बातें माड़र दक्षिणी पंचायत के मदरसा हुसैनिया खगड़िया में अल्पसंख्यक समाज के उत्थान एवं सरकारी योजनाओं के लाभ पर चर्चा करने के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए राजद के प्रदेश महासचिव डॉ. उर्मिला ठाकुर ने कही. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को एकजुट होकर अपने हक़ एवं अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है. राजद के नेतृत्व में ही अल्पसंख्यकों का विकास संभव है, इसलिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हाथों को मजबूत करने की बात करते हुए श्रीमति ठाकुर ने कहा कि लालू प्रसाद यादव हमेशा से ही अल्पसंख्यक समाज के रहनुमा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजद की राज्य में सरकार बनेगी तो अल्पसंख्यक समाज के लिए सच्चर कमेटी एवं रंगनाथ मिश्रा आयोग की अनुशंसा को लागू की जाएगी. मौक़े पर राजद अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष मो. जुल्फीकार अली, प्रदेश सचिव अनामुल हक़, रामचरित्र सदा, संजय यादव, सुनील यादव, नंदलाल मंडल, तरवीर अहमद, मो. सलाम, रमन कुमार सहित दर्जनों राजद जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित थे.

– मनेंद्र कुमार

मेहता फाउंडेशन द्वारा वृक्षारोपण

प्रदूषित हो रहे वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने की ज़रूरत है. सदर प्रखंड के राजकीय बुनियादी मीडिल स्कूल दुर्गापुर खगड़िया में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान मेहता फाउंडेशन के सचिव योगेन्द्र कुमार मेहता ने कही. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत मेहता फाउंडेशन के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मेहता ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण मौसम की मार से हमें जुझना पड़ रहा है. इसी का परिणाम है कि हमें अनियंत्रित मौसम के कारण बाढ़ एवं सुखाड़ का सामना करना पड़ता है. मौक़े पर विद्यालय प्रधान विजय पासवान, शिक्षक महेश्वरी प्रसाद सिंह, अरविंद कुमार, ललितेश्वर प्रसाद सिंह, मुन्ना कुमार, प्रियंका कुमारी, बुलबुल कुमारी, नीलू, प्रीति, राजकुमारी सहित सैकड़ों छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थे.

रैली की सफलता को लेकर बैठक

पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाली पंचायत अधिकार रैली की सफलता के लिए बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक ग्राम पंचायत राज अमनी के मुखिया सह जिला मुखिया महासंघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में सन्हौली सामुदायिक भवन खगड़िया में आयोजित की गई. बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि आज कोई भी पंचायत प्रतिनिधि जनता से किए वायदों पर अमल नहीं कर रहीं हैं. यहां तक की पंचायत प्रतिनिधि जाति-आवासीय प्रमाण पत्र पर भी अनुशंसा करने की ज़रूरत नहीं रह गई है. सभी कार्यों के लिए ग़रीब एवं नि:सहाय जनता को बीडीओ-सीओ के ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है. इसलिए गांवों के विकास के बिना बिहार का विकास धोखा है. इस अवसर पर पवन कुमार चौधरी, जगदीश पंडित, रामबालक सिंह, रामविलास महतो, शशिकला देवी, पार्वती देवी, मनोज कुमार, दुर्गा देवी, शम्मी कपूर, राजकिशोर यादव, आशा देवी, रानी देवी, उमेश वर्मा सहित दर्जनों पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे.

बधाई का तांता लगा

रालोसपा के ज़िला कार्यालय कुमार निवास में मो. जफ़र आलम उर्फ बबन बाबू को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अल्पसंख्यक सेल का ज़िला अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी में हर्ष का माहौल है. वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा. नूरहसन आज़ाद को ज़िला कमेटी की तरफ़ से बधाई दिया गया. जिलाध्यक्ष अमित कुमार मंटू ने कहा कि बबन बाबू के जिलाध्यक्ष बनने को लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और उनके आने से पार्टी और मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि पार्टी सभी लोगों का सम्मान करती है. मो. जफ़र आलम के आने से और अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष बनने से पार्टी के विस्तार के साथ-साथ जनाधार भी बढ़ेगा. वहीं खगड़िया अध्यक्ष सकेब अहमद ने भी प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी. जिलाध्यक्ष मो. जफ़र आलम उर्फ बबन बाबू ने कहा कि हमें तन-मन के साथ-साथ एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करना होगा. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सूबे से महाजंगल राज को ख़त्म कर देंगे. इस अवसर पर मुल्क राज आनंद, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, तुरंती सिंह, प्रकाश सिंह, दिनेश सिंह, अजित सिंह, राकेश सिंह सहित दर्जनों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे.

शिलान्यास समारोह आयोजित

स्थानीय राजेन्द्र नगर मोहल्ला स्थित शंकर मिश्रा एसबी मेमोरियल स्कूल होते हुए पप्पू यादव के घर तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास विधान पार्षद रजनीश कुमार ने किया. मौक़े पर एसबी मेमोरियल विद्यालय के प्रांगण में समाजसेवी केदार प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन विधान पार्षद, मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष रामानंद चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष सुनील चौधरी, शशिभूषण प्रसाद, सुनीता देवी राय ने दीप प्रज्जवलित की, जबकि एसबी मेमोरियल स्कूल के निदेशक प्रभाकर प्रभात ने मंच संचालन करते हुए बताया कि पूर्व के कार्यक्रम में एक छोटे से बच्चे द्वारा विधान पार्षद से सड़क की मांग की गई थी, जिसे पाकर राजेन्द्र नगरवासी उनके ऋणी हुए थे. मौक़े पर दर्जनों लोगों के द्वारा विधान पार्षद रजनीश कुमार का भव्य स्वागत किया गया.

प्रखंड व अंचल कार्यालय का घेराव

ज़मीन, सड़क, बिजली सहित अन्य मांगों को लेकर बहिष्कृत हितकारी संगठन के ज़िला अध्यक्ष पप्पू डोम के नेतृत्व में दलित वर्ग के दर्जनों महिला एवं पुरुषों ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का घेराव किया. 21 दिनों के अंदर मांग पूरा होने के आश्वासन पर संगठन के लोगों का आक्रोश शांत हुआ. बहिष्कृत हितकारी संगठन के सदस्य सनोज कुमार ने बताया कि अधिकारियों के द्वारा 21 दिनों के अंदर मांगों को पूरा नहीं करने पर पुन: आंदोलन किया जाएगा. इस अवसर पर पार्वती देवी, राधा देवी, रीना देवी, सुमन कुमार गुलशन, हीरालाल दास, पंकज कुमार परवाना, विवेक कुमार, केदार दास, महेंद्र राम, विकास दास, कुलो दास आदि उपस्थित थे. *– नंदकिशोर शर्मा*

भक्तों की भीड़ उमड़ी

सहरसा ज़िले के दर्जनों शिव भक्तों ने 55 फीट के कांवर को लेकर गंगा नदी अगुवानी घाट से जल भर कर मधेपुरा ज़िले के सिंहेश्वर धाम में बाबा भोले को जल चढ़ाने के लिए जाने के क्रम में कांवर सत्कार संघ मुश्कीपुर कोठी के सदस्यों के द्वारा डॉ. अशोक कुमार के नेतृत्व में रंजीत यादव, नीरज कुमार उर्फ बबलू, सन्नी कुमार, रूपेश कुमार, उदय कुमार, मुकेश कुमार, श्याम कुमार, आवेश कुमार सहित दर्जनों सदस्यों ने शिव भक्तों का भव्य स्वागत किया. वहीं कांवर को देखने के लिए जमालपुर बाजार, रामपुर रोड, माली टोला, कुर्मी टोला सहित अन्य जगहों के श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही. इस अवसर पर राहुल राज, हिमांशु शेखर, लवली सिंह, साक्षी सिंह, वीर प्रकाश रजक सहित शिव भक्त उपस्थित थे.■

– उधव कुमार

पृष्ठ 17 का शेष

मोदी की हुंकार से गूंजेगा बिहार

हर पंचायत में रैली से संबंधित होर्डिंग लगाने की योजना को अमल में लाया जा रहा है. भाजपा अध्यक्ष मंगल पांडेय ने पूरे सूबे में फैले अपने 50 लाख सामान्य सदस्यों को रैली में आने का निमंत्रण पत्र भेजा है. इसके अलावा, 32 हज़ार सक्रिय सदस्यों को यह टास्क दिया गया है कि रैली में आने वाले हर एक सदस्य को पटना लाने के इंतजाम में सहयोग करें. दूरदराज के ज़िले से पटना आने वाले लोगों के लिए रेलगाड़ियों का इंतज़ाम भी किया गया है. ख़बर लिखे जाने तक किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बेतिया, नौगछिया, भागलपुर, मोतिहारी और समस्तीपुर से रेलगाड़ी की बुकिंग की गई है. पार्टी से जुड़े लोग बता रहे हैं कि और भी बुकिंग कराने का अनुरोध आ रहा है. इसके अलावा, भाजपा विधायकों व नेताओं को बसों के इंतज़ाम के लिए कहा गया है. हर ज़िले से बसों का लंबा काफिला 26 व 27 अक्टूबर को पटना के लिए प्रस्थान करेगा. इसके अलावा, छोटी गाड़ियों का भी इंतजाम हज़ारों की संख्या में किया जा रहा है.

इन दिनों पटना में ठहरने के सभी विकल्पों का खंगाला जा रहा है. भाजपा के 92 विधायकों के निवास तो रहेंगे ही, इसके अलावा सामुदायिक भवनों व मिलर स्कूल के मैदान को भी बुक कराया जा रहा है. पार्टी ने अपने पटना स्थित कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि बाहर से आने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए वे अपने घरों के दरवाजे खोल दें. पटना के सारे होटल बुक हो चुके हैं और 26 व 27 अक्टूबर को पटना आने के लिए विमानों में भी टिकट नहीं बचा है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय कहते हैं कि 27 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पूरा बिहार उमड़ पड़ेगा. नरेंद्र मोदी के लिए इस दिन गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा. पांडेय का दावा है कि रैली के दिन पूरा पटना शहर नरेंद्र मोदी के समर्थकों से लबालब भरा होगा. पांडेय ने यह भी कहा कि ऐतिहासिक भीड़ के बावजूद रैली पूरी तरह अनुशासित होगी और हमारे कार्यकर्ता इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि आम जनता को रैली से कोई परेशानी न हो. भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपाल नारायण सिंह कहते हैं कि लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे यह आभास हो रहा है कि 27 अक्टूबर की हूंकार रैली बिहार में हुई सारी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ देगी. भाजपा प्रवक्ता सुधीर शर्मा भी दावा करते हैं कि ऐसी रैली न कभी हुई थी और न कभी आगे होगी. पूरा बिहार इस दिन नरेंद्र मोदी को सुनने पटना की ओर कूच कर जाएगा, लेकिन राजद सांसद रामकृपाल यादव ऐसा नहीं मानते. वह कहते हैं कि भाजपा के लोग केवल हवा बनाना जानते हैं. रैली टांय-टांय फिस्स हो जाएगी. नरेंद्र मोदी को बिहार के लोग रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यह अमनप्रिय प्रदेश है. धर्मनिरपेक्षता यहां की विरासत है और इसे ख़त्म करने वालों को बिहार कैसे पसंद कर सकता है.

बहरहाल रैली के दिन भाजपा कुछ नए राजनीतिक साथियों को भी अपना सकती है. बताया जा रहा है कि जदयू व राजद के कई बड़े नेता इस दिन नरेंद्र मोदी के सामने भाजपा का दामन थाम सकते हैं. इनमें जदयू के कई सांसद शामिल हैं. इसके अलावा, इस दिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एनडीए में शामिल होने की भी संभावना है. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हूंकार रैली के माध्यम से भाजपा ख़ुद को और नरेंद्र मोदी को बिहार में स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रही है. ऐसा करके ही मिशन 272 को भाजपा अमलीजाम पहना सकती है. भाजपा नेताओं को यह अच्छी तरह पता है कि रैली की असफलता उनकी सारी संभावनाओं को धूमिल कर देगी. इसलिए पार्टी चूक की कोई गुंजाइश छोड़ने के मूड में नहीं है. भाजपा का हर कार्यकर्ता नमो-नमो के जाप में इस उम्मीद से लगा है कि जदयू का साथ छूटने के बाद अब यही मंत्र उसे मंजिल तक पहुंचा सकता है. नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद बसंल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का जादू बिहार में आम लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा है और यही करिश्मा भाजपा को अपनी चुनावी मंजिल तक ले जाने का माद्दा रखती है. बंसल का नारा है, अबकी बारी नरेंद्र भाई.■

feedback@chauthiduniya.com

वाल्मीकि /शशांक सांडिल्य

शिवहर

राजद की आंतरिक कलह घातक हो सकती है

बाढ़, सुखाड़ व नक्सलवादी घटनाओं को लेकर शिवहर ज़िले में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी ज़ोरों पर है. तक़रीबन सभी दलों ने अपने पार्टी का चुनावी पतवार थामना शुरू कर दिया है. फिलहाल शिवहर ज़िला राजद भारी अंर्तकलह के दौर से गुजर रहा है. नतीजतन चुनाव में युवाओं को तरजीह देने की घोषणा करने वाले पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी की अब बोलती बंद होने लगी है. कारण यह है कि पार्टी के तीन धुरंधर पूर्व सांसदों के बीच एक युवा कार्यकर्ता की दावेदारी ने सभी को सांसत में डाल दिया है. पिछले तक़रीबन दो माह के अंदर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद व उनके पुत्र तेजस्वी यादव की शिवहर यात्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार कर दिया है, लेकिन पार्टी के लिए यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि कार्यक्रम आयोजन के साथ ही पार्टी का अंर्तकलह भी परवान चढ़ने लगा है. शिवहर ज़िले की राजनीति में सक्रिय रहे तीन पूर्व सांसदों सीताराम सिंह, मो अनवारुल हक़ और रघुनाथ झा आगामी लोकसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी पार्टी की ओर से टिकट पाने को लेकर एड़ी–चोटी एक किए हुए हैं. तीनों धुरंधर एक दूसरे को पीछे छोड़ किसी भी प्रकार से टिकट पाने को आतुर हैं. ज़िले की राजनीति पर पैनी नज़र रखने वालों की माने तो तीनों धुरंधरों का अंदर ही अंदर जारी शीतयुद्ध राजद के लिए घातक साबित हो रहा है. चर्चा है कि तीनों में से किसी एक को भी अगर टिकट मिला तो पार्टी के अंदर भीतरघात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. दूसरी बात यह कि तीन राजनीतिक हस्तियों के बीच एक युवा पार्टी नेता अंगेश कुमार सिंह की सक्रियता भी धुरंधरों के लिए परेशानी का सबब बनने लगी है. हालांकि युवाओं को चुनाव में तरजीह दिए जाने की वकालत करने वाले लालू पुत्र तेजस्वी की फिलहाल शिवहर सीट के संबंध में बोलती बंद हो चुकी है. पिछले दिनों शिवहर आगमन के

दौरान अतिथि गृह में स्थानीय पत्रकारों के समक्ष युवा मामले को टालते हुए कहा कि जो जनता चाहेगी, वही होगा. पार्टी जिसके लिए निर्णय करेगी, वही मान्य होगा, लेकिन शिवहर की राजनीति तेजस्वी के इस बात को फिलहाल नहीं पचा पा रही है. शिवहर ज़िला राजद में जहां तक अंर्तकलह की बात है, तो सबसे पहले पार्टी के जिलाध्यक्ष चुनाव के दौरान यह मामला सामने आया था. उस वक्त पूर्व सांसद रघुनाथ झा ने डॉ. बिंदेश्वरी सिंह पहाड़पुरी को पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाने की मंशा व्यक्त की थी. नतीजतन पूर्व सांसद सीताराम सिंह व मो अनवारुल हक़ ने दूरी बनानी शुरू कर दी थी.

जिलाध्यक्ष के चुनाव के दिन पूर्व सांसद झा के आवास स्थित पार्टी कार्यालय पर राजद डेलीगेट सदस्यों का जमावड़ा लगा था, तो पूर्व सांसद मो. हक़ स्थानीय अतिथि गृह में चुनाव स्थल बदलने एवं युवा को जिलाध्यक्ष बनाने की मांग पर डटे थे. तक़रीबन दो घंटे के गतिरोध के बाद अंतत: चुनाव पर्यवेक्षक ने झा के आवासीय परिसर स्थित कार्यालय में चुनाव संपन्न कराया. चुनाव में झा समर्थित बिंदेश्वरी सिंह पहाड़पुरी जिलाध्यक्ष चुने गये. इसके बाद समाहरणालय मैदान में आयोजित राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की सभा में मंच पर कुर्सी पाने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत भी हुई थी. साथ ही पार्टी के ही दो पूर्व सांसद मो अनवारुल हक और रघुनाथ झा के बीच नोक–झोक भी हो गई थी. हाल में तेजस्वी यादव की सभा में भी अप्रत्यक्ष रूप से शिवहर ज़िला राजद का अंर्तकलह एक बार फिर झलका है, जब पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए पुलिस को सामने आना पड़ा. अब ऐसे हालात में ज़िला राजद की भूमिका आगामी लोकसभा चुनाव में क्या होगी, सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है. पार्टी नेतृत्व की पहल पर सभी को एक मंच पर लाकर राजद की डूबती नैया को जिला में पार लगाने की जुगत की जाएगी अथवा अंर्तकलह के भंवर में पार्टी को डूबोया जाएगा आना वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि तीनों धुरंधरों की दावेदारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी संकट में डाल सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

लखीसराय

चानन थाना को अपना भवन भी नसीब नहीं

सीतेश सुधांशु

एक तरफ़ सुशासन की सरकार पुलिस प्रशासन को जनहित में काम करने, अपराधियों पर अंकुश लगाने, नक्सलवाद के निपटारे एवं अन्य तरह की आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लोगों को सहयोग करने की बात कहती है, वहीं सुविधा के नाम पर एक छप्पर भी यहां उपलब्ध नहीं है. ऐसे में पुलिस प्रशासन की मानसिकता क्या होगी और वह भला कैसे लोगों की सहयोगी हो सकते हैं. यह बानगी लखीसराय ज़िला अंतर्गत नक्सल प्रभावित चानन थाना की है. हालांकि नक्सल प्रभावित थाना के अंतर्गत कजरा व पीरी बाज़ार थाना का भी नाम आता है, लेकिन वहां कम से कम थाना भवन का अपना छत तो है. अपने स्थापना काल 1985 से ही चानन थाना जर्जर खैरा स्टेट की कचहरी में संचालित होकर अपराधियों पर नकेल कसने की नाक़ाम कोशिश करती रही है. अंचलाधिकारी चानन के अनुसार भौगोलिक दृष्टिकोण से इस थाना का क्षेत्रफल 176 वर्ग किलो मीटर है तथा 2011 के जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 1,06,82 है जिसमें

चानन थाना भवन

55,775 पुरूष 52.21 प्रतिशत तथा 51,046 महिला 47.78 प्रतिशत हैं. एसआई पवन कुमार के अनुसार कुल 10 पंचायत के 36 गांवों में सुशासन का डंडा चलाने के लिए चौकीदार के 32 पद सृजित हैं, जिसमें तैनाती 25 की है. दफादार का सृजित पद 04 है, लेकिन तैनाती 02 की है. एएसआई का 04 पद सृजित है, लेकिन तैनाती 04 की है. एसआई का सृजित पद 03 है, लेकिन तैनाती ज़रूरत के हिसाब से कभी 03 तो कभी 04 तो कभी 05 भी हो जाती है. आरक्षी के 06 सृजित पद में तैनाती 01 की है. हवलदार का पद यहां सृजित नहीं किया गया है. मुंशी का 01 पद सृजित है, जिसमें 01 की तैनाती भी है. महिला पुलिस का पद सृजित नहीं है तथा ज़रूरत के हिसाब से महिला पुलिस को टाउन थाना, महिला थाना व पुलिस लाईन लखीसराय से सुविधा ली जाती है. थाने के बेसिक फोन की स्थिति हास्यास्पद है, क्योंकि यह कब से ख़राब पड़ा है और इसके बारे में यहां तैनात किसी भी कर्मी को पता ही नहीं है. थाने में दर्ज मामले का आकड़ा वर्ष के हिसाब से घटता–बढ़ता रहा है. वर्ष 2007 में 92, 2008 में 93, 2009 में 102, 2010 में 70, 2011 में 61, 2012 में 52 तथा वर्तमान वर्ष 2013 में अब तक कुल 56 मामले दर्ज हैं. थाने में तैनात एसआई वाई एन पांडेय का कहना है कि क़रीब दो वर्ष पूर्व थाना का भवन निर्माण से संबंधित टेंडर रामपुर हौदा के लिए हो चुका है, लेकिन भवन निर्माण शुरू होने या ना होने के संबंध में जानकारी नहीं है. जानकारी के अनुसार टेंडर हो जाने के बावजूद भवन निर्माण से संबंधित शुरुआत यानी नींव खुदाई का भी काम अब तक शुरू नहीं किया जा सका है. थाने में तैनात कई कर्मियों ने बताया कि सबसे ज़्यादा परेशानी बरसात में होती है, क्योंकि छप्पर से जगह–जगह पानी टपकने लगता है. ऐसी स्थिति में ज़रूरी काग़ज़ात को बचाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है. किसी तरह प्लास्टिक से ढंककर बचाने की केशिश की जाती है. पुलिस प्रशासन की नज़र में चानन क्षेत्र एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है. यहां आये दिन नक्सली गतिविधियां होती ही रहती हैं. कई बार नक्सलियों द्वारा थाना भवन उड़ाने की भी धमकी दी जाती रही है, लेकिन थाना भवन गांव की आबादी के बीच रहने के कारण अभी तक यह बचा हुआ है. जर्जर भवन की दिवार से कभी–कभी छोटे–छोटे विषैले सर्प–बिच्छू भी निकलते रहते हैं. हाजत नहीं रहने के कारण बंदियों को रखने में भी काफ़ी असुविधा होती है. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चानन अंचल मंत्री कार्तिक वर्मा ने कहा कि थाना भवन का निर्माण एवं बदहाली के बारे में कई बार ज़िला प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन ज़िला प्रशासन द्वारा सिर्फ़ आश्वासन की घुट्टी ही पिलाई जा रही है. बाध्य होकर जनता के सहयोग से उग्र आंदोलन किया जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

सारण की राजनीति ग़रम हुई

अगले लोकसभा चुनाव को लेकर सारण के दोनों लोकसभा क्षेत्र छपरा और महराजगंज में सभी दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं. सभी दल मानते हैं कि इस क्षेत्र के दर्जनों जातियों एवं समुदायों में पैठ के बिना किसी भी लोकसभा क्षेत्र पर क़ब्ज़ा जमाना संभव नहीं है.

चंद्रप्रकाश राज

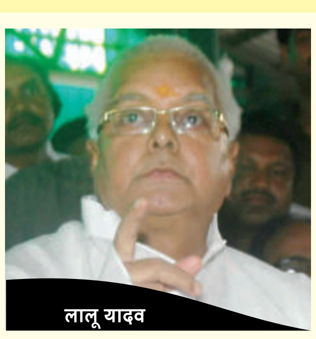
लालू यादव

मिथिलेश कुमार सिंह

प्रभुनाथ सिंह

राजनीव प्रताप रूढ़ी

अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्व मंत्री व जेपी सम्मान योजना के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह और राजद के सांसद प्रभुनाथ सिंह समेत सभी नेताओं ने क्षेत्र में अपनी गतिविधियां तेज कर दी है. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व महासचिव राजीव प्रताप रूढ़ी भी इसी तरह एसएमएस से हाइटेक संपर्क की शुरुआत कर चुके हैं. विभिन्न दल अपने मृत्यप्राय हो चुके संगठन को पुनर्जीवित करने में लगे हुए हैं और साथ ही नए मंच और मोर्चों का भी गठन किया जा रहा है. इसी कार्य को अमलीजामा पहनाने के लिए भाजपा का विश्वासघात दिवस तो जदयू व राजद में सम्मेलनों का दौर जारी है. उपेंद्र कुशवाहा की लोक समता पार्टी भी दो नेताओं रामबिहारी सिंह व विज्ञान स्वरूप सिंह के सहारे अशोक कुशवाहा और पार्थ कुमार यादव से प्रतिदिन संवाद कर रहे हैं. कांग्रेस भी अपने ज़िला अध्यक्ष मनोज सिंह भारद्वाज के अलावा सारण कांग्रेस के युवा नेता अनिल कुमार सिंह को महत्वपूर्ण प्रभार दिया है.

क्षेत्रिय क्षत्रपों एवं ज़मीनी कार्यकर्ताओं की मदद से पिछले लोकसभा चुनाव में विजय हासिल करने वाली राजद 2014 की तैयारी सांसद प्रभुनाथ सिंह, विधायक जितेंद्र कुमार राय, पूर्व मंत्री उदित राय, प्रवक्ता हरेंद्र सिंह, बरवा के जितेंद्र सिंह, युवा व्यवसायी राजकमल चुन्नू जी, रवि सिंह, हेमनारायण सिंह, आमडाढ़ी के महेश सिंह, प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, जिलाध्यक्ष बेलागुल मोबिन समेत दर्जनों पूर्व विधायकों को भी कई तरह की ज़िम्मेदारियां सौंपने की तैयारी में है. जदयू अपने पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार सिंह के अनुभवों के साथ विधानपरिषद के उपसभापति सलीम परवेज, घूमल सिंह, छोटेलाल राय, जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार मंटू, शैलेंद्र प्रताप सिंह, रामप्रवेश राय, कामेश्वर सिह, संतोष कुमार महतो पूर्व मुखिया गुड्डू सिंह, सुपेंद्र चौधरी, मनोज सिंह, पुरुषोत्तम सिंह गुड्डू सहित कई अनुभवी नेताओं को भी लगातार आगामी योजनाओं पर अमल करने की तैयारी के लिए मार्गदर्शन दे रही है. भाजपा जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में सत्येंद्र सिंह, कामेश्वर ओझा, पूर्व मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रिवाल, जनक सिंह, विनय सिंह, ज्ञानचंद्र मांझी, बृजमोहन सिंह, अजय अजनबी, वंशीधर तिवारी, प्रवक्ता प्रकाश रंजन निकू, जय प्रकाश वर्मा, गामा सिंह, धर्मेंद्र चौहान के अलावा विहिप, बजरंग दल भी नेताओं का लगातार मार्गदर्शन कर रहा है. कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी जितेंद्र स्वामी, रामनारायण यादव, राकेश सिंहा, शंकर चौधरी, रामस्वरूप राय, सुबोध कुमार जायसवाल, अशोक जयसवाल, अनुप श्रीवास्तव सहित पार्टी पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी रखे रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच दलों में आंतरिक कलह लगातार दिखाई दे रही है. मढ़ौरा के पूर्व विधायक लालबाबू राय के नेतृत्व में कई नेता जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार मंटू को अक्षम करार दे रहे हैं. भाजपा में भी यह रोग लग चुका है. जनार्दन सिंह सिग्रिवाल के मंत्रित्व काल में ज़िले में हुए उनके दर्जनों कार्यक्रमों में एक बार भी राज्यसभा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी नज़र नहीं आए. यह ज़िले में चर्चा का विषय है. वहीं समाजवादी नेता ललन सिंह, भाजपा प्रदेश के किसान नेता परमात्मा सिंह, पूर्व ज़िला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, पूर्व ज़िला महामंत्री कन्हैया सिंह व रणजीत कुमार सिंह की भी उपयोगिता पार्टी में नज़र नहीं आ रही है.

कांग्रेस नेता नज़रे हसन व नई ज़िम्मेदारियों से लैश ज़िला समन्वयक अनिल कुमार सिंह ने तो जिलाध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए गुटबाज़ी को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है. राजद में सब कुछ फौरी तौर पर शांत दिख रहा है, लेकिन इसमें भी पुराने कार्यकर्ता अपने को उपेक्षित बताते हुए चुनाव में परिणाम भुगताने तक की बात कह रहे हैं. सभी दल महिला इकाइयों, युवा संगठन, अतिपिछड़ा, संगठन, दलित व महिलादलित संगठन एवं अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए लगातार कई कार्यक्रम चलाकर पंचायत व बूथस्तर तक इन संगठनों के विस्तार में लगे हैं, लेकिन अंतत: ज़मीनी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय क्षत्रपों को अपने पाले में लाने वाले दल ही अपने प्रत्याशियों को विजयश्री दिलवा पाएंगे.

अगले चुनाव के मद्देजऩर राजद सुप्रिमो लालू प्रसाद यादव, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी, जदयू के राज्यसभा सदस्य आरसीपी सिंहा व विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी पूर्व मंत्री विजय शंकर दूबे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेन्द्र कुश्वाहा, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान भी लगातार बदल रही परिस्थितियों पर नज़र रख रहे हैं. वहीं पूर्व जिलापरिषद अध्यक्ष शिवपूजन राय भी दोनों क्षेत्रों में कांटे की टक्कर से इनकार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पूर्व विधायक विद्याभूषण सिंह नरेन्द्र मोदी की लहर की चर्चा करते हुए इसे समाजवादी राजनीति के लिए ख़तरे का संकेत मान रहे हैं. बदली हुई परिस्थितियों में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी चुनावी गणित को बदल सकती है.■

feedback@chauthiduniya.com

» एक नज़र «

जदयू कार्यकर्ताओं ने धरना दिया

सीतामढ़ी के बैरगनिया में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर में नौ सूत्री मांगों के समर्थन में जदयू कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया. ज़िला महासचिव प्रो. राज कुमार सिंह ने बताया कि मांगों में बैरगनिया को आदर्श स्टेशन का दर्जा देने, ओवरब्रिज का निर्माण कराने, पानी टंकी चालू करने, टिकट खिड़की बढ़ाने, पर्याप्त रौशनी देने, खाली ज़मीन आवंटन करने समेत अन्य मांग शामिल है. धरनार्थियों ने स्टेशन अधीक्षक सुभाष कुमार, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर श्रीकांत सिंह व स्थानीय इंचार्ज राम भरोसे प्रसाद को एक ज्ञापन सौंपा. मौक़े पर कैलाश बिहारी मिश्रा, महासचिव डॉ. अवधेश नायक, भोला साह व मोहन प्रसाद समेत अन्य थे.

स्वयं सेवक इकाई का गठन किया

सीतामढ़ी के बैरगनिया प्रखंड के रामबिलास कॉलेज के छात्रावास में सांख्यिकी स्वयं सेवकों की एक बैठक ज़िला कार्यकारिणी अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई. बैठक में सर्वसम्मति से अरविंद कुमार को प्रखंड अध्यक्ष, सुशील कुमार को उपाध्यक्ष, पुरुषोत्तम कुमार को सचिव, ललन कुमार कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी संजय कुमार गुप्ता, प्रवक्ता राजीव कुमार के अलावा सरोज कुमार झा, नवनीत कुमार, प्रमोद कुमार पटेल, मो. अबुलेस व उपेंद्र राय बतौर सदस्य मनोनीत किए गए. *– विनोद कुमार*

नरेंद्र मोदी को बधाई दी

सीतामढ़ी भाजपा द्वारा घोषित प्रधानमंत्री प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काट कर जश्न मनाया. कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए देश की कमान नमो के हाथ आने की कामना की. स्थानीय श्रद्धानंद अनाथालय में भाजपा क्रीडा मंच के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार शक्ति एवं महामंत्री मनोज बैठा द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान अनाथ बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री व खेल का सामान वितरित किया गया. मौक़े पर जिलाध्यक्ष मनोज कुमार, महामंत्री श्याम सुंदर सिंह अमिताभ, नरोत्तम व्यास, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष इंदिरा पांडेय, किरण श्रीवास्तव, मुन्नी ख़ातून, नगर अध्यक्ष विजय प्रसाद स्वर्णकार व मो. अताबुल अंसारी समेत अन्य थे. *– ब्रजेश*

नीतीश ने विश्वासघात किया : कादरी

सीतामढ़ी भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य सह प्रदेश उपाध्यक्ष तुफैल कादरी ने कहा कि राजनीति में विश्वासघात की शुरुआत नीतीश ने की है. प्रखंड से लेकर ज़िला स्तर तक प्रशासनिक दलालों के माध्यम से नीतीश सरकार ने ग़रीबों का पैसा लूटा है. उन्होंने कहा कि बिहार मदरसा बोर्ड को छठा वेतन देना महज एक छलावा है. साथ ही यह भी कहा कि नीतीश का पाकिस्तान दौरा केवल मुस्लिम वोट को पाने को लेकर था. भाजपा के नरेंद्र भाई मोदी से मुकाबला करना नीतीश कुमार के बूते की बात नहीं है. मौक़े पर पूर्व जिलाध्यक्ष रामा शंकर प्रसाद, अख्तर इमाम, मो सलीम, शिवहर अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष एहसान अहमद समेत अन्य थे. *– वाल्मीकि*

मोदी के साथ होने का सवाल ही नहीं–देवेन्द्र यादव

नए बनते – बिगड़ते सियासी समीकरणों और उठा–पटक की ख़बरों के दरम्यान बिहार समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा है कि वे और उनकी पार्टी पूर्णत: समाजवादी सोच और विचारधारा के है. नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं के मद्देनज़र भले ही दूसरी पार्टियां या नेता, नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने की मशक्क़त कर रहे हों, पर वे और उनकी पार्टी सत्ता और कुर्सी की चाह में ऐसा कभी नहीं कर सकते. पिछले दिनों इस किस्म की खबरे आईं थीं कि देवेन्द्र प्रसाद यादव ने मोदी से बात की है और उन्हें समर्थन देने को कहा है. पर देवेन्द्र प्रसाद यादव ने इस संभावना से पूरी तरह इनकार किया है. उन्होंने कहा कि ना अभी और ना ही कभी भविष्य में वे नरेन्द्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे.

राकांपा शांति व्यवस्था को लेकर गंभीर

सीतामढ़ी राकांपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सह पूर्व मंत्री नवल किशोर शाही ने कहा कि देश में शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर पार्टी गंभीर है. शाही ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति हैं. उन्होंने कहा कि मोदी को शीर्ष पर पहुंचाने में नीतीश का महत्वपूर्ण योगदान है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सूबे के लोग बिजली की समस्या से परेशान हैं और किसान सिंचाई की समस्या से, लेकिन इसके निदान के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है. सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सूबे में उच्च शिक्षा का बुरा हाल है. अब तक राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी ख़ास नहीं कर पाई है. मौक़े पर प्रो सुरेश प्रसाद सिंह व अशोक कुमार समेत अन्य थे. *– वाल्मीकि*

चिकित्सक सालों से ग़ायब हैं

फरवरी 2009 को चतरा ज़िले में आयुश चिकित्सक के रूप में डॉ. निर्मल कुमार (आयुर्वेद) और डॉ. अनवर इमाम (होम्योपैथ) की नियुक्ति हंटरगंज प्रखंड में हुई थी. सूत्र बताते हैं कि नियुक्ति को अब तक पांच साल बीत चुके हैं, लेकिन एक भी दिन इन दोनों चिकित्सकों को किसी ने सेवा क्षेत्र में देखा तक नहीं है. ये दोनों चिकित्सक बगैर किसी सेवा के अपना वेतन उठा रहे हैं. चतरा के सिविल सर्जन डॉ. विनोद उरांव कहते हैं कि हमें इस बात की जानकारी हैं, लेकिन हमारे विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है. चतरा के उपायुक्त हंसराज सिंह ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो जांच के उपरांत उनके मानदेय को रोक दिया जाएगा.

दौरे पर पूर्व मंत्री

चतरा विधानसभा के पूर्व मंत्री सत्यानंद भोगता इन दिनों क्षेत्र के पांचों प्रखंड चतरा, हंटरगंज, प्रतापपुर, कुंदा व कान्हाचट्टी का दौरा कर रहे हैं. इस क्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष विनय सिंह, व्यपार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रदीप केशरी, पूर्व जिलाध्यक्ष रामविलास सिंह, महेंद्र यादव, विनोद सिंह आदि उनके साथ होते हैं. बताते चलें कि पिछले विधानसभा चुनाव में वे सिमरिया विधानसभा से चुनाव हार गये थे और इस बार उनका चतरा विधानसभा से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है. भोगता कहते हैं कि वर्तमान विधायक ने जनता के साथ वादाख़िलाफ़ी की है और जनता उन्हें सबक अवश्य सिखाएगी. *– अमरेंद्र सिंह*

गोपाल गुप्ता राजद के प्रदेश महासचिव बने

अतिपिछड़ा कानू महासभा के प्रदेश संयोजक सह पूर्व बीस सूत्री उपाध्यक्ष गोपाल प्रसाद गुप्ता को राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव मनोनित किया गया है. गुप्ता के प्रदेश महासचिव बनाए जाने से राजद कार्यकर्ताओं, ख़ासकर अतिपिछड़ा एवं वैश्य समाज में खुशी है. राजद नेताओं ने गुप्ता को बधाई देते हुए कहा है कि गुप्ता पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ सिपाही हैं तथा उनके महासचिव बनने से पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी. ■

– राजेश कुमार

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

3 नवंबर, 1982 को सरकार ने सोनो से पांच किमी की दूरी पर स्थित करमटिया को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था, क्योंकि वहां भूतल से कुछ ही फीट की दूरी पर स्वर्ण कण मिले थे. कई वर्षों तक यहां भू-छेदन कार्य चलता रहा, तब भूगर्भ वैज्ञानिकों ने अपने सर्वेक्षण में सोनो के आस-पास के क्षेत्रों को खनिज संपदा से परिपूर्ण बताया था.

नीतीश झूठे आंकड़े दे रहे हैं : उदय

नीरज सिंह

जदयू से अलगाव के बाद अब पूर्णिया के सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उनकी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ अब और भी अधिक मुखर हो गए हैं और उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं. आरोपों की बौछार के बीच वह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के पास नैतिकता नाम की चीज नहीं रह गई है. विकास की सच्चाई का आलम यह है कि कटिहार के कोढा विधानसभा क्षेत्र के आठ प्रधानमंत्री सड़कों में से किसी भी सड़क पर एक टोकरी मिट्टी भी अब तक नहीं डाली गई है, जबकि रिपोर्ट कार्ड में इन सभी सड़कों को पूरा हुआ दिखाया गया है. सरकार झूठे आंकड़े पेश कर मजाक कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है. देश के आतंकवादियों का राज्य शरणस्थली बनता जा रहा है और अपराध का ग्राफ लालू के तथाकथित जंगल राज्य से ऊपर पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि एक बेटी के पिता ने उनसे शिकायत कि उनकी बेटी कई दिनों से गाायब है, लेकिन पुलिस उनकी नहीं सुन रही है. पुलिस द्वारा धमकाने और फर्जी मुकदमे की बात आये दिन सामने आ रही है और थाने की बोली लग रही है. बीपीएल समेत विभिन्न योजनाओं के लाभ में क्या धांधली है? यह बात किसी से छुपी नहीं है. बिहार में दूसरे राज्यों से घोटाले में आरोपित अधिकारियों का पदस्थापन कराया जा रहा है. बिहार में अधिकारियों के पदस्थापन में लेन-देन का खेल चल रहा है. मोटी रकम देकर जिले में पदस्थापित होने वाले अधिकारी जिले को अपने हिसाब से चला रहे हैं, जहां अधिकारियों को लूट की खुली छुट मिली हुई है. आज बिहार के मुखिया कह रहे हैं कि बिहार से अन्य राज्यों की तरफ पलायन रुका है, जबकि हाल में दिल्ली में जो रिपोर्ट आइ है, उसमें कहा गया है कि दिल्ली में बिहार के लोंगो की संख्या पिछले पांच वर्षों में चार गुणी बढ़ी है. नीतीश कुमार सुशासन विकास मॉडल और उद्योग की बाते कर रहे हैं, वह आखिर कहां दिख रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार एक भी महादलित टोला या अल्पसंख्यक समुदाय के गांव में जाकर विकास की किरण दिखला दे तो वे मान लेंगे की इस समुदाय के गांव मे विकास हुआ है. सांसद ने कहा कि पूर्णिया में बिजली की व्यवस्था में सुधार के लिए सांसद निधि से 12 करोड़ रुपया राज्य सरकार के विधुत विभाग को दिए, लेकिन बिजली मंत्री के नीति के चलते वह रुपया वहीं पड़ा हुआ है और आज तक बिजली की समस्या दूर नहीं हुई. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने से भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

नर्सिंग की पढ़ाई शुरू

यहां के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को देखते हुए यहां नर्सिंग शिक्षा की शुरुआत की गई है. नर्सिंग शिक्षा प्रारंभ होने से पूर्णिया प्रमंडल के चारों ज़िलों समेत पड़ोसी राज्य बंगाल और पड़ोसी देश नेपाल के छात्रों को भी लाभ मिलेगा...

नीरज कुमार सिंह

सीमांचल का इलाक़ा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है. यहां के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को देखते हुए यहां नर्सिंग शिक्षा की शुरुआत की गई है. यहां पूर्णिया के प्रसिद्ध माता अनुपमा देवी टेस्ट ट्यूब बेबी संस्थान के निदेशक डॉ. विजय राधवन ने पूर्णिया में नर्सिंग शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया, जिसके तहत पूर्णिया के नामचीन चिकित्सक डॉ. एके पाठक, डॉ. अशोक चौधरी, डॉ. केके चौधरी, मनोचिकित्सक प्रणव प्रकाश डॉ. डीके कपूर एवं स्थानीय बुद्धिजीवी वर्ग की गरिमामयी उपस्थिति में डॉ. एके पाठक के कर कमलों द्वारा नर्सिंग शिक्षा संस्थान का उद्घाटन किया गया, इस अवसर पर टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं संस्थान के निदेशक डॉ. राधवन ने जानकारी दी की संस्थान में लैब टैक्नीशियन एमएलटी, डीएमएलटी, हेल्थ मैनेजमेंट, ओटी ट्रीटमेंट और एएनएम नर्सिंग शिक्षा का कोर्स को चालू किया गया है, जिसकी मान्यता कर्नाटक ऑपर विश्व विद्यालय, मगध विश्वविद्यालय और सिक्किम, मनिपाल यूनिवर्सिटी से ली गई है. नर्सिंग शिक्षा प्रारंभ होने से पूर्णिया प्रमंडल के चारों ज़िलों कटिहार, अररिया, किशनगंज समेत पड़ोसी राज्य बंगाल और पड़ोसी देश नेपाल के छात्रों को भी लाभ मिलेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

पश्चिम चंपारण
खिलाड़ियों को नहीं मिलता सम्मान

अवधेश कुमार शर्मा

बिहार की नीतीश सरकार पढ़ाई के साथ-साथ खेल पर भी करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष बहाती है. अनेक घोषणाएं करती है, लेकिन राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके खिलाड़ियों के लिए कोई कदम नहीं उठाती. नरकटियागंज शहर के नया टोला मुहल्ला निवासी व रिक्शा चालक पन्नालाल पासवान की 12 वर्षीय पुत्री सोनी कुमारी इसका ज्वलंत उदाहरण है. श्रीलंका में आयोजित महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम की ओर से शामिल होकर सोनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारतीय चयनकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया था. इससे पूर्व सोनी ने पहली बार सोनी ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित एशियन फुटबॉल फेडरेशन (एएफसी) में बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक गोल दागा था, जिससे भारतीय टीम ने कामयाबी का परचम लहराया था. इसके अलावा, ईरान के साथ फाइनल मुकाबले में सोनी द्वारा किए गए एकमात्र गोल की बदौलत भारतीय टीम 1-0 से विजयी हुई. गौरतलब है कि सोनी के पिता पन्नालाल पासवान तांगा-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करते है. सोनी की खेल प्रतिभा को उसके प्रशिक्षक सुनील वर्मा ने पहचाना, उसे इस लायक बनाया कि वह भारतीय टीम में खेल सके. शिकारपुर स्टेट के आलोक प्रसाद वर्मा के सहयोग से सुनील कुमार वर्मा ने नरकटियागंज में महिला फुटबॉल टीम का शुभारंभ किया. सबसे पहली फुटबॉलर निकली वाजदा तब्बसुम, जिसने भारतीय महिला फुटबॉल टीम में अपनी जगह बनाई. इसके बाद से सुनील वर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, खेल-कूद को समर्पित सुनील ने महिला फुटबॉल को बुलंदी पर पहुंचा दिया. फिलहाल सुनील टीपी वर्मा कॉलेज में खेल प्रशिक्षक है. सोनी का कहना है कि वह आज जिस मुकाम पर पहुंची है, इसका श्रेय सुनील वर्मा को ही जाता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रौशन करने वाली नरकटियागंज की सोनी को आज भी समुचित प्रश्रय की आवश्यकता है. सरकार अगर ध्यान देती तो सोनी आज की तारिख में काफी आगे होती और उसके आर्थिक व सामाजिक हालत में भी सुधार होता. फुटबॉल के खेल में इसे प्रारंभिक प्रशिक्षक तो मिला, लेकिन अंतरराष्ट्रीय ख्याति के लिए इसे राष्ट्रीय प्रशिक्षक चाहिए और सरकार को इस दिशा में कदम उठाने होंगे, तभी एक छोटे शहरों की लड़कियां भी सानिया मिर्जा, ज्वाला गट्टा, सायना नेहवाल और अन्य उभरती-चमकती खिलाड़ियों की भांति सफलता की सीढियां चढ सकेंगी और देश का नाम रौशन करेगी. सोनी को भले सरकारी उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है, अलबत्ता क्षेत्र की खिलाड़ियों के लिए वह रोल मॉडल अवश्य बन गई है. अपने क्षेत्र की खिलाड़ियो के बीच तांगे वाले की बेटी सफलता से अन्य खिलाड़ियों में जोश व उमंग भर गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मफिया की मुट्ठी में खनिज संपदा

मनोज भारद्वाज

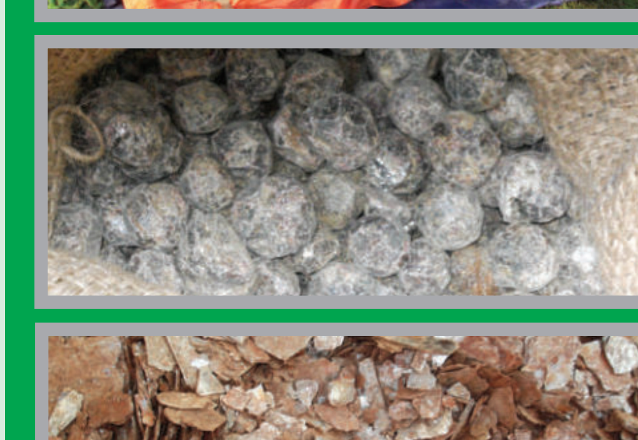

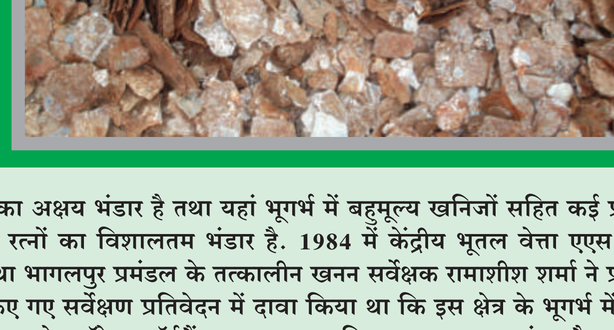

जमुई के नक्सल प्रभावित क्षेत्र चरका पत्थर के विभिन्न हिस्सों में अवैध ढंग से संचालित माइंस से अब तक कई टन गारनेट व पोखराज पत्थरों की खेप माफ़िया द्वारा अन्य प्रदेशों में भेजी जा चुकी है. ऐसी बात नहीं कि इन इलाक़ों के प्राकृतिक संपदाओं की जानकारी सरकार को नहीं है. इधर दो महीनों में लाल गलियारे के भिन्न-भिन्न ठिकानों पर छापेमारी में वन विभाग एवं खनन विभाग को बड़ी मात्रा में गारनेट, पुखराज व अबरख हाथ लगे हैं. चूंकि इन इलाक़ों में संचालित सभी माइंस सुरक्षित वन क्षेत्र में है, लिहाजा झाझा रेंज के वन क्षेत्र पदाधिकारी आनंद कुमार द्वारा इस गोरखधंधे में संलिप्त तक़रीबन एक दर्जन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और कुछ मामलों में गिरफ्तारी भी की गई है. खनन विभाग से जुड़े सूत्रों का मानना है कि पिछले छह महीनों में इस इलाक़े से 20 टन से ज़्यादा गारनेट पत्थरों को गया की मंडियों में भेजा गया है.

पिछले कई वर्षों से अवैध खनन का मामला प्रकाश में नहीं आ पाया था, लेकिन कामगारों द्वारा मजदूरी बढ़ाने को लेकर यहां के स्थानीय माफ़िया से हुई तक़रार के बाद इस गोरख धंधे का ख़ुलासा अब हो गया है. यहां गोमेद-पुखराज व अबरख के अवैध खनन से हो रही राजस्व की राष्ट्रीय क्षति पर सरकार की उदासिनता कई तरह के सवाल खड़े करती है. आश्चर्य की बात तो यह है कि इस प्राकृतिक संपदा के संपोषण व संरक्षण की दिशा में अभी तक सरकार द्वारा मामूली प्रयास भी नहीं किए गए हैं, लिहाज़ा इलाक़े से इन क़ीमती पत्थरों की अवैध बिक्री लगातार जारी है.

12 अप्रैल, 2002 को तत्कालीन केंद्रीय खनन मंत्री रामविलास पासवान ने सोनो में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि करमटिया सहित अन्य जगहों का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया जाएगा, लेकिन उनकी घोषणा पर अब तक अमल नहीं हो सका है. बताते चलें कि 3 नवंबर, 1982 को सरकार ने सोनो से पांच किमी की दूरी पर स्थित करमटिया को इसलिए सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था कि वहां भूतल से कुछ फीट की दूरी पर ही स्वर्ण कण पाए गए थे. इस दौरान कई वर्षों तक वहां भू-छेदन कार्य चलता रहा, तब भूगर्भ वैज्ञानिकों ने अपने सर्वेक्षण में सोनो के आस-पास के क्षेत्रों को खनिज संपदा से परिपूर्ण बताया था. वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण में इसकी पुष्टि की थी कि करमटिया में 24 कैरेट सोनेलका अक्षय भंडार है तथा यहां भूगर्भ में बहुमूल्य खनिजों सहित कई प्रकार के रत्नों का विशालतम भंडार है. 1984 में केंद्रीय भूतल वेत्ता एएस सिंह तथा भागलपुर प्रमंडल के तत्कालीन खनन सर्वेक्षक रामाशीश शर्मा ने प्रस्तुत किए गए सर्वेक्षण प्रतिवेदन में दावा किया था कि इस क्षेत्र के भूगर्भ में तीन प्रकार के कॉट्रिज, हॉर्नबैंड तथा माइका सिस्ट का अक्षुण्ण संग्रह है. सोनो, चरका पत्थर, बटिया देहरीडीह (नाढी पहाड़ी) तथा नरगंजो के तक़रीबन 60 किमी की परिधि में यूरेनियम, बेरेलियम, अबरख, नीलम, पन्ना, पुखराज, गोमेद सहित कई बहुमूल्य खनिज रत्न भूतल से 25 से 350 फीट नीचे तक पाए जाने की संभावना बताई गई थी.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
07 अक्टूबर-14 अक्टूबर 2013
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड

दंगा शांत राजनीति जारी

मुज़फ़्फ़रनगर में लगाई गई सांप्रदायिकता की आग शांत हो गई. जनता अपने जख्मों से जूझ रही है, लेकिन सियासी दल जनता के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह सियासत करने में लगे हैं. भाजपा ने दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान कर फायदा उठाने की कोशिश की. अब भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने में जुटे हैं. इतना कुछ हो जाने के बाद भी प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल को खत्म करने की जगह उसे और हवा देने की ही कोशिश होती दिख रही हैं...

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश शांत हो गया है. दंगों के दर्द को पीछे छोड़कर जनता अपने काम धंधे में लग गई है. वह लोग भी अपने गमों को भुलाने की कोशिश में हैं, जिनके परिवार को जान-माल का नुकसान उठाना पड़ा. उन्हें इस बात की चिंता जरूर सता रही है कि दंगों का राजनीतिकरण होने के कारण कहीं असली गुनहगार, जिन्होंने खुल कर हत्याओं, हिंसक वारदातों और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया था, बच न जाएं. क्योंकि अभी तक कथित रूप से दंगा भड़काने वाले कुछ नेताओं और छिटपुट लोगों के अलावा दंगे में शामिल रहने वालों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है. कई बेगुनाह और तमाशबीन ही नहीं, रिक्शा चलाने और मजदूरी करने वालों को भी गुड वर्क दिखाने के चक्कर में पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया है. वहीं असली गुनहगार खुलेआम अपने आकाओं के संरक्षण में घूम रहे हैं. खैर, इन सब बातों के बीच अच्छी खबर यह भी आ रही है कि दहशत कम होते ही शरणार्थी शिविरों में जीवनयापन करने वाले परिवार वापस अपने गांव-देहात की तरफ कूच करने लगे हैं. भाजपा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद भी शांतिपूर्वक निपट गया. अगर कुछ शांत नहीं हुआ है तो राजनीतिक नेताओं की धमा-चौकड़ी. दंगों को लेकर नेताओं के बीच आरोपों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. सभी अपने-अपने हिसाब से दंगा भुनाना चाहते हैं.

दंगों के बाद की राजनीति पर नजर डाली जाए तो समाजवादी नेता भाजपा और कांग्रेस पर दंगा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं तो भाजपा का आरोप है कि दंगा समाजवादी सरकार की साजिश का परिणाम था. कांग्रेस ने भी इसमें अखिलेश सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करके राजनैतिक रोटियां सेंकने की कोशिश की. भाजपाई अपने नेताओं को बेदाग बताते हुए आरोप लगाते हैं कि उनके नेताओं और जनप्रतिनिधियों को साजिशन पकड़ा जा रहा है. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री तो हिंसा ग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा नेताओं को दंगा प्रभावित इलाकों में जाने से रोका जा रहा है, ताकि समाजवादियों और कांग्रेसियों का खेल उजागर न हो जाए. भाजपा, सपा के कद्दावर नेता और मंत्री आजम खान पर कई गंभीर आरोप लगा रही है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उनके निशाने पर हैं. पूरी पठकथा 2014 को ध्यान में रखकर लिखी जा रही है.

भाजपा को इस बात का बेहद मलाल है कि कांग्रेस और उसकी केंद्रीय सरकार और समाजवादी पार्टी और उसकी राज्य सरकार दंगों के नाम पर एक वर्ग विशेष को खुश करने में लगी है, जबकि दंगों से कोई भी अछूता नहीं रहा था. बसपा सुप्रीमो मायावती अपना अलग राग अलाप रही हैं. वह भाजपा और समाजवादी दोनों को निशाने पर लिए हैं. दंगों ने बसपा में प्राण वायु फूंक दी है, बसपाइयों के जबर्दस्त विरोध के चलते अखिलेश सरकार सदन से लेकर सड़क तक पर बैकफुट पर आ गई, लेकिन बसपा को इस समय करारा झटका लगा, जब यह खबर सार्वजनिक हुई की उसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक मुस्लिम महिला सांसद समाजवादी सरकार के मुखिया अखिलेश यादव से करीबी बना कर बसपा के मंसूबों पर पानी फेरने में लगी हैं. खबर लीक होते ही बसपा आलाकमान का पारा चढ़ गया. चर्चा तो यहां तक है कि इसी महिला सांसद की बातों पर विश्वास करके ही समाजवादी सरकार ने भाजपा ही नहीं, बसपा विधायक को भी दबोचा था.

सबके अपने-अपने तर्क हैं. राजनीतिक पंडित कहते हैं कि सपा नहीं चाहती है कि दंगाग्रस्त इलाके में उनके अलावा किसी और जाति का नेता मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश करे.इसीलिए बसपा के कुछ मुस्लिम जनप्रतिनिधियों पर भी लगाम लगाई जा रही है. वैसे भी जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी कैबिनेट मंत्री आजम खान के बहाने समाजवादी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. कभी मुलायम के काफी करीब रहे जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी द्वारा आजम को यूपी का मोदी तक बताया जा रहा है. रही सही कसर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने मुजफ्फरनगर दंगों की तुलना गुजरात दंगों से करके पूरी कर रखी है. जमीयत के महासचिव मौलाना महमूद मदनी शायद ही कोई दिन गुजरता होगा, जब यूपी सरकार पर हमला नहीं बोलते हों, वह सीमए अखिलेश को विफल सीएम की उपमा दे रहे हैं.

हालात की गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि राजनीति के सबसे चतुर खिलाड़ियों में गिने जाने वाले सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव तक चारों खाने चित दिखाई दे रहें हैं. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के दौरान कुछ मुस्लिमों संगठनों और मुसलमानों की नाराजगी और सीएम को काला झंडा दिखाए जाने की घटना ने सपा को सकते में डाल दिया है. मुलायम की लाचारी का आलम यह है कि वह दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने तक का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं. एक बार प्रोग्राम बना भी था तो विरोध की आशंका के चलते अंतिम समय में रद कर दिया गया. सपा का कोई बड़ा नेता दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है. मुलायम के साथ परेशानी यह है कि आजम खान को लेकर दौरा करेंगे तो गैर मुस्लिम नाराज हो जाएंगे और उनके बिना दौरा करेंगे तो मुसलमानों के बीच यह मैसेज जाएगा कि आजम साहब दंगों से नाराज चल रहे हैं. इन सब बातों के बीच बताते चलें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह इलाका मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह का राजनीतिक क्षेत्र रहा है.

हालांकि चौधरी चरण सिंह ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, जिससे लगे कि मुलायम को वह अपना चेला नहीं मानते थे. अनेक मौकों पर दोनों अलग-अलग खड़े दिखाई पड़ जाते थे. चरण सिंह ने जाटों और मुसलमानों को एक ही घाट पर रहना सिखाया था और इसी के बल पर वर्षों तक यहां एकछत्र राज किया था. चरण सिंह की विरासत संभालने वाले उनके पुत्र अजित सिंह भी इसी फार्मूले के बल पर रोटिंया सेंकते रहें हैं. मुलायम अपनी पार्टी के जाट नेताओं की नाराजगी से भी परिचित हैं. कई ने पाला बदल दिया है तो कुछ और के बदलने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक मुसलमानों से भी बढ़ा है, इसीलिए मुलायम दोनों (जाट और मुसलमानों) को नाराज नहीं करना चाहते हैं. मामला थोड़ा ठंडा होने के बाद ही मुलायम का वेस्ट यूपी दौरा संभव लग रहा है. तब तक उनकी सरकार

(शेष पृष्ठ 18 पर)

अजित सिंह की सियासत पर ग्रहण

संजय सक्सेना

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हिंसा से राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के वोट बैंक को करारा झटका लगा है. जाट-मुसलमानों का समीकरण बैठाकर पश्चिमी यूपी में न केवल भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने वर्षों तक अपना दबदबा कायम रखा था, बल्कि उनके पुत्र अजित सिंह भी इस गठजोड़ के सहारे अपनी राजनीतिक धरोहर बचाए हुए थे, लेकिन उनकी थोड़ी सी ढिलाई ने भाजपा को जीवनदान दे दिया. बुरे वक्त और दंगे के समय अजित सिंह जब कहीं नहीं दिखे तो दंगा प्रभावित इलाके की जाट बिरादरी को सम्मोहित करने के लिए भाजपा नेता रहनुमा बनकर सामने आ गए. उधर, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को समर्थन के बदले अजित सिंह को नागर विमानन मंत्री बनाकर लाल बत्ती जरूर दे रखी है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़त बनाने के लिए उसने रालोद की पीठ में छुरा भोंकने से परहेज नहीं किया. यही वजह थी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव राहुल गांधी जब दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए तो अपने साथ केंद्रीय मंत्री और रालोद नेता चौधरी अजित सिंह की बजाय केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह को लेकर गए. वैसे, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस नेतृत्व के दौरे से थोड़ा पहले अजित सिंह ने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने की कोशिश की जरूर थी, परंतु तब तक जानमाल का काफी नुकसान हो चुका था, दंगा उनके संसदीय क्षेत्र बागपत तक पहुंच गया था. इस समय समाजवादी सरकार ने उनके लिए नो इंट्री कर दी थी. अजित सिंह ही नहीं उनके सांसद पुत्र जयंत तक को दंगा प्रभावित जिलों मुजफ्फरनगर और बागपत में नहीं घुसने दिया गया. दंगों की राजनीति ने छोटे चौधरी की सियासत पर ग्रहण लगा दिया है.

अजित सिंह की गैर-मौजूदगी को भाजपा ने पूरी तरह से भुनाया. जब जाटों की पंचायत कवाल के निकट नंगला मंदौड़ स्थित चौधरी चरण सिंह इंटर कालेज में हुई तो भाजपा और विहिप के नेताओं ने मंच पर कब्जा जमा लिया. भाजपा विधायक हुकुम सिंह, संगीत सोम, सुरेश राणा, भारतेंदु सिंह आदि नेता खुलकर जाटों के समर्थन में आ गए. अखिलेश सरकार ने जब इन पर शिकंजा कसा तो भाजपा की पौ बारह हो गई. उसके कई नेता अखिलेश सरकार पर जानबूझ कर दंगा नियंत्रित नहीं करने का आरोप लगाते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए कूच करने लगे. कलराज मिश्र, रविशंकर प्रसाद, उमा भारती आदि तमाम भाजपा नेताओं को दंगा प्रभावित इलाकों में जाने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी राजनैतिक महत्वाकांक्षा जरूर पूरी हो गई. विधानसभा सत्र में भी भाजपा ने इस मुद्दे पर बढ़त बना ली. आगे भी उसका यह प्रयास जारी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है.

बहरहाल, बदले हालात में अजित अपनी खोई हुई जमीन कैसे तलाशेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है. ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के रवैये से आहत अजित सिंह कोई बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन यह बातें खोखली निकलीं. उम्मीद थी कि अजित सिंह केंद्रीय नेतृत्व से मांग करेंगे कि यूपी की अखिलेश सरकार को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इसी को आधार बनाकर वह कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे. इससे उनको

(शेष पृष्ठ 18 पर)

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

दस्तावेजों में गुमनामी बाबा को कहा जा रहा नेताजी

राकेश कुमार यादव

फैजाबाद में लंबे समय तक रहे गुमनामी बाबा नेताजी सुभाषचंद्र बोस ही थे, इसे लेकर को लेकर मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार ने जहां दफ्न कर दी है, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस बाबत हाईकोर्ट के आदेशों पर मौन साधे हुए है. पहली बार जहां इस प्रकरण को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहस-मुबाहिसा शुरू कराया है, वहीं सूबाई सरकार के खतो-किताबत में भी गुमनामी बाबा को नेताजी सुभाषचंद्र बोस दर्शाया जाना शुरू हो गया है. वैसे हाईकोर्ट के आदेश की अवधि बीत चुकी है और इस संबंध में प्रदेश सरकार का रवैया टाल-मटोल का बना हुआ है. माना जा रहा है कि केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के दबाव में प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है. नतीजा कुछ भी निकले, परंतु अब सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर खुलकर कहा जाने लगा है कि फैजाबाद में अन्तिम सांस लेने वाले गुमनामी बाबा ही राष्ट्र नायक नेताजी सुभाषचंद्र बोस थे.

सरयू तट स्थित गुप्तारघाट पर गुमनामी बाबा की पुख्ता समाधि निर्मित करा दी गई है. हर साल 16 सितंबर को नेताजी सुभाषचंद्र बोस के अनुयायी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करने आते हैं. इस बार भी 16 सितंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की मौजूदगी में पुण्यतिथि मनाई गई. पुण्यतिथि की अगुवाई नेशनलिस्ट थिंकर्स क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वरदत्त शर्मा ने की. राम भवन में उनकी प्रेस वार्ता का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद षर्मा द्वारा कराया गया जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय विभाग प्रचारक रामचंद्र, भाजपा जिलाध्यक्ष रामकृष्ण तिवारी सहित कई लोग मौजूद रहे. वार्ता के दौरान नेशनलिस्ट थिंकर्स क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ईश्वरदत्त शर्मा ने चौंकाने वाले खुलासे किए. शर्मा ने कहा कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाषचंद्र बोस थे. नेताजी की गुमनाम जिंदगी पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी की देन है. 15 अगस्त, 1947 को तथाकथित आजादी नहीं मिली, केवल ट्रांसफर ऑफ पॉवर पैक्ट हुआ था. निजाम नहीं बदला, केवल सत्ता में गोरे के स्थान पर काले लोग बैठ गए. 18 अगस्त, 1945 को विमान दुर्घटना में नेताजी शहीद हो गए, ऐसा सरकार कहती है. उस समय नेताजी जापान में थे. माउंटबेटन ने जापान में उनकी हत्या का षडयंत्र रचा था, जिसकी भनक लगने पर नेताजी भूमिगत हो गए थे और 22 अगस्त, 1945 को बीबीसी रेडियो पर खबर आई थी कि विमान दुर्घटना में नेताजी मारे गए. रूसी राष्ट्रपति स्टालिन से नेताजी के अच्छे संबंध थे. नेताजी ने उनसे वार्ता की और

गुप्तरूप से रूस चले गए. इससे ब्रिटेन और अमेरिका दिग्भ्रमित हो गए. नेताजी 1955 तक रूस में रहे. शर्मा का कहना है कि 15 अगस्त, 1947 को जब देश आजाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को रूस में रह रहे नेताजी ने गुप्त पत्र भेजा था और भारत आने की मंशा जाहिर की थी. परंतु नेहरू ने गद्दारी करते हुए ब्रिटिश हुकूमत को अवगत करा दिया था कि रूस जिसे वह मित्र देश समझता है, उसी ने नेताजी को शरण दे रखी है. ब्रिटिश हुकूमत ने स्टालिन पर दबाव बनाया और कहा कि नेताजी को खत्म कर दो, जिसपर स्टालिन ने जबाब दिया था कि उन्हें खत्म कर दिया गया है. नेताजी 1955 में चीन के रास्ते तिब्बत होते हुए भारत पहुंचे और 30 साल विभिन्न स्थानों पर गुमनामी की जिंदगी बिताई और अंततः फैजाबाद के रामभवन में 16 सितंबर, 1985 को अंतिम सांस ली. शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उप्र सरकार को आदेश दिया था कि फैजाबाद के गुमानामी बाबा/नेताजी की जांच 90 दिन के भीतर कराकर रिर्पोट हाईकोर्ट को दें, परंतु साढ़े सात माह बीत चुका है. कोर्ट के आदेश का पालन अखिलेश सरकार ने नहीं किया, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सपा मुखिया घिरे हुए हैं, इसलिए सीबीआई से बचने के लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार से समझौते के तहत नेताजी के प्रकरण पर हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं.

गौरतलब है कि ललिता बोस आदि की याचिका पर उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने 31 जनवरी, 2013 के निर्णय में प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी. न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह और न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार दीक्षित की डबल बेंच ने अपने निर्णय में कहा था कि पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश से फैजाबाद के डीएम ने गुमनामी बाबा के कमरे में मिली वस्तुओं की सूची बनाई थी और उन्हें कोषागार में रखने को कहा था. मुखर्जी आयोग ने जांच के दौरान इन सामाग्रियों मे से कुछ को प्राप्त किया था. गुमनामी बाबा के कमरे से प्राप्त वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं और सरकारी सम्पत्ति हैं. पीठ ने केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि वह तीन माह के भीतर आयोग से उसके द्वारा हस्तगत अभिलेखों को प्राप्त कर फैजाबाद के डीएम को मुहैया कराए और डीएम इन चीजों को संग्रहालय में संरक्षित करें. इसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में गृह अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन ने वर्तमान जिलाधिकारी विपिन कुमार द्विवेदी को आदेश दिया कि गुमनामी बाबा के सामान का दस्तावेज रखने के लिए निमार्णाधीन राम कथा संग्रहालय का चयन किया है. प्रदेश सरकार ने गुमनामी बाबा को नेताजी सुभाषचंद्र मान भी लिया है. 17 मई को शासन स्तर पर गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही और शासन व जिला प्रशासन के पत्राचार में यह बात सामने आई है. खतो-किताबत में गुमनामी बाबा को नेताजी सुभाषचंद्र बोस के तौर पर उल्लिखित किया गया है. गुमनामी बाबा ने फैजाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित रामभवन में 16 सितंबर, 1985 में अंतिम सांस ली थी. कहा जाता है कि फौज व प्रशासन के आलाधिकारियों की मौजूदगी में गुपचुप ढंग से गुमनामी बाबा के पार्थिव शरीर को गुप्तारघाट ले जाकर कंपनी गार्डेन के समीप मुखाग्नि दे दी गई थी. गुमनामी बाबा के चेहरे पर तेजाब डाले जाने को लेकर उनके स्थानीय शिष्यों में विवाद इस कदर उग्र हुआ था कि कुछ शिष्यों ने इस हाईप्रोफाइल मामले को मीडिया के सामने लीक कर दिया था. नतीजतन देहांत के 21 दिन बाद एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र ने संबंधित समाचार को सुर्खियां देते हुए प्रकाशित किया. इसके बाद फैजाबाद समेत पूरे देश में भूचाल-सा आ गया. हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन को गुमनामी बाबा के कमरे से मिले सामानों और दस्तावेजों की फर्द बनानी पड़ी और राजकीय कोषागार में इसे रखा गया. सरकार ने जब मुखर्जी आयोग गठित कर नेताजी सुभाषचंद्र बोस को लेकर एकबार फिर जांच शुरू करवाई तो कोषागार के 28 बंद बक्सों के ताले खोले गए और तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज मुखर्जी आयोग ने हस्तगत कर लिया. आयोग द्वारा हस्तगत किए गए दस्तावेज वर्तमान समय में कहां है और किस दशा में हैं, यह न तो आयोग बता पा रहा है और न ही सरकार ही कोई जानकारी दे पा रही है. हाईकोर्ट के पुनः आदेश से प्रदेश की सरकार पसोपेश में है और किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पा रही है. मुखर्जी आयोग द्वारा फैजाबाद कोषागार में रखे गुमनामी बाबा के महत्वपूर्ण सामान, जो वह कोलकाता स्थित आयोग कार्यालय ले जाए गए थे, उनको भी निर्माणाधीन राम कथा संग्राहालय में रखा जाना है. आयोग का दफ्तर बंद हो चुका है और वहां संबंधित सामान नहीं रखे हैं. ऐसे में शंका व्यक्त की जा रही है कि साजिश के तहत केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नष्ट करा दिया है या उन्हें किसी गोपनीय स्थान पर रखवा दिया है. उच्च न्यायालय लखनऊ डबल बेंच ने 31 जनवरी, 2013 के फैसले में यह भी कहा था कि 1945 में एक प्लेन क्रैश की दुर्घटना में मारे गए नेताजी की मृत्यु के संदर्भ में विभिन्न इतिहासकारों और पत्रकारों की खोजबीन के इतिहास को खंगालने के बाद निष्कर्ष निकला है कि प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु हुई या नहीं, इस बारे में निश्चित राय कायम नहीं की जा सकती, पर यह तथ्य निर्विवाद और सर्वविदित है कि नेताजी स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे सेनानी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सभी के दिल में आजादी का जज्बा भर दिया था. ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की यादें या उसकी धरोहर आने वाली नस्लों के लिए प्रेरणादायक हैं. यदि फैजाबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा, जिनके बारे में लोगों का विश्वास था कि वे नेताजी सुभाषचंद्र बोस हैं और उनके पास आने जाने वाले लोगों तथा उनके कमरे में मिली तमाम वस्तुओं से इस बात का तनिक भी आभास होता है कि लोग गुमनामी बाबा को नेताजी के रूप में मानते थे तो ऐसे व्यक्ति की धरोहर को राष्ट्र की धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जाना चाहिए. फिलहाल नेताजी गुमनामी से उबरेंगे या नहीं, यह अभी भी भविष्य के गर्भ में है. ■

कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन में शीघ्रता बरती जाए

शासन का रुख सच्चाई के अनुरूप है, लेकिन उसे कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन में शीघ्रता बरतनी चाहिए, ताकि उन दस्तावेजों और सामाग्री को सुरक्षित और सार्वजनिक किया जा सके जो गुमनामी बाबा के आवास से मिले थे.

-शक्ति सिंह, अध्यक्ष (नेताजी सुभाषचंद्र बोस राष्ट्रीय विचार केंद्र)

गुमनामी बाबा से जुड़े स्थल राष्ट्रीय स्मारक घोषित हों

नेताजी से संबंधित केंद्र सरकार के अधीन समस्त 111 गुप्त फाइलों को सार्वजनिक किया जाए और फैजाबाद का नाम बदलकर नेताजी के नाम पर रखा जाए. सिविल लाइंस स्थित रामभवन व गुप्तारघाट स्थित समाधि स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए तथा फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी के नाम पर रखा जाना चाहिए. केंद्र सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे लोगों को सच्चाई का पता चल सके.

-ईश्वरदत्त शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनलिस्ट थिंकर्स क्लब ऑफ इंडिया

feedback@chauthiduniya.com

बसपा राज में हुए थे ज्यादा दंगे : अखिलेश

उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने अपराध के संबंध में चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं. आंकड़े बोलते हैं कि एक अप्रैल, 2012 से 31 अगस्त, 2013 तक यानी 17 महीनों में प्रदेश में हत्या की 6778, डकैती की 293, बलात्कार की 3167, लूटपाट की 4049 तथा अगजनी की 148 वारदातें हुईं. कांग्रेस के नेता नसीब पठान के सवाल का जबाव देते हुए सरकार ने विधान परिषद में लिखित रूप से यह भी कहा कि विगत वर्ष की अपेक्षा इस बार हत्या में 2.57 फीसद, डकैती में 18.38 फीसद व लूटपाट में 4.57 प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन बलात्कार की घटनाओं में 15.80 और आगजनी में 13.85 प्रतिशत वृद्धि हुई है. दंगों को लेकर समाजवादी पार्टी की छवि बेहद खराब हुई है. दंगों का आंकड़ा शतक बना चुका है, लेकिन सरकार यह मानने को तैयार नहीं है. विधानसभा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गृह विभाग के आंकड़ों के हवाले से जब यह बताया कि बसपा के राज में ज्यादा दंगे हुए थे तो कांग्रेस और भाजपा के चेहरों पर कुटिल मुस्कान देखने को मिली तो बसपा की त्योरियां चढ़ गईं थीं. हालांकि, केंद्र ने मुजफ्फनगर दंगों के बाद रिपोर्ट जारी की थी कि अखिलेश सरकार के एक साल के कार्यकाल के दौरान राज्य में 104 दंगे हुए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

दंगा शांत, राजनीति जारी

पृष्ठ 17 का शेष

दोनों की कौमों को मरहम लगाने का काम करती रहेगी.

बहरहाल, बात कैराना से बसपा सांसद तबस्सुम हसन की कि जाए जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए दंगों के बाद रहनुमाई कर रही हैं, वह एक तीर से दो निशाने लगा रही हैं. अपने संसदीय क्षेत्र में भाजपा की कमर तोड़ना और मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बनाना उनका परम धर्म बन गया है. यहीं से भाजपा के बड़े जाट नेता हुकुम सिंह आते हैं. हाल फिलहाल तक हुकुम सिंह और तबस्सुम के बीच अच्छी बनती थी, विधायक का चुनाव हुकुम सिंह लड़ते तो तबस्सुम उनकी मदद करती और सांसदी में हुकुम सिंह की मदद उन्हें मिलती, लेकिन बदले हालात ने रिश्तों पर ग्रहण लगा दिया. तबस्सुम की मुलाकात विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से हुई थी. सीएम जब दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने गए थे, तब भी तबस्सुम ने उनपर काफी मेहरबानी की थी. दौरे के दौरान भी उन्होंने बसपा सांसद से मुलाकात की थी. तबस्सुम कहती भी हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री को सच्चाई बताई थी. सांसद तबस्सुम का सारा ध्यान 2014 पर लगा है, वह यहां अपना वोट बैंक किसी भी तरह से बढ़ाना चाहती हैं, इसीलिए सभी तरह के हथकंडे अपना रही हैं. बसपा सुप्रीमो नाराज भी हो जाएंगी तो उनकी सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा. बसपा आलाकमान को इस बात का पता चलते ही महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सफाई देते हुए कहा कि उनके पास सांसद तबस्सुम के मुख्यमंत्री से मिलने के बारे में कोई जानकारी नहीं है. पार्टी के अन्य नेताओं को भी कुछ नहीं पता है. मीडिया से इस बात का पता चला है, पूरे मामले की जांच की जाएगी. ■

अजित सिंह की सियासत पर ग्रहण

पृष्ठ 17 का शेष

थोड़ी-बहुत जनता की सहानुभूति मिल जाती, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ. उन्होंने जनसंघर्ष की बजाय सत्ता का रास्ता चुना, जिसके लिए उनके ऊपर पहले भी कई बार उंगली उठती रही हैं. बात अजित सिंह के राजनीतिक चरित्र करें तो पिछले एक दशक में चुनावी गठबंधन के मामले में उनका रिकार्ड मजेदार रहा है. 2002 के विधानसभा चुनाव में उनका गठबंधन भाजपा के साथ हुआ था, लेकिन दो वर्षों बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में उनकी दोस्ती समाजवादी पार्टी के साथ हो गई. इनके साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा. इसके बाद आया 2007 का विधानसभा चुनाव, जो कि वह अकेले ही लड़े, लेकिन कोई पराक्रम नहीं कर पाए. 2009 के लोकसभा चुनाव में उनका गठबंधन एक बार फिर भाजपा के साथ हुआ, परंतु फिर उनका कांग्रेस के प्रति मोह बढ़ गया. वह मंत्री बने और 2012 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस से मिलकर लड़े. इससे नाराज होकर रालोद नेता अनुराधा चौधरी ने सपा का दामन थाम लिया था. 2014 में हालात क्या होंगे, कोई नहीं जानता. कांग्रेस से उनके रिश्ते वैसे ही खराब हो गए हैं. उनके दो सांसद देवेंद्र नागपाल (अमरोहा) और सारिका बघेल (हाथरस) पहले ही उनका साथ छोड़ चुके हैं.

तमाम किंतु-परंतु के बीच अजित सिंह ने 13 सितंबर को मुलायम पर हमला बोलते हुए कहा कि वह उत्तर प्रदेश के नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं, वहां भी दंगों को नियंत्रित करने में सरकार ने जान-बूझ कर देरी की थी और यहां भी ऐसा ही हुआ. अजित चुप थे तो भी नुकसान उठा रहे थे और जब बोले तो भी जाट नेताओं को उनका बयान अच्छा नहीं लगा. जाटों के बीच उनके बयान का निहितार्थ यह निकाला गया कि वह मुसलमानों को रिझाने में लगे हैं. इधर, मुलायम ने भी अजित सिंह को करारा जबाव देते हुए घोषणा कर दी कि उत्तर प्रदेश में गुजरात जैसी स्थिति नहीं पैदा होने दी जाएगी. गुजरात में पीड़ितों के साथ न्याय नहीं हुआ था. ■

feedback@chauthiduniya.com

लखनऊ के हाईप्रोफाइल ठग

दर्शन शर्मा

उत्तर प्रदेश के दफ्तरों में ठगी का धंधा करने वाले छुटभैये ठग जहां भोले-भाले लोगों को ठगकर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय, दारुलशफा के इर्द-गिर्द डेरा जमाए हाई प्रोफाइल ठग बड़े-बड़े अफसरों, व्यापारियों को झांसा देकर इनसे लाखों रुपये ऐंठने में सफल हो रहे हैं. ये ठग अपना अड्डा विधानसभा के आसपास स्थित सचिवालय, एनेक्सी, जवाहर भवन, बापूभवन, शक्तिभवन, इंदिराभवन आदि सरकारी इमारतों के आसपास ही बनाते हैं. जहां बैठकर वे कभी सचिव, प्रमुख सचिव, डायरेक्टर, निजी सचिव बनकर लोगों को फर्जी कॉल के सहारे अपने जाल में फंसा लेते हैं. रुतबा इतना कि नीलीबत्ती एम्बेसडर से चलते हैं. इसी तरह के एक हाई प्रोफाइल ठगों के एक गिरोह का पर्दाफाश तब हुआ, जब ठगी का शिकार हुए सआदतगंज, लखनऊ के एक टेंट व्यापारी नंदप्रकाश मिश्र ने हजरतगंज कोतवाली में ठगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई. जिसके आधार पर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इन शातिर ठगों एसएस साहिल, जमीरुद्दीन उर्फ बाबू, जफरुद्दीन उर्फ जफर, प्रदीप शुक्ल, मोहम्मद उमर उर्फ मर्फी, अली जाफरी व 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के हेड कांस्टेबल दूधनाथ तथा लखीमपुर खीरी की चंदन पुलिस चौकी के सिपाही रामसजन सरोज को गिरफ्तार कर लिया. इन जालसाजों के पास से पुलिस ने एक एम्बेसडर, दो टाटा सफारी व फोर्ड फिगो सहित छह लाख 43 हजार रुपये सहित सरकारी गाड़ियों की नंबर प्लेंटें भी बरामद कीं. गाड़ियों पर विधानभवन एनेक्सी में जाने का ए श्रेणी का पास लगा था. इन गाड़ियों में एक नीली बत्ती लगी एम्बेसडर भी थी, जिस पर सरकारी नंबर यूपी 32,बीजी 1038 अंकित था.

पुलिस के मुताबिक, हाई प्रोफाइल ठग एसएस साहिल स्लाटर हाउस की एनओसी दिलवाने जैसे बड़े काम की डील करता था. रुपया लेने के लिए वीवीआईपी गेस्ट हाइस और फाइव स्टार होटलों या अन्य स्थानों को चुनता था. स्पूफिंग कॉल के जरिये मुख्यमंत्री, कमिश्नर, डीएम व अन्य अधिकारियों के नंबर अपनी कॉल डिटेल में शामिल किए था, जिसके चलते वह खुद को मुख्यमंत्री का करीबी बताकर करोड़ों रुपये के वारे न्यारे कर चुका था. टेंट व्यापारी नंद प्रकाश मिश्र के साथ भी वहीं हुआ. एसएस साहिल उर्फ निस्सू ने व्यापारी की एक जमीन को भारमुक्त कराने के लिए राजेंद्र कुमार को फर्जी सचिव (न्याय) बताकर डेढ़ करोड़ में सौदा तय कराना चाहा, लेकिन बात न बन पाने पर पैंतरा बदलते हुए प्रमुख सचिव सदाकांत बनकर व्यापारी से पच्चीस लाख की मांग की. वायदे के मुताबिक, व्यापारी ने वीवीआईपी गेस्टहाउस निजी सुरक्षा अधिकारी को दस लाख रुपये सदानंद के पास भिजवाने के लिए दे दिए, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब 26 तारीख तक जमीन का काम नहीं हो पाया. शक होने पर नंद प्रकाश मिश्र ने साहिल के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिससे इस हाई प्रोफाइल गिरोह की ठगी का राज खुल गया.

पुलिस को पता चला कि स्पूफिंग कॉल के जरिये मुख्यमंत्री के निजी नंबर से साहिल आवाज बदल-बदल कर अधिकारियों के नाम से बात करता था. पुलिस के अनुसार, बड़े नेताओं के निजी नंबर से बात करने के बाद साहिल एक दो दिन में संबंधित कमिश्नर, पुलिस के डीजी व बड़े अधिकारियों से मिलने जाता था. पहले उनसे व्यवहार बनाता, फिर बाद में उन बड़े अधिकारियों से अपनी पत्रिका प्रयास व साहिल फाइंडेशन संस्था के लिए विज्ञापन या नकद रुपये ले लेता था. यही नहीं, साहिल बड़े नेताओं के अलावा कई अधिकारियों के नंबरों को पता करके खुद अधिकारी बनकर भी स्पूफिंग काल के जरिये दूसरे लोगों से बात करता था. इसमें सबसे अहम बात यह रहती कि कोई भी अधीनस्थ अफसर पलटकर इस नंबर पर कॉल नहीं करता था, जिससे साहिल ने कॉल किया होता था. इसी छलदंभ के बल पर उसने बुलंदशहर के 65 मोर्चा स्ट्रीट पठान वाड़ा खुर्जा निवासी सिराज अहम से भी स्लाटर हाउस की जमीन दिलवाने के नाम पर एक करोड़ 60 लाख की डील की थी. इसके अलावा उसने दर्जन भर प्रशासनिक अधिकारियों को भी चूना लगाया है. चिंताजनक बात यह है कि इस ठगी में साथ देने वाले दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं.

बहरहाल ठगी के इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव एके सिंह को इस पूरे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी. वहीं प्रमुख सचिव आवास सदाकांत ने इस पूरे मामले पर आश्चर्य जताया है. उनका कहना है कि फ्रॉड करने वाले सभी लोगों के खिलाफ जांच करके कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

क्या है स्पूफिंग कॉल

स्पूफिंग कॉल इंटरनेट के माध्यम से की जाती है. यह कॉल (मोबाइल नंबर) से जिस व्यक्ति के मोबाइल पर की जाती है, उसको वही नंबर दिखता है, जो किसी तीसरे का नंबर होता है, जबकि बातचीत में यह पता लगता है कि फलां अधिकारी ने सीधे अपने मोबाइल से कॉल किया है. कॉल रिसीव करने वाले के मोबाइल पर मुख्यमंत्री या अधिकारी का नंबर ही डिस्प्ले करता है. इससे व्यक्ति को लगता है कि मुख्यमंत्री या अधिकारी ने कॉल की है, जबकि कॉल खुद साहिल स्पूफिंग कॉल के जरिये करता है. साइबर एक्सपर्ट के अनुसार, आजकल चोर व बदमाश स्पूफिंग कॉल का काफी प्रयोग कर रहे हैं. इस कॉल को वीओआईपी (वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल) भी कहते हैं.

इतिहास के पन्नों में अमर हुए समाजवादी मोहन सिंह

संजय सक्सेना

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद मोहन सिंह गत दिनों अपने गृह जनपद देवरिया में हजारों नम आंखों के बीच पंचतत्व में विलीन हो गए. मोहन सिंह समाजवादी पार्टी के उन चेहरों में से थे, जिन्होंने एक बार मुलायम सिंह यादव का हाथ पकड़ा तो ताउम्र उन्हीं के करीब रहे. प्रमुख समाजवादी चिंतक डॉ राम मनोहर लोहिया के अनुयायी मोहन सिंह ने कभी भी समाजवाद से समझौता नहीं किया. ऐसा नहीं था कि उनकी कभी मुलायम से नाराजगी नहीं हुई, लेकिन इसके लिए उन्होंने बगावत का रास्ता नहीं चुना. मोहन सिंह किसानों, पिछड़ों और नौजवानों के लिए जीवन पर्यन्त संघर्ष करते रहे. वह एक सच्चे समाजवादी, ईमानदार एवं निष्ठावान नेता थे. उनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन साफ-सुथरा था. वह डॉ राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए संघर्षरत रहे. मोहन सिंह दो बार देवरिया से लोकसभा सदस्य रहे, दो बार राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य रहे. वह 1977 में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे. श्री सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और उन्होंने छात्रों एवं नौजवानों के लिए संघर्ष किया. उन्होंने 1975-76 (आपातकाल) में जेल यातना भी सही. वह प्रारम्भ से ही समाजवादी युवजन सभा एवं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे.

मोहन सिंह की मौत दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुई थी. उनकी मौत की खबर सुनते ही सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित तमाम बड़े नेता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच गए. दिल्ली से मोहन सिंह का शव लखनऊ लाया गया. यहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो राम गोपाल यादव ने उनके पार्थिव शरीर पर समाजवादी पार्टी का झंडा एवं पुष्पचक्र अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी. उनकी शान में पार्टी का झंडा झुका दिया गया.

विदाई की इस बेला में विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय, राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान, उदय प्रताप सिंह, कुंवर रेवती रमण सिंह, भगवती सिंह, सहित मंत्रीगण अहमद हसन, पारसनाथ यादव, राजेन्द्र चौधरी, राज किशोर सिंह, शिव कुमार बेरिया, कैलाश यादव, सांसद सुशील सरोज, ऊषा वर्मा, प्रदेश सचिव एसआरएसयादव, राज्यमंत्री मनोज पाण्डेय, मनोज पारस, (राज्यमंत्री दर्जा) राज किशोर मिश्रा, राजा चतुर्वेदी, लीलावती कुशवाहा, महिला आयोग की अध्यक्ष जरीना उस्मानी, विद्यावती राजभर, विधायकगण सतीश निगम, आशा किशोर, शारदा प्रताप शुक्ला, चन्द्रा रावत, राजू यादव, रविदास मेहरोत्रा, उन्दल रावत, राम मगन रावत, डॉ मधु गुप्ता, उदयराज यादव, कुलदीप सिंह सेंगर, सुधीर रावत, गजाला लारी एवं सत्यदेव त्रिपाठी, श्रीनारायण शुक्ला, आनन्द भदौरिया, सुनील यादव मुजीबुर्रहमान बबलू, राजेश यादव, अतुल प्रधान, अल्पना बाजपेयी, विजय यादव, राम सागर यादव, मोहम्मद एबाद आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित की. ■

राम मनोहर लोहिया के अनुयायी मोहन सिंह ने कभी भी समाजवाद से समझौता नहीं किया. मोहन सिंह किसानों, पिछड़ों और नौजवानों के लिए जीवन पर्यन्त संघर्ष करते रहे. वह एक सच्चे समाजवादी, ईमानदार एवं निष्ठावान नेता थे.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया साप्ताहिक अखबार के सफलतम प्रकाशन पर हार्दिक बधाई

बब्बन सिंह 'रघुवंशी'
प्रबंधक, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज दलन छपरा बलिया

ददन सिंह, प्रधानाचार्य
महात्मा गांधी इंटर कॉलेज दलन छपरा बलिया

चौथी दुनिया साप्ताहिक अखबार के सफलतम प्रकाशन पर हार्दिक शुभकानाएं

- डी.पी. यादव
  राष्ट्रीय महासचिव, हस्तक्षेप (मानवाधिकार जननिगरानी समिति)
- जे.पी. सिंह, राष्ट्रीय सचिव, हस्तक्षेप (मानवाधिकार जननिगरानी समिति)
- मूरत राम
  राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैंपेन फॉर मनरेगा
- डॉ राजेश कुमार यादव
  प्रभारी, आरटीआई टास्कफोर्स उत्तर प्रदेश
- डॉ शैलजा राय
  अध्यक्ष, डोमेस्टिक वायोलेंस एक्शन ग्रुप (डग) उ.प्र.
- संगीता जायसवाल
  महासचिव, डोमेस्टिक वायोलेंस एक्शन ग्रुप (डग) उ.प्र.
- सरोज पांडेय
  राष्ट्रीय महासचिव, डोमेस्टिक वायोलेंस एक्शन ग्रुप (डग)
- ओमकार नाथ मेहता, एडवोकेट
- हंसराज तिवारी एडवोकेट
  कानूनी सलाहकार हस्तक्षेप (मानवाधिकार जन निगरानी समिति)

संस्था का सदस्य बनने अथवा संस्था के विषय में जानकारी के लिए संपर्क करें
Email : awsar3334@gmail.com
अथवा कॉल करें 09455209120, 09453517597,07668952813

अजय कुमार , लखनऊ ब्यूरो प्रमुख कार्यालय का पता : जे-3/2 डॉलीबाग़, हजरतगंज, लखनऊ-226001, फोन -(0522) 2204678/09415005111

मातृसदन में सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने अवैध खनन और गंगा की अविरलता पर पक्ष व विपक्ष दोनों को ही अगंभीर बताया. कहा कि राज्य-केंद्र की सरकारें तो इस पर ध्यान दे ही नहीं रहीं हैं, साथ ही राज्य के विपक्ष की भी इस पर कोई चिंता नहीं है. शिवानन्द ने निगमानन्द की मौत के लिए इशारे से भाजपा को कटघरे में खड़ा किया.

विवादों से पूर्व सैनिकों में रोष

सेना का राजनीतिकरण अनुचित

रेनू शर्मा

सेना की खुफिया जानकारियों के सार्वजनिक होने और इस पर राजनीतिक दलों की बयानबाजी को लेकर पूर्व सैन्य अधिकारी खासे आहत हैं. उनका कहना है कि यूपीए सरकार अब सेना का भी राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है. इससे न केवल देश की सुरक्षा का खतरा बढ़ रहा है, बल्कि सैनिकों का भी मनोबल गिर रहा है. सैन्य अधिकारियों ने चेताया है कि यदि केंद्र इसी प्रकार सेना की खुफिया जानकारियों को सार्वजनिक कर सेना को निशाने पर लेती रही तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं. रिटायर्ड जनरल वीके सिंह के कार्यकाल में गठित टीएसडी यानी टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन की कार्यप्रणाली की जांच को लेकर गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पूरे देश में हलचल है. माना जा रहा है कि सरकार इस मसले पर सीबीआई जांच के भी आदेश दे सकती है. इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे पूर्व सैन्य अधिकारी इसे एक घटिया राजनीति से अधिक कुछ नहीं मानते. पूर्व अधिकारियों का कहना है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है. सेना के भीतर चल रही खुफिया गतिविधियों की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना देश की सुरक्षा के हित में नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि जो रिपोर्ट केंद्र को तकरीबन छह माह पूर्व सौंप दी गई थी, वह अचानक रिटायर्ड जनरल वीके सिंह के नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने के बाद ही क्यों सार्वजनिक हुई? अधिकारियों का कहना है कि रिटायर्ड जनरल वीके सिंह और वर्तमान जनरल बिक्रम सिंह के बीच तनातनी को सार्वजनिक मंच पर लाकर सरकार सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रही है.

■ क्या कोई मान सकता है कि एक करोड़ रुपये देकर किसी राज्य की सरकार गिराई जा सकती है. अब टॉप सीक्रेट यूनिट को भी सार्वजनिक किया जा रहा है. यह घटनाक्रम सेना व देशहित में नहीं है.

-ले. जनरल (रिटा.) ओपी कौशिक

■ राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित बातों को इस तरह सार्वजनिक किया जाना ठीक नहीं. छह महीने पहले जो जांच हो गई थी, अचानक ही एक रैली के बाद इसकी रिपोर्ट लीक कैसे हो गई? पुराने चीफ व वर्तमान चीफ के बीच में जो चल रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है. सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है. नेता खतरनाक खेल खेल रहे हैं. इसका अंजाम आने वाले समय में भुगतना होगा.

-ले.जनरल (रिटा.) एमसी भंडारी

■ इस गलत परंपरा की शुरुआत की जा रही है. केंद्र सरकार रिटायर जनरल पर गलत तरीके से दबाव डाल रही है. इसके लिए वह वर्तमान जनरल की मदद ले रही है. इस तरह की गोपनीय बातों का सार्वजनिक किया जाना गलत है. खुफिया विभाग देश हित में गोपनीय कार्य करता है. इसे सबके बीच में नहीं लाया जाना चाहिए.

-ले.जनरल (रिटा.) जीएस नेगी

■ संवेदनशील जानकारियों को सार्वजनिक किया जाना गलत है. यह राष्ट्रीय हित में नहीं है. जिस तरह से यह घटनाक्रम सामने लाया गया, इससे लगता है कि यह राजनीति से प्रेरित है. यदि कहीं कुछ है तो इसकी जांच कराओ, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं होना चाहिए. इसके लिए राजनेताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए.

-ले.जनरल (रिटा.) केके खन्ना

पीस पार्टी में विद्रोह

संदीप कश्यप

पीस पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष डाक्टर अयूब खान को इनके संगी-साथियों के बीच आजकल शह-मात का खेल चल रहा है. कभी उनके विरोधियों का पलड़ा भारी लगता है तो कभी अयूब का. पीस पार्टी के चार में से तीन विधायकों और उनके हजारों समर्थकों ने अपने ही विधायक अयूब की कार्यशैली से नाराज होकर उन्हें उनकी ही पार्टी के विधानमंडल दल के नेता पद से हटा दिया था. रायबरेली के दबंग विधायक अखिलेश कुमार सिंह को नये धड़े (विधायक मलिक कमाल यूसुफ, अखिलेश सिंह और अनीसुर्रहमान) ने पीस पार्टी विधानमंडल दल का नया नेता भी चुना लिया. पार्टी के चार में से तीन विधायकों ने पाला बदलने से दलबदल कानून भी इन विधायकों के खिलाफ नहीं लागू हो सका, लेकिन अयूब ने भी हार नहीं मानी. बागी हुए विधायकों का आरोप था कि डॉ. अयूब ने सांप्रदायिक शक्तियों से सांठगांठ कर ली थी, वह कभी भी विधान सभा की कार्यवाही में सक्रिय नहीं दिखते थे. इसलिए विधायकों को अपना नेता बदलना पड़ा. तीन विधायकों के पाला बदलने के कारण डॉ. अयूब को विधानसभा में उस समय काफी फजीहत झेलनी पड़ी, जब वह मुजफ्फरनगर दंगों के संदर्भ में बोलने के लिए खड़े हुए. विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद ने उन्हें यह कहते हुए नहीं बोलने दिया कि फिलहाल इस प्रकरण पर केवल दलीय नेताओं को बोलने की छूट दी गई है और अब वह पीस पार्टी के विधानमंडल दल के नेता नहीं हैं. अयूब को अपनी पार्टी में विद्रोह का पता तब चल पाया, जब उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया. अयूब ने उनकी पार्टी में विभाजन के लिए सपा को दोषी ठहराया. अपनों से ही मुंह की खाए विधायकों और उनके समर्थकों को अपनी ताकत दिखाने के लिए अयूब ने आनन-फानन में मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के नाम पर एक आंदोलन की घोषणा कर दी. धरने-प्रदर्शन का यह बड़ा आंदोलन विधान भवन के बाहर हुआ. अयूब अपने समर्थकों संग तब तक विधानभवन के बाहर डटे रहे जब तक पुलिस ने लाठियां भांज कर उन्हें खदेड़ा नहीं. हाथों में पीस पार्टी का झंडा थामे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दंगा पीड़ित मुसलमानों को राहत और अखिलेश सरकार की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े थे. अयूब अपनी ताकत दिखाने में सफल रहे. पीस पार्टी के नेता अयूब के लिए अपनी पार्टी को बचाए रखना हमेशा ही मुश्किल रहा है. 2012 में भी पार्टी के विघटन के हालात बने थे, लेकिन तब अयूब ने मौका रहते स्थित संभाल ली थी, परंतु अबकी बार वे मात खा गए. ■

शिव भी शक्ति के उपासक हैं

आर के शर्मा

विंध्य क्षेत्र में स्थित आदिशक्ति जगदम्बा विन्ध्यवासिनी एंव उनके विन्ध्यधाम की महिमा अपार है. नवरात्रि के अवसर पर इस धाम का विशेष महत्व है. अनादिकाल से सम्पूर्ण विश्व में किसी न किसी रूप में इस महाशक्ति की उपासना का प्रचलन रहा है. विश्व का कण-कण शक्ति की कामना को लेकर इस शक्ति की देवी की उपासना में रत रहता है. वेदों में भी सभी देवताओं ने इस महाशक्ति की उपासना की है. भगवान शिव उनकी महत्ता को स्वीकारते हुए कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव भी शव है. भगवान विष्णु ने उनकी महत्ता को स्वीकारते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति भी शक्ति के बिना जगत की रक्षा का सामर्थ्य नहीं रखते, इसी प्रकार मैं भी शक्ति सम्पन्न रहने पर ही इस सृष्टि की रक्षा और पालन करने में समर्थ रहता हूं. शक्ति की महत्ता को स्वीकारते हुए सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मिट्टी के बिना कुम्हार जैसे घड़ा नहीं बना सकता, सोने के बिना स्वर्णकार आभूषण नहीं बना सकता, वैसे ही शक्ति की कृपा के बिना मैं सृष्टि की रचना करने में अपने को असमर्थ पाता हूं. इस शक्ति की मूलाधार मां जगदम्बा की उपासना के लिए वैसे तो कोई देश काल का बन्धन नहीं है, वर्ष में आराधकों के लिए दो ऐसे अवसर आते हैं जब वासंतिक नवरात्रि एंव शारदीय नवरात्रि के अवसर पर नव दिनों में मां की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है. इन दोनों काल को मां विन्ध्यवासिनी की अराधना का श्रेष्ठ समय माना गया है. मातृ शक्ति की पूजा का इतिहास अति प्राचीन है. इतिहासकारों का भी मानना है कि सामूहिक उपासना एवं मातृ देवियों की उपासना एक ही समय होती रही है. विन्ध्य देश के विन्ध्याटवी के गहन वनों में आग्नेय, शवर आदि जनजातियां वास करती रही हैं. ये जनजातियां एक कुमारी देवी की पूजा करती थीं. इसी कुमारी देवी के पूजा का प्रचलन हिमालय की तराई तक फैला. इसी देवी को कालान्तर में विध्यपर्वत पर निवास करने के कारण मां विन्ध्यवासिनी के नाम से पुकारा गया. प्रकृतिरूपा इस देवी का जन्म ही अति प्राचीन विन्ध्य पर्वत पर हुआ था. शतपथ ब्राह्मण एंव केनोपनिषद में वर्णित है कि कालान्तर में पर्वत पर निवास करने के कारण इन्हीं देवी को पार्वती के नाम से पुकारा गया. मां विन्ध्यवासिनी को आदिकाल से शक्ति की देवी के साथ उनके ममतामयी चरित्र और पौरुषेय गुणों को मान्यता मिलती रही है. इस शक्ति ने सदैव आततायियों का नाश कर सभ्य प्रजा की रक्षा का धर्म निभाकर अपने ममतामयी रूप का परिचय दिया. सभी पूज्य देवियों को विन्ध्यवासिनी/पार्वती/उमा का अंश स्वीकारा गया है. आदिकाल से इस सर्वशक्ति सम्पन्न कुमारी, सर्वशक्ति सम्पन्न देवी की विंध्यपर्वत पर की जाने वाली पूजा स्वयं में एक प्रमाण है. इसी देवी को योगमाया के नाम से जाना गया. उन्हें भगवान कृष्ण की भगिनी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है जो कंस के हाथ से छूट कर विन्ध्य पर्वत पर अष्टभुजा देवी के नाम से स्थित है, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी भी हैं. महाभारत के भीष्मपर्व हरिवंश देवी, भागवत मारकण्डेय पुराण, विष्णुपुराण में विन्ध्यवासिनी देवी का वर्णन आया है. देवी पुराण में इस देवी के लिए दुर्गा, उमा, शिवा, देवी, ब्रह्मणी, विन्ध्यासिनी, चामुण्डा, पराशक्ति, कात्यायिनी, कौशिकी, पार्वती, नारायणी, मीना, धूमा, अम्बिका, लक्ष्मी, चण्डी, कपालिनी, काली, कज्जला, महिषासुर मर्दिनी, नन्दा, भवनी, तारा, वैष्णवी, महालक्ष्मी, श्वेता, योगेश्वरी आदि नामों से पुकारा गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

निगमानंद की राह पर स्वामी सानंद

राजकुमार शर्मा

गंगा में खनन और जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर शासन-प्रशासन की हठधर्मिता के विरोध में स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद (प्रो. जीडी अग्रवाल) ने प्राण त्यागने का ऐलान किया है. धर्मनगरी हरिद्वार के मातृसदन में पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपने तप (अनशन) के 101वें दिन यानी 21 सितंबर से जल भी त्यागने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि गंगा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद संत निगमानन्द जी मेरे आदर्श हैं. मैं उनका अनुगमन करने को तैयार हूं.

स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद ने कहा कि अवैध खनन और जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक की मांग को लेकर वह 13 जून से तपकर रहे हैं. इसके बावजूद भी केंद्र व राज्य सरकार की संवेदनहीनता के चलते तप के 101 वें दिन यानि 21 सितंबर से जल त्याग कर कठोर तप शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि इस कठोर तप के बल पर वे या अपने उद्देश्य में सफल होंगे, या फिर प्राण त्याग देंगे. स्वामी सानंद ने इस कठोर तप को अनशन या आमरण अनशन कहने से इन्कार कर दिया. कहा कि आमरण अनशन जैसा कोई शब्द हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं है. वे सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं, इसलिए वे या मंत्र सिद्ध करूंगा या प्राण त्याग दूंगा के आधार पर ही अपनी तपस्या को जारी रखेंगे. उल्लेखनीय है कि संत सानंद को अनशन के दौरान बहुगुणा सरकार ने जेल में डाल दिया था. जब पूरा देश आजादी दिवस का जश्न मना रहा था, गंगा की रक्षा के लिए तक एक संत जेल की यातना झेल रहा था. सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर उन्हें जेल से मुक्ति मिली है. स्वामी सानंद ने सिल्ट की आड़ में हरिद्वार जिले की नदियों में हो रहे अवैध खनन पर भी चिंता जताते हुए कहा कि चारों ओर अवैध खनन हो रहा है. प्रशासन ठोस कार्रवाई करने से बच रहा है. प्रख्यात वैज्ञानिक संत सानंद स्वामी स्वरूपानन्द के शिष्य हैं. उन्होंने इस मसले पर अपने गुरु की चुप्पी पर हैरानी के बावजूद कुछ भी नहीं कहा. मातृसदन में पत्रकार-वार्ता में सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने अवैध खनन और गंगा की अविरलता पर पक्ष व विपक्ष दोनों को ही अगंभीर बताया. कहा कि राज्य-केंद्र की सरकारें तो इस पर ध्यान दे ही नहीं रहीं हैं, साथ ही राज्य के विपक्ष की भी इस पर कोई चिंता नहीं है. भाजपा को आड़े लेते हुए शिवानन्द ने निगमानन्द की मौत के लिए इशारे से भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अब भी विपक्ष को कम से कम इस विषय को मुद्दा बनाकर सरकार से जवाब मांगना चाहिए. अन्यथा भाजपा को हिन्दू, गंगा, संत का अलंबरदार होने की बात नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को केदारनाथ में पूजा की तो जल्दी रही, मिटने की कगार पर पहुंच चुकी अलकनंदा की चिंता नहीं हुई. धारी देवी की चिंता नहीं हुई. जल भी त्याग देने के बाद स्वामी सानंद की हालत बिगड़ने लगी है. उन्हें पुलिस ने मातृसदन से उठाकर पुलिस ने दून चिकित्सालय में भर्ती कराया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पूर्वोत्तर रेलवे संजो रहा है ऐतिहासिक धरोहर

आलोक कुमार सिंह

पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र पर्यटन एवं ऐतिहासिक विरासत की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है. पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर गुरु गोरखनाथ की समाधि एवं मंदिर, विश्व प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान गीताप्रेस, रामगढ़ ताल, एवं टेराकोटा की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है. इसी के पास मगहर में महान संत कबीर का मकबरा है तो दूसरी तरफ पडरौना एवं देवरिया रेलवे स्टेशन के निकट भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर मौजूद है, जहां के स्तूप एवं मॉनूमेन्टस विश्वप्रसिद्ध हैं. भगवान बुद्ध का जन्मस्थल लुंबिनी नौगढ़ रेलवे स्टेशन के पास स्थित है जो शाक्य वंश की राजधानी कपिलवस्तु जाने का भी निकटतम रेलवे स्टेशन है. पूर्वोत्तर रेलवे सेवित क्षेत्र में पूरा बुद्ध सर्किट तथा श्रावस्ती का सहेत-महेत, जहां अंगुलिमाल एवं सुदत्त का स्तूप है. बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने शिष्यों को दी जाने वाली शिक्षा के पहले स्थल के रूप में सारनाथ अत्यंत दर्शनीय है. तीन नदियों की संगम नगरी इलाहाबाद, कालीन नगर के रूप में प्रसिद्ध भदोही/मिर्जापुर एवं बनारसी साड़ियों, गंगा के घाटों पर मनाई जाने वाली विश्वप्रसिद्ध देवदीपावली के लिए प्रसिद्ध बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी, देवी मां दुर्गा के सिद्ध पीठ के रूप में देवीपाटन, भगवान ब्रह्मा के द्वारा विश्व रचना हेतु अश्वमेघ यज्ञ स्थल मार्कंडेय महादेव का मंदिर अत्यंत दर्शनीय है. स्वामी नारायण छपिया रेलवे स्टेशन के निकट छपिया गांव संत स्वामी नारायण की जन्मस्थली है. इनके अनुयायियों ने अक्षरधाम का मंदिर अहमदाबाद में उन्हीं के नाम पर बनवाया. देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु इनके जन्मस्थल को देखने आते हैं.

भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में विख्यात अयोध्या भी पूर्वोत्तर रेलवे के कटरा स्टेशन के समीप है. भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा, नंदग्राम एवं द्वारिकाधीश का मंदिर भी सेवित क्षेत्र पूर्वोत्तर रेलवे ही है. हर्षवर्धन एवं जयचंद की राजधानी एवं वर्तमान में इत्र उत्पादन में विश्वप्रसिद्ध कन्नौज, पूर्व में भारत के मानचेस्टर के रूप में प्रसिद्ध कानपुर, सैयद सालार मसूद की दरगाह के लिए सुविख्यात बहराइच, अवध के नवाबों की राजधानी लखनऊ एवं यहां की भूल-भुलैया, बड़ा इमामबाड़ा, जामा मस्जिद, नादान महल, रेजीडेन्सी अविस्मरणीय है. कुमाऊं की पहाड़ियों की सैर करने के लिए पर्यटकों को पूर्वोत्तर रेलवे के काठगोदाम, हल्द्वानी एवं रामनगर स्टेशन सेवा प्रदान करते हैं.

पर्वतीय पर्यटन स्थलों की रानी के रूप में विख्यात नैनीताल 11.73 किमी वर्ग क्षेत्र में फैली है, जो समुद्र तल से 6400 फीट की ऊंचाई पर है. नैना चोटी, हनुमानगढ़ी, भुवाली, भीमताल आदि स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं.

पर्वतमाला पर स्थित घोड़े की काठी के आकार में विस्तृत और अपने नैसर्गिक सौंदर्य के कारण आज भी प्रकृति के मासूम शिशु के रूप में प्रसिद्ध अल्मोड़ा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है. यहां मोहन जोशी पार्क, सिमटौला, कालीमठ, केदार देवी का मंदिर, हिरण उद्यान आदि स्थलों का आनंद लिया जा सकता है.

मनोरम प्राकृतिक छटा से संपन्न पर्वतीय स्थल रानीखेत सैलानियों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है. चौबतिया भालू डाम, द्वारघाट, दूनगिरी, सितला खेत आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं. कौशानी पर्वतीय स्थल से कुछ ऊंची पर्वत चोटियों की मनोरम छटा देखी जा सकती है. यह समुद्र तल से 1896 मीटर की ऊंचाई है. महात्मा गांधी ने वर्ष 1929 में यहां 12 दिन व्यतीत किए थे. हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली कौशानी उनकी रचनाओं की प्रेरक भूमि है. चंदक, घालकदार, खटमाउंट, चंपावत आदि दर्शनीय स्थल हैं.

विश्वप्रसिद्ध वन्य पशु अभ्यारण्य जिम कार्बेट नेशनल पार्क रामनगर से 32 किमी दूर स्थित है. इस पार्क का नामकरण सुप्रसिद्ध शिकारी, पशु प्रेमी द मेन ईटर्स ऑफ कुमाऊं के लेखक जिम कार्बेट के नाम पर हुआ. यह अभ्यारण्य 183 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है, जो पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केंद्र है. उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भारत-नेपाल बॉर्डर के समीप लखीमपुर खीरी जनपद में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, जहां पर जंतु तथा पशु-पक्षियों का बसेरा है. यह क्षेत्र 1958 में स्थापित किया गया तथा वर्ष 1987 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया. ■

(लेखक पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तराखण्ड के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन, प्रसार प्रतिनिधियों एवं एजेंसियों के लिए शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
arifali@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें: 0120-6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627366